ISSN-0971-8397

विकास को समर्पित मासिक

योजना

मई 2005

मूल्य : 7

विकास की एक प्रविधि है एसपीवी - मोंटेक सिंह अहलुवालिया का साक्षात्कार

ढांचागत सुविधाओं के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग

क्या है विशेष उद्देश्यीय व्यवस्था (एसपीवी)

बुनियादी ढांचे के लिए वित्त व्यवस्था

चामत्कारिक प्रगति का संसार : दूरसंचार

भारत और चीन में राजमार्ग और रेल विकास का तुलनात्मक मूल्यांकन

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु समूह उद्यमिता

फ्लाई ऐश - जैव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रबंधन

बुनियादी ढांचा

चल पड़ा कारवां अमन का

श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा आरंभ हुई

प्रधानमंत्री, डा. मनमोहन सिंह ने पिछले दिनों श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम से श्रीनगर-मुजफ्फराबाद यात्री बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, विदेश मंत्री नटवर सिंह, शहरी विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री गुलाम नबी आजाद, तेल एवं प्राकृतिक गैस एवं पंचायती राज मंत्री मणिशंकर अय्यर, जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल एस.के. सिन्हा, मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद उपस्थित थे।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री के भाषण का मूल पाठ इस प्रकार है:

"आज का दिन हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है। एक अमन का कारवां बना है, वह अब चल पड़ा है। आज मैं फख्र के साथ मुजफ्फराबाद शाहराह का इफ्तिताह कर रहा हूं। लेकिन आप पूछेंगे कि इस पर इतना फख्र क्यों ?यह फख्र इसलिए कि ये लाखों इंसानों के अरमानों का नतीजा है, हजारों की मेहनत का अंजाम। यह दिन वह दिन है, जिसे देखने का ख्वाब, बहुतों ने जरूर देखा था मगर अपनी जिन्दगी में वह दिन है, जिसकी असलियत में देखने की उम्मीद कम ही थी। आखिर आपकी दुआओं की सुनवाई हुई, यह रास्ता जो 1953 से बंद पड़ा है, आखिर खुल ही गया। इससे पुराने ताल्लुकात फिर से बहाल हो पाएंगे। बिछड़े खानदान फिर से एक हो सकेंगे। भाई-बहन जिन्होंने एक दूसरे से फिर से मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, हाथ में हाथ मिलाकर चल सकेंगे। जम्मू-कश्मीर के खूबसूरत पहाड़, ये सब्ज वादियां, हंसते-खेलते पानी के झरने फिर खुशियों से लहरायेंगे, गूंज उठेंगे, ये हमारी उम्मीद है।

हमारे लिए इस शाहराह का मुसाफिरों के लिए खुलना सिर्फ पहला कदम है। एक दरवाजा खुला है जिसकी अपनी अहमियत है। और इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारे साथ मिलकर इसे मुमकिन बनाया है। हुकूमते पाकिस्तान और खास तौर से उस मुल्क के सदर परवेज़ मुशर्रफ़ के इत्तिफाक के बगैर, जाहिर है कि ये दरवाजा कभी खुल न पाता। क्योंकि ये काम भारत और पाकिस्तान के साथ-साथ मिलकर चलने का नतीजा है, इसकी सबसे बड़ी अहमियत इसी में है कि दोनों हुकूमतों ने ये कर दिखाया कि हम अपने-अपने अवाम के जज्बात की कितनी कदर करते हैं। और, अगर हम सब मिलकर काम करें तो क्या नहीं कर सकते हैं। भारत की फौज के सिपाहियों ने रियासती सरकार और मक़ामी, मेहनती, मजदूरों के साथ मिलकर कम से कम वक्त में रास्ता तैयार कर लिया ताकि आज ये रस्मे इफ्तिताह का काम पूरा हो सके। यह काबिले तारीफ़ है।

मगर जैसा मैंने शुरू में कहा, यह एक लंबे रास्ते पर पहला ही कदम है। आगे के रास्ते को तय करने में काफी मुश्किलात बाकी हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हमारे दोनों देशों की सरकारों ने मिलकर हमारे अवाम की ख़ाहिशात की कद्र की, अगर ऐसा ही रवैया रहा तो आगे भी जिन दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा, मसलों के हल की तलाश, दोस्ती और रवादारी के माहौल में आसानी से पा लेंगे।

मैं जब पिछली दफ़ा आपके बीच हाज़िर हुआ था तो मैंने कहा था कि हमारी सरकार कश्मीर की इक्तिसादी तरक्की के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी, पूरा करने के लिए तैयार होगी। जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ मिलकर हम हर महीने काम की तरक्की का जायजा लेते हैं ताकि मंसूबा पूरा हो सके। हमारी कोशिश रही है कि जम्मू-कश्मीर सरकार के पास पूरे जराये हो ताकि जो

(शेष कवर तीन पर)

योजना

वर्ष : 49 अंक 2 मई 2005 वैशाख-ज्येष्ठ, शक संवत 1927 कुल पृष्ठ : 56

प्रधान संपादक
अनुराग मिश्रा

संपादक
विश्वनाथ त्रिपाठी

सहायक संपादक
राकेशरेणु

संपादकीय कार्यालय
कमरा नं. 538, योजना भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली–110 001
दूरभाष : 23096738, 23717910
23096666 / 2508, 2511
ई–मेल : yojana@techpilgrim.com
www.publicationsdivision.nic.in
a) dpd@nic.in
b) dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
एन.सी. मजूमदार

व्यापार प्रबंधक (प्रसार एवं विज्ञापन)
दूरभाष : 24367260, 2436509, 24365610

आवरण – दीपायन मैत्रा

इस अंक में

• विकास की एक प्रविधि है एसपीवी - मोंटेक सिंह अहलुवालिया	अमिति सेन	5
• बुनियादी सुविधाओं के विकास पर ध्यान दें : कमलनाथ	–	6
• ढांचागत सुविधाओं के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग	एस.एल. राव	7
• भारत और चीन में राजमार्ग और रेल विकास का तुलनात्मक मूल्यांकन	सेल हैरल एवं जीत सोंधी	11
• बुनियादी ढांचे के लिए वित्त व्यवस्था	अपर्णा सिन्हा	17
• निर्माण, संचालन, हस्तांतरण विधि (बीओटी) से बुनियादी ढांचे का मार्ग प्रशस्त होता है – प्रधानमंत्री	–	21
• चामत्कारिक प्रगति का संसार : दूरसंचार	विजय ठाकुर	23
• आर्थिक सर्वेक्षण की दृष्टि में बुनियादी ढांचा	–	27
• क्या है विशेष उद्देश्यीय व्यवस्था (एसपीवी)	–	29
• अर्थव्यवस्था दसवीं योजना का मध्यावधि मूल्यांकन	–	31
• शोध यात्रा : शारीरिक विकलांगों के लिए स्कूटर	–	33
• ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु समूह उद्यमिता का मॉडल	वीरेंद्र कुमार विजय	37
• पर्यावरण ग्रामीण समुदाय और प्रति संरक्षण से जुड़ी लघु खनिज नीति	भारत डोगरा	41
• फ्लाई ऐश – जैव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रबंधन	राजीव कुमार सिंह	43
• कश्मीर में फलों की खेती की धूम	–	52
• स्वास्थ्य चर्चा : तनाव से बचाव के लिए ब्राह्मी	जॉब थॉमस	53
• स्वास्थ्य चर्चा : केला : एक संपूर्ण आहार	गीता रानी	55
• अनुकरणीय पहल : अच्छा प्रयोग है दीवार लेखन	हीरल दवे	56

योजना हिन्दी के अतिरिक्त **असमिया, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलगू** तथा **उर्दू** भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। **पत्रिका मंगवाने हेतु, नई सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें :–**

व्यापार प्रबंधक (प्रसार एवं विज्ञापन), प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110 066 टेलीफोन : 26100207, 26105590

चंदे की दरें : वार्षिक : 70 रु.; **द्विवार्षिक** : 135 रु.; **त्रैवार्षिक** : 190 रु.; विदेशों में **वार्षिक** दरें : **पड़ोसी देश** : 500 रु.; **यूरोपीय एवं अन्य देश** : 700 रु.

'योजना' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से सम्बद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

आपकी राय

पेटेंट व्यवस्था : एक दिल्लगी

विकास को समर्पित 'योजना' का मार्च अंक पढ़ा। 'बजट-विशेष' यह अंक कई मायनों में संग्रहणीय लगा। सर्वप्रथम तो बजट 2005-06 में किए गए प्रावधानों पर लेखों के कारण, दूसरे मूल्यवर्द्धित कर (वैट) पर इतने विस्तार से बताने के कारण और 'पेटेंट व्यवस्था' पर विस्तृत चर्चा के कारण। पेटेंट व्यवस्था पर शामिल विभिन्न लेखों ने इस संबंध में फैली अनेक भ्रांतियों को दूर करने में मदद की।

परंतु इन लेखों में पेटेंट व्यवस्था के बाद औषधि क्षेत्र में विकास की जिस विस्तारशील प्रकृति को दर्शाने का प्रयास किया गया है वह के मुझे हजम नहीं हो सका। आज जबकि सारे विश्व की निगाहें भारत के फटेहाल किंतु 'भरे-पूरे' औषधि क्षेत्र पर किसी तरह कब्जा पा लेने पर लगी हैं, हम विश्व बाजार पर कब्जे की सोच रहे हैं। हमारी बड़ी दवा कंपनियां पेटेंट व्यवस्था के लागू होने के पश्चात विश्व बाजार में अपना हित देख रही हैं। सरकार का भी तर्क है कि डब्ल्यूटीओ का सदस्य बनने (1995) के बाद (2004 तक) हमारा औषधि निर्यात 4,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 14,000 करोड़ रुपये हो गया है और पेटेंट व्यवस्था के पूरी तरह लागू होने के बाद इसमें काफी वृद्धि होने के आसार हैं।

परंतु 40,000 करोड़ रुपये के समृद्ध देशी बाजार के विषय में घरेलू दवा कंपनियां और सरकार चुप्पी साधे हैं। 40,000 करोड़ रुपये के इस विशाल बाजार पर आज भी विदेशी दवा कंपनियों का हिस्सा 30 फीसदी के लगभग है और पेटेंट व्यवस्था के लागू होने के बाद उनकी हिस्सेदारी निश्चित रूप से और बढ़ेगी जिसका कम-से-कम भारतीय उपभोक्ताओं पर अच्छा प्रभाव नहीं होगा। दवाइयों के दाम निश्चित रूप से बढ़ेंगे और जनसाधारण का वर्तमान जीवनस्तर इन दवाओं के 'साइड इफेक्ट्स' के रूप से नीचे गिरेगा।

इन सबके बावजूद सरकार द्वारा एक ही राग अलापना कि 'पेटेंट व्यवस्था भारतीय औषधि उद्योग को विश्वस्तरीय बनाने के मदद करेगी' भारतीय जनता के प्रति सरकार के प्यार को नहीं बल्कि एक तरह के 'दिल्लगी' (जुनून) को दर्शाती है।

अजित कुमार
गेवाली, नवादा, बिहार

विशेष प्रस्तुति

मार्च अंक की विशेष प्रस्तुति के लिए आपको धन्यवाद। पत्रिका के जनवरी 2005 अंक में '**इतिहास के आइने में**' नामक कॉलम में दो लेख छपे हैं जिनमें से 'योजना का उद्देश्य' नाम से प्रकाशित दूसरे लेख में कुछ त्रुटि का आभास होता है क्योंकि वी.टी. कृष्णामाचारी के नीचे लिखा है 'प्रथम उपाध्यक्ष, योजना आयोग, फिर 'योजना आयोग के बीते दिन' (लेखक-मुजीब उर रहमान) शीर्षक से प्रकाशित पेज नं. 24 पर दूसरा पैरा, पहली लाइन में लिखा है, 'गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे'। दोनों में विरोधाभास है। आपसे अनुरोध है कि इस आशय की सूचना अगले अंक में दें।

दीपेन्द्र बहादुर सिंह
तेलियागंज, इलाहबाद

नवीनता है अंकों में

योजना के अभी हाल ही में मार्च एवं अप्रैल 2005 के अंक पढ़े। पत्रिका के आवरण नवीनता लिए हुए हैं। चित्रों का रंग संयोजन विशेष बना है। पत्रिका का कागज़ भी अच्छी क्वालिटी का है। सबसे खास बात है पत्रिका के आलेख तथा विषयवस्तु। मार्च के अंक में 2005-06 के बजट की विस्तृत जानकारी महत्वपूर्ण है। देवेन्द्र कुमार का लेख 'बजट शब्दावली परिचय' नवीनता लिए हुए है तथा एस.जे. परमार का 'मूल्यवर्धित कर (वैट)' शीर्षक आलेख भी काफी जानकारी युक्त है। इसी तरह अप्रैल 2005 के अंक में प्रकाशित 'जहां चाह वहां राह' के अंतर्गत 'असंभव को संभव किया' शीर्षक कुमार मयंक का आलेख सराहनीय एवं अनुकरणीय है। साथ ही, श्री नरेन्द्र देवांगन का 'परिवर्तनशील बनिए' आलेख भी प्रेरणादायी है।

सभी अंक रोचक एवं जानकारी देने वाले हैं। यदि पत्रिका में शासकीय योजनाओं की प्रस्तुति की जाए तो पत्रिका और भी उपयोगी सिद्ध होगी। विभिन्न क्षेत्रों की सफलता की कहानियां तथा चित्रों का समावेश भी पत्रिका में किया जाना उपयुक्त होगा।

सभी आलेख प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हैं तथा उपयोगी हैं। भविष्य में पत्रिका की सफलता की कामना के साथ,

विभा नरगुन्दे
इंदौर, म.प्र.

आंकड़े उपयोगी हैं

मैं एक प्रतियोगी छात्र हूं। मैंने मासिक पत्रिका 'योजना' को कॉलेज पुस्तकालय में पढ़ा। मुझे यह बहुत ज्ञानवर्द्धक लगा।

इसमें शामिल आंकड़े, समसामयिक घटनाओं एवं ज्वलंत मुद्दों पर लेख अन्य किसी जगह इस प्रकार नहीं मिल पाते।

आर्थिक क्षेत्र में होने वाली विभिन्न घटनाओं का विवरण सही ढंग से पढ़ने को मिलता है जो मेरे लिए बहुत लाभदायक है।

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय
मोतिहारी, बिहार

परिवर्तन के बीच चुनौतियां एवं अवसर

वस्त्र-उद्योग में खुली प्रतिस्पर्धा भारत के लिए चुनौती व अवसर दोनों हैं। आखिर कब तक बैसाखियों का सहारा लिया जाए? अपने पांव को दुरुस्त कर (अवरोधों व असंतुलन को दूर कर) मजबूत इरादे व दृढ़ कदमों से इस नवीनता को स्वीकार कर सफलतापूर्वक रास्ता तय करना होगा। ऊर्जा (बिजली) की समुचित आपूर्ति, ढांचागत सुविधाओं का विकास और श्रम-सुधार के साथ तकनीक का श्रेष्ठतम व इष्टतम उपयोग कर हम इस चुनौती को एक सुखद अवसर में बदल सकते हैं। पारदर्शिता, क्रियात्मकता और जवाबदेही की व्यवस्था से हम अपने मिशन में जरूर कामयाब होंगे। गुणवत्ता व प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाकर हम विश्व-बाजार में आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं, बशर्ते यह प्रक्रिया अनवरत चलनी चाहिए। वस्तुत: आकर्षण में यदि रहना है तो परिवर्तन के साथ परिवर्तित होना होगा अन्यथा बदलते बाजार के प्रतिमानों में कौन किसे पूछता है?

उमेश चन्द्र राय
इलाहाबाद (उ.प्र.)

इस अंक में

बुनियादी ढांचागत विकास तथा त्वरित प्रगति और आर्थिक विकास के बीच के संबंध के बारे में जो भी कहा जाए, कम है। बुनियादी ढांचे के मामले में भारत अपने प्रमुख एशियाई देशों से पीछे है। यह बात चीन के साथ एक चलताऊ तुलना से भी स्पष्ट हो जाती है। यद्यपि चीन के 18.1 लाख किमी. सड़क नेटवर्क की तुलना में भारत का सड़क नेटवर्क (33 लाख किमी.) अधिक व्यापक है, लेकिन चीन में 30 हजार किमी. लंबा एक्सप्रेस-वे है जबकि 2004 में भारत में कुल एक्सप्रेस-वे मात्र 3.5 हजार किमी. लंबा है। दूरसंचार घनत्व तथा अन्य क्षेत्रों में भी लगभग यही स्थिति है।

गत वर्ष शीर्ष अमरीकी कंपनियों के प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों के साथ न्यूयॉर्क में हुई बैठक में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने बुनियादी ढांचागत विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उनका अनुमान था कि अगले 10 वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 150 खरब डॉलर की आवश्यकता होगी। उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास को निजी क्षेत्र के सम्मुख खड़ी सबसे बड़ी चुनौती और साथ-ही-साथ सबसे बड़ा अवसर भी बताया।

प्रश्न उठता है कि क्या बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए निजी क्षेत्र की आवश्यकता है? इस काम में उन्हें शामिल करने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, सरकार की अन्य प्रतिबंद्धताएं और प्राथमिताएं भी हैं इसलिए उसके पास अपेक्षित वित्तीय संसाधन नहीं हैं। दूसरे, सड़क, हवाईअड्डों, बंदरगाहों तथा बिजली उत्पादक संयंत्रों का निर्माण निजी क्षेत्र संभवत: ज्यादा कुशलतापूर्वक कर पाएगा। यदि सरकार इन परियोजनाओं में निजी क्षेत्र को शामिल करना चाहती है, तो उसे ज्यादा व्यावहारिक नीतियां बनानी पड़ेंगी ताकि निजी कंपनियों को आकर्षित किया जा सके। सभी संभावित पक्षों को समान अवसर प्रदान करना होगा। निवेशकों में अपेक्षित विश्वास कायम करने के लिए स्वायत्त एवं ऊर्जावान नियामक संरचना स्थापित करना महत्वपूर्ण होगा।

केंद्रीय बजट 2005-06 में बुनियादी ढांचे के अभाव को सर्वाधिक खटकने वाली बात मानते हुए एक वित्तीय विशेष उद्देश्यीय व्यवस्था (एसपीवी) का प्रस्ताव रखा गया है जो सड़क, बंदरगाह, हवाईअड्डे तथा पर्यटन जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को वित्त प्रदान करेगी। यह व्यवस्था पात्र परियोजनाओं को सीधे दीर्घावधि ऋण प्रदान करेगी जो उसे बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त होने वाले ऋण के अलावा होगा। वर्ष 2005-06 के लिए इस प्रकार के ऋण की सीमा 10,000 करोड़ रुपये रखी गई है।

बातचीत के दौरान जब कुछ अमरीकी प्रमुख कार्यकारियों ने प्रधानमंत्री से आर्थिक सुधार पर कुछ राजनीतिक दलों के विरोध के बारे में पूछा तो प्रधानमंत्री ने कहा कि जनतंत्र होने के नाते भारत में सर्वानुमति पर पहुंचने के लिए खुली परिचर्चा को बढ़ावा दिया जाता है। इससे सुधार ज्यादा स्थायी बनते हैं।

इस अंक को बुनियादी ढांचा पर केंद्रित करते हुए शामिल आलेखों के माध्यम से न केवल ढांचागत विकास की मौजूदा अवस्था का विश्लेषण किया गया है, बल्कि उपलब्ध विकल्पों पर दृष्टिपात करने का भी प्रयास किया गया है। ❑

हमारे टॉपर्स

Amritendu Sekhar
BPSC 1st Topper

"सर के G.S. पढ़ाने-समझाने एवं अभिभावक की तरह मार्गदर्शन का तरीका अद्भुत है"

Ajay Kumar
BPSC 8th Topper

ILA G. PARMAR
IAS 2003

वैकल्पिक विषय के रूप में / इतिहास / का वैज्ञानिक तरीके से अध्यापन जिससे प्री० में 90 से 100 प्रश्न सही, मुख्य परीक्षा में न्यूनतम 350 अंक

सामान्य अध्ययन के कुल 600 अंक में 588 अंक और निबंध के 200 अंक नोट्स एवं कक्षा में किए गए अभ्यास के अनुरूप आया है तब अधिक भटकाव क्यों?

G.S.

सामान्य अध्ययन

IAS/PCS (फाउंडेशन + मुख्य + प्रारम्भिक)
+ टेस्ट सीरिज + मानक प्रश्न-उत्तर प्रारुप कक्षाएँ

By

R. Kumar & Team

नया बैच प्रारम्भ : 01.06.2005

हमारे टॉपर्स

Shashi Bhusan Singh
UPPCS Topper

"G.S. और इतिहास मेरे लिए सबसे अंकदायी रहा इसका सम्पूर्ण श्रेय सर को जाता है।"

Sunil Kumar Agarwal
IAS 2003

Updated जीवंत पत्राचार

सामान्य अध्ययन :-
मुख्य परीक्षा - 7 Booklet
प्रारंभिक परीक्षा - 4 Booklet
इतिहास :-
मुख्य परीक्षा - 3 Booklet
प्रारंभिक परीक्षा - 3 Booklet
हिन्दी साहित्य - 3 Booklet

Science & Tech. by R. Kumar IAS TUTORIALS
Economics by R. Kumar & Team IAS TUTORIALS
Indian Polity by R. Kumar IAS TUTORIALS
History by R. Kumar IAS TUTORIALS
G. Science by R. Kumar IAS TUTORIALS
...

शुल्क एवं अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें:-

अन्य विषय

इतिहास	समाज शास्त्र	लोक प्रशासन
द्वारा	द्वारा	द्वारा
विशेषज्ञ समूह	डॉ० एस.आर. सिंह	मनीषा सिंह

आवासीय सुविधा उपलब्ध

आस्था IAS TUTORIALS
102-103, Jaina House, Mukherjee Nagar, Delhi-9
Ph.: (0) 27651392 Cell.: 9810664003

1 मई, 2004 से IAS TUTORIALS का नया नाम आस्था IAS TUTORIALS हो गया है।

विकास की एक प्रविधि है एसपीवी – मोंटेक सिंह अहलूवालिया

हम जो कुछ हासिल करना चाहते हैं उस लिहाज से एसपीवी तंत्र में कोई कमी नहीं है। हमारा अनुभव है कि नियामक व्यवस्था सही नहीं है। हमें इसमें सुधार करना होगा। ये विचार हैं योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया के। प्रस्तुत है अमिति सेन के साथ उनका साक्षात्कार

आप बुनियादी ढांचे के लिए मुद्रा भंडार से धन उपलब्ध कराने के प्रबल समर्थक हैं, लेकिन क्या सचमुच में यह मुद्रा भंडार के इस्तेमाल का सबसे अच्छा तरीका है?

मैंने ये कभी नहीं कहा कि हमें विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल देश के मुद्रा भंडार से 'चेक काटो और धन निकालो' की तरह करना चाहिए। मैंने तो ये कहा था कि चूंकि अब हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है अत: हम बढ़ते आयात खर्च के बावजूद विदेशी मुद्रा के मामले में कोई कठिनाई महसूस नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब था कि व्यवस्था को अस्थिर किए बगैर हम इसकी ज्यादा मांग पूरी कर सकते हैं।

मैं नहीं मानता कि लोग इससे असहमत होंगे। मेरा मानना है कि लोग ऐसी मांग को पूरा करने से खुश नहीं होते जो उत्पादन बढ़ाने में लाभदायक नहीं है। यही वजह है कि मैंने कहा है कि हमें सीधे तौर पर बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी मांग की पूरी करनी चाहिए। यह विचार भारत के लिए अनोखा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सलाहकारों ने, जो हाल में यहां आए थे, मुझे बताया कि एशिया के कई देश जिनके पास बहुत बड़ा मुद्रा भंडार है, इस बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं कि वे इसे दूसरे देशों को उधार देने की बजाए अपने यहां के कार्यों के लिए किस तरह इस्तेमाल करें। अत: जो कुछ हम कह रहे हैं शेष एशिया में भी उसी तरह की बातें हो रही हैं।

आप और स्पष्ट रूप से कुछ कहेंगे?

हमने महसूस किया है कि भारत सबसे ज्यादा बुनियादी ढांचे के क्षेत्र मे पीछे है। योजना आयोग में हम महसूस करते हैं कि हमें प्रयास करके धन जुटाने के रास्ते खोजने चाहिए ताकि इससे हम अच्छी ढांचागत परियोजनाओं, खासकर निजी-सार्वजनिक भागीदारी वाली परियोजनाओं का निर्माण कर सकें। वित्त मंत्री ने इससे सहमति व्यक्त की है और उन्होंने एक विशिष्ट व्यवस्था अर्थात एसपीवी की व्यवस्था करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। मैं एसपीवी व्यवस्था से बहुत खुश हूं। कुछ सूचनाएं बेवजह फैलाई गई हैं कि मैं इसका आलोचक हूं। यह पूरी तरह गलत है। संक्षेप में एसपीवी का अर्थ है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। एक समय हम विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के बारे में सोच-विचार कर रहे थे और उनमें यह भी एक रास्ता था। किसी तंत्र को चुनने का अर्थ है कि हम उसके तहत काम करेंगे। हम जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए इस व्यवस्था में कोई कमी नहीं है।

अब हमें यह सुनिश्चित करना है कि परियोजनाएं व्यावहारिक हों। यदि वे व्यावहारिक नहीं हैं तो उन्हें छोड़ देना होगा, हमें उनके लिए धन उपलब्ध नहीं कराना है।

एसपीवी के अतिरिक्त और क्या विकल्प हो सकते हैं, जिनके बारे में सोचा गया होता?

बहुत से विकल्प हैं। लेकिन मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता क्योंकि इससे सीधे-सीधे कई तरह के सवाल उठेंगे कि क्या इससे अच्छा वह नहीं हो सकता और मैं नि:संकोच कहता हूं कि हमें यह वित्त मंत्रालय पर छोड़ देना चाहिए। वित्त मंत्रालय और केंद्रीय बैंक जिसे अनुकूल मानें वही एक अच्छी व्यवस्था है। मैं नहीं मानता कि इस व्यवस्था में कोई बाधा है। आपका उद्देश्य इस व्यवस्था से बुनियादी ढांचे के लिए बेरोक-टोक निवेश को बढ़ावा देना मात्र है।

लेकिन यदि आपकी मांग जायज है, तो क्या यह एक कृत्रिम मांग पैदा करने जैसा नहीं है। देश में मुद्रा भंडार उपलब्ध है। बुनियादी ढांचे के लिए जो भी जरूरी है हम आयात कर सकते हैं।

नहीं, यह मुद्दा नहीं है। तथ्य यह है कि जब आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार है तो आप आर्थिक व्यवस्था को बहुत गड़बड़ाए बिना ही बढ़ती सामान्य मांग को पूरा कर सकते हैं। सवाल यह है कि सामान्य वृद्धि के लिए इस समय धन कैसे उपलब्ध कराएं। यदि हमारे पास नियामक व्यवस्था होती तो सही होता। निजी क्षेत्र के निवेशक इसमें शामिल होने को तत्पर हैं, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि धन के प्रवाह से अधिक धन उपलब्ध होने से बैंक इसे निजी क्षेत्र को उधार-ऋण के रूप में उपलब्ध कराएंगे। और निजी क्षेत्र की निवेश की मांग बढ़ेगी। इसका इस्तेमाल आयात के लिए किया जा सकेगा और विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल हो सकेगा।

बुनियादी सुविधाओं के विकास पर ध्यान दें : कमलनाथ

केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री कमलनाथ ने देश तथा अंतरराष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग करने के लिए अभिनव उपकरण और प्रणाली विकसित करने का आह्वान किया ताकि देश की बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था की जा सके। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति तथा संवर्द्धन विभाग और **फिक्की** द्वारा आयोजित दो दिवसीय **भारत बुनियादी सुविधा शिखर बैठक** का आज सुबह यहां उद्घाटन करते हुए श्री कमलनाथ ने कहा कि इन क्षेत्रों में संसाधनों की जरूरतों को देखते हुए यह संभव नहीं है कि सरकार अपने बजटीय संसाधनों से इसकी वित्तीय जरूरतों को पूरी तरह वहन कर सके। सरकार ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सार्वजनिक/निजी भागीदारी पहलों को मदद देने के उद्देश्य से व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण सुविधा की शुरुआत की है। व्यवहार्यता अंतर का वित्त पोषण कई रूपों और पूंजी तथा राजस्व के संयोजन के जरिये हो सकता है। उन्होंने निवेशक समुदाय से अनुरोध किया कि वे इस सुविधा का पूरा लाभ उठाएं।

इन सुविधाओं में सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली, जलापूर्ति, मल निकासी, ठोस कचरे का प्रबंधन और अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन केंद्र शामिल हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था की विशाल निवेश संबंधी जरूरतों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश में बुनियादी सुविधा क्षेत्र में 150 खरब अमरीकी डॉलर मूल्य के विदेशी निवेश की जरूरत है।

आर्थिक विकास में बुनियादी सुविधाओं की भूमिका पर बल देते हुए श्री कमलनाथ ने कहा कि जापान तथा अमरीका और यूरोप सहित सभी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सबसे पहले बुनियादी ढांचे का विकास किया गया था। हमारे पड़ोस में, दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों और चीन ने भी ऐसा ही किया है। भारत की संस्थागत शक्ति तथा अन्य कई कारकों की वजह से आज देश शानदार भविष्य के साथ स्वतंत्र बाजारी लोकतंत्र के रूप में विश्व में तेजी विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि हमें इस स्वस्थ माहौल को बनाए रखना है तो हमें बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के लिए काफी कुछ करना होगा। प्रत्यक्ष बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की कमी होने से हमारे आर्थिक विकास में काफी अड़चनें आएंगी। सही मायनों ने कहा जाए तो हम पिछड़ जाएंगे। बुनियादी ढांचागत सुविधा चालक और निवेश को आकर्षित करने वाला चुंबक दोनों ही है। ❑

(पीआईबी फीचर)

बहुत से ऐसे कारण है जिनकी वजह से हम महसूस करते हैं कि नियामक व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें इसमें सुधार करना होगा। लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। इसमें 3-4 साल लग सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि इन 3-4 सालों में आप कुछ नहीं करेंगे। आपके सम्मुख नियम संबंधी अनिश्चितताएं हैं और आपको नए नियम बनाने होंगे। जब तक नियमों का परीक्षण न हो जाए और न्यायालय उनके बारे में मत न व्यक्त कर दे तब तक पूर्ण विश्वसनीयता की बात नहीं की जा सकती। क्योंकि विवाद तो पैदा होते ही हैं। मेरा कहना है कि इंतजार किए बिना निवेश को तेज कर देना चाहिए।

जिन परियोजनाओं के लिए आप एसपीवी के जरिए धन उपलब्ध कराए जाने की बात कर रहे हैं, क्या वे पूरी तरह सरकारी क्षेत्र की होंगी या आप सरकारी-निजी भागीदारी की बात कर रहे हैं?

इस बारे में अभी औपचारिक फैसला नहीं लिया गया है। मेरे विचार में यदि परियोजना मोटे तौर पर बुनियादी ढांचे के लिए होगी तो यह सार्वजनिक क्षेत्र की हो सकती है लेकिन यह व्यावसायिक दिशा में अग्रसर होगी। उदाहरण के लिए, यदि रेल विकास निगम लिमिटेड किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निवेश में वृद्धि करना चाहती है तो मैं सोचता हूं इसके लिए एसपीवी उपलब्ध रहेगा।

आप नियामक व्यवस्था कायम करने के लिए बहुत प्रयासरत हैं। लेकिन क्या नियामक संस्थाओं में नियुक्ति का सरकार के लिए एक रास्ता नहीं बन गया है?

मैं यह नहीं कहूंगा कि सभी नियुक्तियां खराब हैं।

लेकिन ये सब सेवानिवृत अधिकारी हैं।

यह सही है। मैं भी रिटायर्ड अधिकारी हूं। (हंसते हुए) इसके स्पष्ट कारण हैं कि क्यों हम रिटायर्ड लोगों और अधिकारियों को चुनते हैं। कारण यह है कि नियामक बनने के बाद आप सरकारी नौकरी नहीं ले सकते। इसका मतलब यह हुआ कि आपको लोगों को उनके कार्यकाल के अंत में ही चुनना होगा। वे रिटायर्ड नहीं होने चाहिए, मैं सहमत हूं। उन्हें उनकी सेवानिवृति से दो साल पूर्व चुना जा सकता है। लेकिन निजी क्षेत्र के लोगों की बजाए सरकारी अफसरों को नियुक्त करने का कारण तो यह है कि हम प्रतियोगी वेतन का भुगतान ही नहीं कर सकते। मेरा विश्वास है कि यदि आप वेतन व्यवस्था में सुधार कर लें तो आप सबको खुश कर सकते हैं (हंसते हुए)।

हमें व्यवस्था में सुधार के लिए ज्यादा सक्रियता से काम करने की जरूरत है। चेयरमैन से ज्यादा महत्वपूर्ण बात स्टाफ की क्वालिटी है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। ❑

(योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया का अमिति सेन द्वारा लिया गया साक्षात्कार। फाइनेंशियल एक्सप्रेस से साभार)

ढांचागत सुविधाओं के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग

○ एस.एल. राव

बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए उपकरणों के आयात को बढ़ावा देने में विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग एक अच्छी धारणा है। इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी क्योंकि इस धन का विदेश में उपयोग किया जाएगा

आज यह आम धारणा बन गई है कि बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की कमी विकास के रास्ते की एक प्रमुख बाधा है। सड़क, रेल, बंदरगाह, जल, बिजली, कोयला जैसी आवश्यक सेवाओं अथवा वस्तुओं के समयानुसार, किफायती और अधिक गुणवत्ता के साथ उत्पादन-संचालन और वितरण की स्थिति आलोचना के लायक है। मुख्य स्वामी के रूप में सरकार इस बारे नीति-निर्धारण करने के साथ-साथ प्रबंधन भी करती है। लेकिन इन सभी प्रयासों में क्षमता की कमी है और यह विश्वस्तरीय सेवाएं उपलब्ध कराने में समक्ष नहीं हैं। इनकी क्षमता और गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बनाने के लिए बड़ी मात्रा में धन निवेश करने की आवश्यकता है। इनमें से कुछ के लिए निजी निवेश को मंजूरी दी गई है किंतु निजी निवेशक भी सभी प्रकार के कोष जुटाने में सक्षम नहीं हैं। हमारे लिए उन सभी स्रोतों को इस्तेमाल में लाना जरूरी है जिन्हें हम बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में निवेश के लिए जरूरी मानते हैं।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार वृद्धि की ओर अग्रसर होने के साथ ही इस्तेमाल से वंजित है और बुनियादी ढांचागत निवेश के लिए इसके द्वारा धन जुटाने के सुझाव मिल रहे हैं। बहुत से आम लोग और विशेषज्ञ किसी न किसी रूप में इनके इस्तेमाल और विदेशी मुद्रा के प्रवाह के पक्षधर हैं। वृद्धि की ओर अग्रसर अपने विदेशी मुद्रा भंडार के प्रति वे गौरवान्वित हो सकते हैं। सरकार, अर्थशास्त्रियों, व्यापारियों और उन लोगों के लिए मुद्रा भंडार की स्थिति उत्साहवर्द्धक है जिन्हें वर्ष 1991 की भयानक स्थिति के बारे में याद है जब हमारा मुद्रा भंडार सिर्फ दो सप्ताह के आयात के लायक रह गया था और जब्त किया गया सोना ब्रिटेन के पास बंधक रखा गया था। इसको लेकर संशयग्रस्त राजनीतिज्ञों और साम्यवादियों ने वित्त मंत्री की जोरदार आलोचना की थी।

अभी भी भारतीय उद्योगों को अतिरिक्त संरक्षण प्रदान करने के कुछ ऐसे हिमायती हैं जिन्हें इस बात का डर है कि विदेशी मुद्रा प्रवाह से हमारी महत्ता प्रभावित होगी। कई भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी कंपनियों को भारत में निष्पक्ष प्रतियोगिता में पीछे छोड़ने के बाद भी ऐसा है। अन्य लोग इसके कारण महंगाई बढ़ने की आशंका से त्रस्त हैं। एक आशंका यह भी है कि हमारे बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार का मुख्य हिस्सा प्रवासी भारतीयों के पूंजी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा शेयर बाजार की खरीद है। इन्हें परिवर्तनशील समझा जाता है। प्रवासी भारतीयों का धन परिपक्वता की स्थिति में वापस लिया जा सकता है। विदेशी संस्थागत निवेशक भी बड़ी मात्रा में अपना धन वापस ले सकते हैं। अगर वे ऐसा करें तो हम आधारभूत निवेशों में लगाए गए धन उन्हें किस प्रकार वापस कर पाएंगे। इसके पीछे सबसे बड़ी आलोचना यह है कि इन भंडारों में राष्ट्र का कम हिस्सा और विदेशी निवेशकों का बड़ा हिस्सा शामिल है।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने मुद्रा-प्रवाह के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों की भूमिका के कारण मुद्रा भंडार की परिवर्तनशीलता के बारे में चिंता व्यक्त की है। कुछ सप्ताह पूर्व उन्होंने कहा, "विदेशी संस्थागत निवेशकों के द्वारा बाजारों में मुद्रा प्रवाह की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। इसके लिए कर जैसे मूल्य-आधारित उपायों का मूल्यांकन होना चाहिए क्योंकि उनकी प्रभावोत्पादकता के बारे में तर्क-वितर्क हो सकता है।" वित्त मंत्री ने इस बात से इनकार किया कि ऐसे कर के बारे में विचार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि इसके लिए सारे विकल्प खुले होंगे।

शेयर बाजार पर नजर रखने वाले किसी भी व्यक्ति को मालूम है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान शेयर के मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव का मुख्य कारण विदेशी धन का एकाएक

'पतञ्जलि' दर्शनशास्त्र की तैयारी हेतु समर्पित भारत का विशेषज्ञ संस्थान **IAS/PCS**

दर्शनशास्त्र

सर्वाधिक लोकप्रिय एवं अंकदायी विषय

द्वारा

धर्मेन्द्र कुमार

धर्मेन्द्र कुमार के विशेषज्ञतापूर्ण एवं सारगर्भित मार्गदर्शन में संस्थान ने अपनी स्थापना के पश्चात दर्शनशास्त्र को लेकर सिविल सेवा के क्षेत्र में लगातार सफलता के नवीन प्रतिमानों को स्थापित किया है तथा इसे एक सुरक्षित, विश्वसनीय एवं सर्वाधिक अंकदायी विषय के रूप में प्रतिष्ठित किया है।

दर्शनशास्त्र विषय के साथ हिन्दी माध्यम में **सर्वोच्च स्थान**

UPSC
13th Rank
डॉ० प्रदीप सिंह राजपुरोहित

"दर्शनशास्त्र में 'पतञ्जलि' के धर्मेन्द्र कुमार सर से काफी सहायता मिली।"
(राष्ट्रीय सहारा, दिल्ली संस्करण-१२ मई)

UPPSC,
Ist Ranker

दर्शनशास्त्र विषय के साथ **सर्वोच्च स्थान**

बिपिन कुमार मिश्रा

"मैंने 'पतञ्जलि' के निर्देशक धर्मेन्द्र कुमार सर से दर्शनशास्त्र एवं साक्षात्कार हेतु कोचिंग ली थी, जिसका निर्णायक रूप से मुझे लाभ मिला। दर्शनशास्त्र की तार्किक एवं वैज्ञानिक रूप से उनकी अभिव्यक्ति एवं जटिल तथ्यों के भी सरल रूप में स्पष्टीकरण की कला ने मेरे अभिव्यक्ति पक्ष को मजबूत बनाया। यहाँ उल्लेखनीय है कि मैंने बाद में 'पतञ्जलि' में दर्शनशास्त्र के कुछ भागों का अध्यापन का भी कार्य किया।"
(प्रतियोगिता दर्पण, फरवरी ०४, पृष्ठ १२९१)

UPSC-2003, 41st Rank
राजेश प्रधान

देश भर में दर्शनशास्त्र में **सर्वोच्च अंक**

"दर्शनशास्त्र हेतु मैंने 'पतञ्जलि' के निदेशक धर्मेन्द्र कुमार सर से मदद ली थी। जरूरत के अनुरूप उनका मित्रवत् मार्गदर्शन मेरे लिये लाभदायक रहा।"
(सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, दिसम्बर २००३, पृष्ठ ४८)

अमृतेन्दु शेखर ठाकुर **BPSC,** Ist Ranker

"मार्गदर्शन मुझे श्री धर्मेन्द्र कुमार (निर्देशक Patanjali) का मिला।"
(प्रतियोगिता दर्पण, अप्रैल २००४, पृष्ठ १६७७)

जगदीश प्रसाद मीणा
I.A.S.
दर्शनशास्त्र विषय के साथ S.T. वर्ग में
द्वितीय स्थान

अविनाश कुमार
I.P.S.

"दर्शनशास्त्र के द्वितीय-पत्र में देश भर में ***सर्वोच्च अंक।***"

फूलचन्द मीणा
I.A.S.
दर्शनशास्त्र विषय के साथ S.T. वर्ग में
पाँचवां स्थान

अरविन्द कुमार, I.R.S.

"दर्शनशास्त्र विषय के साथ अपने पहले ही प्रयास में सफल।"

दीपक कुमार
DANIPS

"दर्शनशास्त्र विषय के साथ प्रथम प्रयास में सफल।"

अभय कुमार, I.C.E.S.

"दर्शनशास्त्र विषय के साथ प्रथम प्रयास में सफल।"

कक्षा कार्यक्रम-2005

दर्शनशास्त्र (Philosophy)

प्रथम बैच

24 मई, समय: 8.30 प्रात:)

(नि:शुल्क परिचर्चा के साथ कक्षा प्रारम्भ)

द्वितीय स्वतंत्र बैच

16 जून

(नि:शुल्क परिचर्चा के साथ कक्षा प्रारम्भ)

PHILOSOPHY (English Medium)
(Separate Batch - 24 May, 11.00 a.m.

राजनीति विज्ञान

द्वारा - **जितेन्द्र कृष्णन**

बैच का प्रारम्भ - 1 जून

(नि:शुल्क परिचर्चा 29,30,31 मई

नामांकन प्रारम्भ - 16 मई 2005

पत्राचार कार्यक्रम
दर्शनशास्त्र (मुख्य परीक्षा)

संस्थान दर्शनशास्त्र हेतु पर्याप्त, गुणात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ, अत्यन्त उपयोगी एवं प्रमाणिक अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराता है। इसमें वैसे अध्यायों पर विशेष बल दिया गया है जिस पर प्रमाणिक सामग्री सहजता से उपलब्ध नहीं है। पत्राचार सामग्री को प्राप्त करने के लिये २६०० रू० का दिल्ली में भुगतान योग्य बैंक ड्राफ्ट 'PATANJALI IAS CLASSES' के नाम भेजें।

PATANJALI

2580, हडसन लाईन, किंग्जवे कैम्प, दिल्ली-110009 फोन : 011-30966281,
मोबाईल : 9810172345 वैबसाइट : www.patanjaliias.com E-mail : pir@patanjaliias.com

सलाह, सहयोग, समर्थन-दर्शन प्रसार एवं अनुसंधान केन्द्र

आना-जाना है। आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत से विदेशी संस्थागत निवेशकों का बहिर्गमन पिछले बारह वर्षों के दौरान सिर्फ 1998-99 में हुआ था, जब पोखरण के आणविक परीक्षणों के कारण प्राय: सभी विकसित देशों ने प्रतिबंध लगा दिया था और उन्हें लगा था कि देश की अर्थव्यवस्था अनिश्चितता का सामना करने वाली है। इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशकों के बल पर ही प्रत्येक वर्ष विदेशी संस्थागत धन का आना जारी रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इस विषय पर अंतरराष्ट्रीय शोध पर सहमति व्यक्त करते हुए ठीक ही कहा कि ऐसे धनागम पर कर प्रभावोत्पादकता तर्क-वितर्क का विषय है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के इस उदार वक्तव्य पर दलालों, व्यापारियों और कुछ स्तंभ लेखकों की प्रतिक्रिया आलोचनात्मक थी। कुछ संपादकीय लेखों में भी इसकी आलोचना की गई थी। हाल के वर्षों में कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के वक्तव्य के बारे में विश्लेषण और चर्चा नहीं हुई थी। यह प्रतिक्रिया इसलिए थी क्योंकि इन लोगों को यह मालूम था कि छोटी घटनाओं और सरकार की नीति के प्रति शेयर बाजार में प्रतिक्रिया अक्सर ही नकारात्मक होती है। उन लोगों को विदेशी संस्थागत निवेशकों से भी विपरीत प्रतिक्रिया की आशा थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। गवर्नर द्वारा सावधानीपूर्वक प्रयोग में लाए गए शब्द किसी नीति की ओर संकेत नहीं कर रहे थे। वास्तव में उन्होंने 'कीमत आधारित उपायों' के मूल्यों के बारे में भी सवाल उठाया। उनके वक्तव्य के पक्ष अथवा विपक्ष में निंदा के बिना भी तर्क-वितर्क किए जा सकते थे। इस प्रतिक्रिया से ऐसे विचार की तर्कहीनता और अनिच्छा का पता चलता है जिससे शेयर बाजार में हलचल आती है और ये विश्लेषक और दलाल ऐसी स्थिति को जारी रखना चाहेंगे।

इस बारे में कुछ लोगों का कहना है कि यह धन सरकार का नहीं है और इसका बड़ा हिस्सा उधार के रूप में है और ऐसे में इन सुझावों को लागू करने से महंगाई बढ़ने की प्रबल संभावना होगी।

किसी ने भी यह नहीं कहा कि आधारभूत निवेश को सशक्त बनाने से केवल निवेश ही प्रभावकारी नहीं होता बल्कि निवेश के द्वारा होने वाली कमाई से हम लाभान्वित होते हैं।

अब यह सवाल उठता है कि निजी आधारभूत निवेश की स्थिति दयनीय क्यों रही है। धन की कमी होना इसका प्रमुख कारण नहीं है। जब वातावरण ठीक रहता हो तो भारत से और विदेश से धन प्राप्त हो जाता है। दूरसंचार के क्षेत्र में निवेश बढ़ना इस बात का पर्याप्त प्रमाण है। किंतु जब भी वातावरण प्रतिकूल होता है तो धन नहीं मिल पाता। निजी धन तब तक आधारभूत निवेश के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा जब तक कि व्यापारिक दृष्टि से यह अर्थपूर्ण न हो। सड़क और संभवत: रेल भी इसी श्रेणी में आते हैं। अगर नीतियां प्रतिबंधक रहती हैं तो उनके प्रति निजी निवेशकों में कोई रुचि उत्पन्न नहीं होगी।

विद्युत वितरण में निजी निवेश के दरवाजे हालांकि 1998 में ही खोल दिए गए थे, फिर भी, निवेश का द्वार खुलने के बावजूद टाटा पावर को छोड़कर अन्य किसी उपक्रम में निजी निवेश नहीं हो पाया। जब बिजली उत्पादन के लिए निजी निवेश का द्वार पहली बार खुला तब कई घरेलू और विदेशी प्रस्ताव मिले। जब संभावित निवेशकों ने यह महसूस किया बिजली वितरण कंपनियां मुख्य रूप से राज्य सरकारों के विभाग हैं जो काफी घाटे में चलती हैं और बिजली खरीद के लिए समय पर भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्होंने प्रस्ताव वापस ले लिए। एकमात्र डाभोल स्थित एनरॉन परियोजना शुरू हुई थी और अत्यधिक धन लागत, महंगे इंधन और ऊंचे शुल्कों के फलस्वरूप महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा संभाल पाने में अक्षम रहने के कारण मुश्किल में पड़ गई। डाभोल परियोजना बंद होने के कारण निजी निवेशकों ने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में निवेश करने के प्रति अपने विचार बदल दिए। उड़ीसा में बिजली निजीकरण की योजना का स्वरूप निर्धारण और क्रियान्वयन इस बेतरह प्रकार से किया गया कि उड़ीसा बिजली आपूर्ति से जुड़े निजी निवेशक इसके क्रियाशील होने को लेकर अब तक संघर्ष कर रहे हैं। परिणामस्वरूप इस प्रकार के अन्य निजी उपक्रमों में निवेश के प्रति विमुखता रही है। तेल की खोज के क्षेत्र में भी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अत्यधिक संभावनाओं वाले क्षेत्रों में खोज कार्य रोकने तक निजी निवेशकों का आकर्षण कायम रहा।

बिजली के क्षेत्र में वितरण का जिम्मा अभी भी राज्य विद्युत बोर्डों के पास है जो नौकरशाहों द्वारा चलाए जा रहे हैं और यह कार्य किसी प्रकार की व्यावसायिक और उद्यमी संस्कृति के बिना हो रहा है। विद्युत अधिनियम से कैप्टिव उत्पादन की और भी अधिक लोचदार परिभाषा के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं और उपभोक्ताओं के लिए एक भिन्न दायरा तैयार करने में मदद मिलेगी और इससे कैप्टिव उत्पादन समूह तैयार करने में संगठन और सहकारी संस्था कायम करने के क्रम में भी बल मिलेगा।

इसलिए कैप्टिव नेटवर्क की योजना तैयार करना संभव है जिसमें वितरण लाइनों तक खुली पहुंच हो और वितरण शुल्क पर कोई वैसा अधिभार न हो जो उपभोक्ता अथवा वितरण लाइनों तक पहुंच के लिए लागू हो।

अधिभार और रियायतें सीमित हों। बिजली वितरण के क्षेत्र में 2002 के बाद दिल्ली में प्रगति नहीं होने के बाद उत्तर प्रदेश इसके लिए तैयार दिखता है। अन्य राज्य भी इसका अनुकरण करेंगे। इस नीति से ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में प्रगति सुनिश्चित है। इन परिवर्तनों से बिजली के क्षेत्र में बड़े निवेश का रास्ता आसान बनता है।

कोयले के क्षेत्र में केंद्र सरकार का एकाधिकार है और इस क्षेत्र में निजी निवेश को अनुमति मिलने का कोई संकेत नहीं है। लाइसेंस पद्धति अथवा शुल्क ढांचा के लिए कोई विनियामक नहीं है।

इनके बिना किसी प्रकार का निजी निवेश संभव नहीं है क्योंकि बंधक खदानों के लिए भी कोयला बेचने की अनुमति नहीं है। अब तक रेलों के लिए निजी निवेश का रास्ता नहीं

खुला है और शुल्कों और अन्य मुद्दों को स्वतंत्र रूप से तय करने के लिए एक विनियामक के बिना निजी निवेश आसान नहीं है। शहरी परिवहन प्रणाली को छोड़कर फिलहाल इसमें निजी निवेश का मौका नहीं नजर आता है।

सड़क के क्षेत्र में निजी निवेश को थोड़ा आकर्षित किया जा सकता है। परंतु इसके लिए निवेशकों को सुनिश्चित पथकर की अनुपस्थिति में पर्याप्त मुनाफा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रारूप विकसित करना जरूरी होगा। एक वैकल्पिक प्रारूप के द्वारा विकासकर्ताओं को सड़कों के आसपास भू-संपदा विकसित करने की स्वीकृति दी गई है। ताकि उनसे पथकर वसूलना न पड़े। लेकिन इस अवधारणा की शुरुआत अभी नहीं हुई है। बंगलूर-मैसूर राजमार्ग परियोजना एक दशक से अधर में लटकी हुई है और कर्नाटक के भूमि के मोह से पीड़ित राजनीतिज्ञ इसे शुरू करने में रुकावट डालेंगे।

तेल और गैस के लिए पाइपलाईन बनाने के संदर्भ में अब तक सरकारी उपक्रमों का एकाधिकार रहा है। ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में निजी निवेश की अनुमति जल्द मिलने के साथ ही हमें शुल्कों, लाइसेंसों और पहुंच आदि के स्वतंत्र नियमन की जरूरत होगी। फिलहाल संसद में पेश विनियामक विधेयक के मसौदे में गैस विनियामक की कार्यप्रणाली शामिल नहीं है। गैस पाइपलाइन के क्षेत्र में निजी निवेश का प्रवेश तो हो सकता है परंतु इसके लिए कुछ सावधानी बरतना जरूरी होगा।

हमें आधारभूत परियोजनाओं के लिए निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए आगे आना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम 1990 के दशक की शुरुआत की उन विनाशकारी गलतियों को दोहराएंगे जब फास्ट-ट्रैक परियोजनाओं, संप्रभु सरकार की गारंटी आदि को बिजली क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा था किंतु यह प्रयास बुरी तरह विफल हो गया था। जहां तक विदेशी मुद्रा भंडार के इस्तेमाल का सवाल है, लंबे समय तक इसके मूल्यांकन के बाद इसे वित्तीय रूप से व्यवहार्य पाया गया। इसके साथ ही उन्हें समय पर पूरा करने के लिए काफी अच्छा प्रबंधन भी है जिनके बल पर विदेश से कर्ज लेना अथवा प्रत्यक्ष कर्ज लेना सही साबित होगा। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार इस्तेमाल में लाई गई धनराशि पिछले अनुभवों पर आधारित एकाएक होने वाले मुद्रा बहिर्गमन की प्रत्याशा की तुलना में काफी कम होगी। राजावाडे के सुझाव के अनुसार भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों से लिए गए कर्जे की जगह किफायती अंतरराष्ट्रीय दरों पर मुद्रा भंडार से कर्ज उपलब्ध कराना चाहिए। ऋणों की वापसी रुपयों में होना चाहिए। आधारभूत परियोजनाओं के लिए आयात के सिलसिले में लागतों पर प्रतिबंध होना चाहिए। यह कर से मुक्त अथवा रियायती करों पर आधारित होना चाहिए।

एक अन्य संभावना यह है कि इस स्रोत से आयात परियोजनाओं में आधारभूत निवेश के लिए निवेशकों को मंजूरी दी जाए और इस आयात के अंतर्गत इस्पात और सीमेंट जैसी स्थानीय तौर पर उपलब्ध वस्तुओं सहित सभी आवश्यक वस्तुओं को शामिल किया जाना चाहिए। इन कोषों में से स्थानीय लागतें इतनी भिन्न होंगी जिससे मंहगाई बढ़ने का खतरा होगा। लेकिन हमें अगर 1980 की उन आपदाओं से बचना है, जब राज्यों के उपक्रमों ने विदेशों से कर्ज लिए और कर्ज की वापसी के समय अपने आपको दबाव में पाया तो, हमें निश्चित तौर पर परियोजनाओं की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक उनका चयन करना होगा। इसके अतिरिक्त भविष्य निधि के रूप में धन का एक अन्य स्रोत भी उपलब्ध है जिसका उपयोग सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों द्वारा सभी प्रकार के बुनियादी ढांचागत निवेशों के लिए किया जा सकता है। अगर सरकार बिजली क्षेत्र में इक्विटी पर 14 प्रतिशत मुनाफा की गारंटी देने में सफल होती है तो भविष्य निधि से और भी अधिक कमाई हो सकती है और सदस्यों को वर्तमान 9.5 प्रतिशत का मुनाफा भी दिया जा सकता है।

विदेशी मुद्रा भंडार का विशेष रूप से बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए उपकरण के आयात हेतु उपयोग एक अच्छी अवधारणा है। इससे मंहगाई नहीं बढ़ेगी क्योंकि धन का खर्च विदेश में होगा। इसके द्वारा किए गए क्षमता निर्माण से ऋण की वापसी सुनिश्चित होगी। बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं पर विवेकपूर्ण तरीके इस्तेमाल करने के बाद भी इसका प्रभाव महंगाई बढ़ाने वाला हो सकता है। लेकिन यह आवश्यक है कि परियोजनाएं व्यवहार्य हों और बिना देरी के उन्हें क्रियान्वित किया जाए, साथ ही कर्जदाता द्वारा उनपर नजर रखी जाए।

हमारे लिए बुनियादी ढांचागत सेवाओं के लिए सही संचालन शर्तों की जरूरत है। निवेश निश्चित तौर पर राजस्व और मुनाफे की ओर अग्रसर हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन में सुधार लाने, व्यापारिक सोच अपनाने, लागत कम करने और सेवाओं में सुधार लाने का निरंतर प्रयास होना चाहिए। सरकारी स्वामित्व वाली प्राय: सभी ढांचागत सेवाओं में स्थिति भिन्न है। संसाधनों की चोरी, ठगी, असीमित रियायतों के कारण उत्पन्न घाटे को रोकने के लिए जरूरी रखरखाव और उपकरणों की मरम्मत, कर्मचारियों की अधिकता और अनुशासनहीन कार्यप्रणाली से उबारने हेतु मालिक को ऐसा अवसर जरूर मिलना चाहिए ताकि प्रबंधकीय नियंत्रण कायम होने के साथ-साथ संस्था व्यापारिक कार्य निष्पादन और उपभोक्ताओं के प्रति सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध हो। इन परिवर्तनों के लिए ढांचागत क्षेत्रों में व्यापक सुधार लाना जरूरी है। जब तक हम आवश्यक व्यापक सुधारों की उपेक्षा करेंगे, बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में से केवल उनके लिए ही निजी निवेश हो पाएगा जिनके लिए सरकार की ओर से मुनाफे की गारंटी होगी। ऐसी स्थिति अर्थव्यवस्था को प्रतियोगी बनाने के विचार से अथवा उपभोक्ताओं के हितों की दृष्टि से सही नहीं है। ❑

निर्मल निवास, बी-41, जीवन पार्क
पंखा रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली-59

भारत और चीन में राजमार्ग और रेल विकास का तुलनात्मक मूल्यांकन

○ सेल हैरल एवं जीत सोंधी

पिछले दो दशकों में, भारत में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर लगभग 5.5 प्रतिशत रही जबकि अर्थव्यवस्था लगभग 2.6 गुणा बढ़ते हुए 2002 में लगभग दस बिलियन अमरीकी डालर के स्तर तक पहुंच गई। चीन में इसी अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद 9.5 प्रतिशत बढ़ता रहा जबकि 1982 और 2002 के बीच अर्थव्यवस्था में पांच गुणे से अधिक वृद्धि हुई और 2002 में, यह लगभग 1,232 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गई। चीन का सकल घरेलू उत्पाद जो 1982 में भारत का लगभग 1.2 गुणा था, 2002 में भारत से 2.6 गुणा बढ़ गया था। गरीबी घटाने में आर्थिक वृद्धि के प्रभाव के संदर्भ में, चीन में 40 करोड़ लोग गरीबी से उबरे और गरीबी दर में भी 4.6 प्रतिशत तक की कमी आई। भारत में इसी दौरान गरीबी दर 3.6 प्रतिशत से घटकर 2.9 प्रतिशत हो गई।

दोनों अर्थव्यवस्थाओं का ढांचा भी अलग तरह से विकसित हुआ, जिसमें कृषि क्षेत्र का हिस्सा चीन में ज्यादा तेजी से घटा, जो कि 2002 में सकल घरेलू उत्पाद के 15 प्रतिशत से भी कम था जबकि भारत में यह आंकड़ा लगभग 23 प्रतिशत था। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सेवाओं का योगदान 2002 में 50 प्रतिशत के आसपास था और औद्योगिक विकासदर लगभग 27 प्रतिशत रही जबकि चीन में, सेवाओं का हिस्सा सकल घरेलू उत्पाद के एक-तिहाई से थोड़ा ऊपर स्थिर बना रहा लेकिन औद्योगिक विकासदर, सकल घरेलू उत्पाद के 52 प्रतिशत से भी ऊपर बढ़ी। इसके अलावा, 2002-2003 तक चीन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और व्यापार भारत से कई गुणा अधिक था। चीन की अर्थव्यवस्था भी भारत से कहीं ज्यादा मालभाड़ा परिवहन-उन्मुखी रही है।

1990 की शुरुआत में भारत का राजमार्ग और रेलवे आधारभूत संरचना, कुल मार्ग किलोमीटर/वर्ग किलोमीटर और मार्ग किलोमीटर/जनसंख्या मद के संबंध में चीन से आगे थी लेकिन आधारभूत संरचना के उपयोग की स्थिति, विशेषकर रेलवे का मुद्दा इससे भिन्न था। राजमार्ग और रेलवे आधारभूत संरचना का विकास 1992 में दोनों देशों के रेलवे की प्रति किलोमीटर यात्री संख्या (314 के मुकाबले 315 बिलियन प्रति किमी.) लगभग बराबर रही लेकिन चीनी रेलवे ने पटरी, रेलइंजन और मालडिब्बों के कहीं अधिक प्रभावी उपयोग और यात्री सेवाओं को निम्न प्राथमिकता देकर भारतीय रेलवे के 257 बिलियन टन किलोमीटर मालभाड़े के साढ़े चार गुणा मालभाड़ा, लगभग 1,157 बिलियन टन किलोमीटर पहुंचाया। भारतीय रेल ने उपनगरीय आदि यात्री सेवाओं को प्राथमिकता दी जबकि चीनी रेलवे इस बोझ से मुक्त रहा। इसी से पता चलता है कि भारतीय नागरिकों में यात्रा की ओर अधिक झुकाव है जिसके फलस्वरूप भारतीय रेल ने प्रति

तालिका

भारत और चीन के मुख्य आर्थिक आंकड़े 1992-2002

	भारत		चीन	
	1991-92	2001-02	1992	2002
जनसंख्या (करोड़ में)	846	1000	1171	1300
गरीबी दर (प्रतिशत)	36	29	40	7
सकल घरेलू उत्पाद (चालू अरब डॉलर)	244.2	510.2	454.6	1232.7
सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.5	4.4	14.4	8.0
सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा (प्रतिशत) उद्योग	26.7	26.4	43.9	51.7
सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा (प्रतिशत) सेवाएं	42.3	50.7	34.3	33.7
व्यापार (चालू अरब डॉलर)	46	157	165	623
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (चालू अरब डॉलर)	1.8	4	11	53

स्रोत : विश्व बैंक 'भारत-एक नज़र' और 'चीन-एक नज़र'

किलोमीटर 314 बिलियन यात्री पहुंचाए गए जो कि अनुमानित प्रति किलोमीटर कुल यात्रियों का मात्र 20 प्रतिशत था जबकि चीनी रेलवे द्वारा पहुंचाए गए 315 बिलियन प्रति किलोमीटर यात्री उसके अनुमानित प्रति किलोमीटर कुल यात्रियों का 45 प्रतिशत था। पिछले दो दशकों में माल ढुलाई का बड़ा हिस्सा सड़क मार्ग, तटीय नौ परिवहन और चीन में हुए अंतर्देशीय जल परिवहन से किए जाने के कारण दोनों देशों के रेलवे का हिस्सा उनके मालभाड़ा बाजारों में काफी हद तक कम हुआ था। 1992 में भारतीय रेलवे का हिस्सा 45 प्रतिशत था जो कि चीनी रेलवे के 40 प्रतिशत से कुछ ही बेहतर था।

हालांकि 1992 में भारत का सड़क नेटवर्क चीन से ज्यादा व्यापक था मगर दोनों देशों में सड़क नेटवर्क की गुणवत्ता आधुनिक राजमार्ग के मानकों के संदर्भ में, बेहद अपर्याप्त थी। पटरी, सड़क आयोजना और यातायात-प्रबंधन जैसे सभी पहलुओं से दोनों देशों में सड़क नेटवर्क की गुणवत्ता लगभग एक सी थी, सिवाय इसके कि चीन में सड़कों का रखरखाव संभवत: बेहतर था। पैदल लोग, जानवर और अन्य धीमी गति वाले यातायात का अनियंत्रित मिश्रण दोनों देशों में एक-सा था जो धीमी यात्रा-गति, अनिश्चित यात्रा समय और उच्च दुर्घटना दर का कारक था।

1992-2002 के दशक के दौरान रेलवे और राजमार्ग विकास में चीन भारत से बहुत आगे निकल गया।

- 1997 में शुरू हुए एशियाई मुद्रा संकट के बाद हुई समष्टि आर्थिक मंदी का लाभ उठाते हुए चीन ने राजमार्ग पर खर्चों को दोगुना कर दिया, 1997 के 13 अरब डॉलर की तुलना अगले वर्षों में प्रतिवर्ष 27 अरब डालर या उससे अधिक खर्च किया जिससे विषमताएं भी बेहतरी में बदल गईं क्योंकि अनुमान है कि राजमार्ग निर्माण से चीन का सकल घरेलू उत्पाद अगले वर्षों में पूरे 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ गया। भारत के सड़क व्यय का औसत केवल 1 से 3 अरब डालर प्रतिवर्ष आया।
- रेल नेटवर्क विस्तार और क्षमता विस्तारीकरण में भी भारत चीन से पिछड़ गया क्योंकि वहां द्विपथ नेटवर्क का 69 प्रतिशत (+9,400 किलोमीटर) विस्तार किया गया, 'विद्युतीकृत ट्रैक किलोमीटर' दोगुना (+8,975 किलोमीटर) किया गया और नेटवर्क मार्ग-किलोमीटर 24 प्रतिशत (+13,797 किलोमीटर) व्यापक किया गया। इसमें नए स्थानीय रेल निगम द्वारा निर्मित 12,367 किलोमीटर रेलपथ भी सम्मिलित था, जिसमें निजी हिस्सेदारी थी जो राष्ट्रीय रेलवे से अलग स्वामित्व और गतिविधि वाली थी। भारत में ऐसा नहीं है, यहां भारतीय रेल ने रेल सेवा का एकाधिकार अपने पास सुरक्षित रखा है। 1992-2002 के दशक के दौरान सरकारी स्वामित्व की रेल में निवेश, चीन और भारत में क्रमश: 85 और 17.3 अरब अमरीकी डालर रहा।
- चीनी रेलवे द्वारा 1992-2002 में वहन किया गया वार्षिक मालभाड़ा यातायात (1,157 से 1,551 तक = 394 बिलियन टन किलोमीटर),

IAS/PCS
आरोहण
(हिन्दी माध्यम)
"आपके सपनों से मंजिल तक"

उपलब्ध विषय :-

भूगोल (प्रा०+मु०): राजीव सौमित्र
दर्शनशास्त्र (मु०) : डा० ए० के० मिश्रा
संस्कृत साहित्य : ललित मण्डल
इतिहास (प्रा० मु०): D.U. के प्रख्यात प्रोफेसर डा० ए० के मिश्रा
सामान्य अध्ययन: संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा
साक्षात्कार : वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व संबंधित विशेषज्ञों द्वारा

UPSC जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में शामिल हो रहे छात्र/छात्राओं को निश्चित रुप से एक ऐसी चुनौती मिलती है जिसे लगन, मेहनत, समर्पण व इच्छा शक्ति से ही पूरा किया जा सकता है। देश के दूर-दराज इलाकों से आने वाले छात्रों की एक बड़ी समस्या उचित वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व मार्गदर्शन का न मिल पाना है। लिहाजा छात्र/छात्राओं को अपना कीमती समय भटाकव में गुजारना पड़ता है। मध्यम आय वर्ग व कमज़ोर आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र/छात्रा, फीस की एक मोटी रकम देने में सक्षम नहीं होते। इसी के मद्देनजर कम फीस में ही हमारा संस्थान एक बेहतर शिक्षण व कुशल मार्गदर्शन की व्यवस्था करता है। इसीलिए हमारी सफलता दर शत-प्रतिशत है।

विशेष आकर्षण:

सिविल सेवा के अभ्यर्थियों विशेषकर हिन्दी माध्यम के समक्ष प्रमुख समस्या वैकल्पिक विषय के चयन, पुन: उसकी तैयारी के तौर-तरीकों की होती है। विषय का सही चयन (विशेषकर दूसरा वैकल्पिक विषय) न कर पाना ही सफलता में सबसे बड़ी बाधा है। अत: यहाँ के विशेषज्ञ (यदा-कदा प्रशासनिक अधिकारी भी) द्वारा अभ्यर्थियों की पृष्ठभूमि एवं रुचि को ध्यान में रखते हुए मार्गदर्शन दिया जाता है।

संस्थान के सलाहकार सदस्य :

अजीत कुमार (IAS अधिकारी), एस० डी० तिवारी (PCS अधिकारी) उमाकांत तिवारी (PCS अधिकारी), प्रदीप कुमार, असीम कुमार (DSP)

✦ छात्र एवं छात्राओं के रहने की अलग-अलग व्यवस्था।
✦ पत्राचार कोर्स उपलब्ध।

☞ नया सत्र 25 मई एवं 9 जून से प्रारंभ।
☞ विशेष जानकारी व मार्गदर्शन के लिए दूरभाष या कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर सम्पर्क करें।

204, IInd Floor, A-23-24, Satija House, Commercial Complex (Near Batra Cinema) Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Tel. :(Off.) 011-27652362, (Mob.) 0-9868259370

भारतीय रेलवे द्वारा 2002 में वहन किए गए संपूर्ण मालभाड़ा यातायात (336 बिलियन टन किलोमीटर) से ज्यादा था, इससे चीनी अर्थव्यवस्था का अन्य विषयों में भी, कहीं ज्यादा मालभाड़ा- उन्मुखी होना झलकता है।

इस अवधि के दौरान, भारत के रेल-नेटवर्क में बढ़ोतरी सिर्फ 682 मार्ग किलोमीटर (1 प्रतिशत), 1,519 किलोमीटर द्विपथ (10 प्रतिशत) और विद्युतीकृत लाईन 5,192 किलोमीटर (48 प्रतिशत) हुई। यह रोचक है कि प्रति अमरीकी डालर निवेश 14.9 टन किलोमीटर + प्रति किलोमीटर पर वार्षिक यातायात में इस दशक के दौरान भारतीय रेलवे का लाभ, चीनी रेलवे (6.8 किलोमीटर + प्रति किलोमीटर) के दोगुने से ज्यादा (2.2 गुना) था लेकिन श्रम उत्पादकता में लाभ चीनी रेलवे के 90 प्रतिशत लाभ (728-1385 टन किलोमीटर + प्रति किलोमीटर) की तुलना में, केवल 61 प्रतिशत (402 से 648 टन किलोमीटर + प्रति किलोमीटर तक) था। चीनी रेलवे ने अतिरिक्त मूलधन का उपयोग बेहतर श्रम-उत्पादकता खरीदने में किया जिससे प्रति श्रमिक औसत उत्पादकता भारतीय रेल के दोगुने से ज्यादा (2.1 गुना) प्राप्त हुई और चीनी रेलवे ने ऐसी रेल-क्षमता का विकास किया जो अगले दशक तक या आगे भी, बढ़ी हुई मांग के अनुरूप था जबकि भारत ने ऐसा नहीं किया।

लेकिन लक्ष्य और उपलब्धि में सबसे ज्यादा अंतर राजमार्ग क्षेत्र में है। जब भारत का सड़क नेटवर्क आधिकारिक तौर पर 600,000 किलोमीटर (2.7 से 3.3 मिलियन किलोमीटर तक या 22 प्रतिशत) बढ़ा, तब लगभग सभी बढ़ोतरी उन अति-ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने हेतु बेहद निम्न-स्तरीय सड़कों में हुई, जहां प्रतिकूल मौसम में पहुंचना मुश्किल होता था। भारत के चार मुख्य शहरों को जोड़ने वाले उच्चस्तरीय प्रमुख महामार्ग ज्यादातर उपेक्षित रहे, अनियंत्रित एक्सेस फीचर के स्वर्णिम चतुर्भुज को चौड़ा करके चार लेन करने का प्रयास 1998 तक तो शुरू भी नहीं हुआ था और अब 2007 के अंत से पहले, इसके पूरा होने की उम्मीद नहीं है। इससे अलग, चीन का सड़क नेटवर्क आधिकारिक रूप से केवल 376,000 किलोमीटर (1.3 से 1.7 मिलियन किलोमीटर या 28 प्रतिशत) ही बढ़ा लेकिन जोर प्रमुख महामार्ग नेटवर्क पर था। 2002 तक 25,130 किलोमीटर एक्सप्रेस-वे जिनमें कम से कम चार लेन और नियंत्रित एक्सेस फीचर वाले थे और इसके अलावा भी 27,468 किलोमीटर चार लेन वाले दोहरे कैरिज-वे

1992 में भारत का सड़क नेटवर्क चीन से ज्यादा व्यापक था मगर दोनों देशों में सड़क नेटवर्क की गुणवत्ता आधुनिक राजमार्ग के मानकों के संदर्भ में, बेहद अपर्याप्त थी। पटरी, सड़क आयोजना और यातायात-प्रबंधन जैसे सभी पहलुओं से दोनों देशों में सड़क नेटवर्क की गुणवत्ता लगभग एक सी थी, सिवाय इसके कि चीन में सड़कों का रखरखाव संभवत: बेहतर था। पैदल लोग, जानवर और अन्य धीमी गति वाले यातायात का अनियंत्रित मिश्रण दोनों देशों में एक-सा था जो धीमी यात्रा-गति, अनिश्चित यात्रा समय और उच्च दुर्घटना दर का कारक था

राजमार्ग, अनियंत्रित एक्सेस फीचर के, तैयार हो चुके थे जिनमें 1992 में शुरू नेशनल ट्रंक हाईवे सिस्टम के लिए योजनाबद्ध 35,000 किलोमीटर के 27,000 किलोमीटर (या 77 प्रतिशत) भी सम्मिलित था।

अप्रैल 2004 में विश्व बैंक को उपलब्ध दस्तावेजों की डेस्क समीक्षा पर आधारित यह रिपोर्ट सर्वप्रथम 1992 में चीन के रेलवे और राजमार्ग व्यवस्था की दशा और उस समय विकास में जो बाधाएं दिखीं, उनका संक्षिप्त ब्यौरा है। इसके बाद, यह उन विभिन्न उपकरणों को समझने का साधन है जिन्हें आगामी दशक में बाधाओं को दूर करने और विकास को त्वरित गति देने के लिए प्रयोग में लाया गया और अंतत: यह प्रयास है चीन के अनुभव से उन सफल तत्वों की पहचान करने का, जो भारत में क्रियान्वित करने योग्य हों।

राजमार्ग

चीन ने दिखा दिया है कि एक गतिशील सड़क उद्योग चुनौतियों का सामना कैसे करता है और समुचित संसाधन उपलब्ध कराए जिनका प्रबंधन भी बेहतरीन रहा। भारत जिन कुछ विशिष्ट कदमों पर विचार कर सकता है, वे ये हैं :

1. आर्थिक प्राथमिकताओं के क्षेत्र और परियोजनाओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन, आधारभूत सड़क निवेश में बड़े स्तर पर बढ़ोतरी, विशेषकर मुख्य महामार्ग नेटवर्क में, जिसका ध्येय परिवहन की दिक्कतों को दूर करना और परिवहन सेवाओं की गति, बारंबारता, सुरक्षा और विश्वसनीयता में सुधार करना हो।
2. पहले से ही भारी दबाव झेल रहे सरकारी बजट को और अधिक बोझ से बचाने के लिए अतिरिक्त राजमार्ग व्यय हेतु धन, नए और विविध स्रोतों से जुटाया जाना चाहिए। जैसाकि इस मुद्दे पर विचार करने वाले विकिस (2004) और व ज्यादातर अन्य अर्थशास्त्रियों ने संस्तुति की है, भारत अन्य ईंधन पर बढ़े हुए उपकर की बड़ी भूमिका पर आंशिक निर्भरता का विकल्प चुन सकता है। सड़क नेटवर्क से जमा की गई चुंगी भी एक बड़ी राशि का योगदान कर सकती है। नेटवर्क के विस्तार और उन्नयन के लिए तात्कालिक मूलधन मांग हेतु बड़ी मात्रा में अर्थनिवेश की आवश्यकता है ताकि बीच का अंतर पूरा हो। सौभाग्य से, भारत का अधिक परिपक्व पूंजीबाजार सामान्यत: निजी स्रोतों को सार्वजनिक निवेश को अधिक उबारने में सहायता देता है। इसके अलावा, चीन से भिन्न, भारत में संस्थागत निवेशकों (बीमा कंपनियों और पेंशन निधि) में से कुछ जिनके पास गारंटी नहीं है और ज्यादातर जो सीमित गारंटी वाले हैं, उनके द्वारा

दीर्घकालिक ऋण से ब्याज रहित हिस्सेदारी को मजबूत सहारा मिल सकता है। अत: जब सार्वजनिक वित्त की संभावनाएं भारत में ज्यादा सीमित हैं तब निजी वित्त की अल्पकालिक और दीर्घकालिक संभावनाएं अधिक आशाजनक हैं।

3. भारत इस बात के लिए बेहतरीन स्थिति में है कि वसूली की ऊंची लागत और यात्रियों को विलंब कराने वाले छोटे-छोटे चुंगी खंडों की समस्या को कम करने या इससे बचने के लिए चुंगी वित्त-पहल का समूहीकरण राज्य या क्षेत्रीय राजमार्ग निगम द्वारा करे जो परिसंपत्तियों का संयोजन कर सके ताकि संचालन मूल्य कम हो, खतरा-प्रबंधन बेहतर हो और नेटवर्क-विस्तार सरल हो। ऐसा मौजूदा परिसंपत्तियों के राजस्व-प्रवाह को सुरक्षित बना कर किया जाए, बजाय छोटे-छोटे खंडों के द्वारा करने के।

इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि सड़क विकास निगम जो कई राज्यों में स्थापित हो चुके हैं, वास्तव में समस्याएं सुलझाने को कटिबद्ध हों और लालफीताशाही की ही एक और कड़ी बनकर न रह जाएं जोकि व्यक्तिगत पहल के लिए एक और बाधा हो। निजी उद्यमियों, विकासकर्ताओं से सहायता लेने के चीन के निर्णय में भले ही श्रेष्ठ ब्लूप्रिंट का अभाव था और तात्कालिक परिणाम अपने उसी मौजूदा स्वरूप में कायम न रह पाएं लेकिन इससे समस्याओं का समाधान ढूंढने की सबल प्रेरणा मिली जिसका उच्चस्तरीय राजमार्ग के विकास में बड़ा योगदान था। चीन में उस समय इसकी बेहद आवश्यकता थी जैसी कि आज भारत में है।

1990 के दशक में भारतीय रेलवे की अर्थव्यवस्था में आई तेज गिरावट, रेलवे के प्रदर्शन ओर भारतीय अर्थव्यवस्था की परिवहन आवश्यकताओं के बीच बढ़ते हुए अंतर से निपटने के लिए भारतीय रेलवे की परिस्थितिगत जांच करके आवश्यक कार्यवाही संस्तुत करने के लिए भारत सरकार ने 31 दिसंबर 31, 1998 में राकेश मोहन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह गठित किया। राकेश मोहन रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष और सुझाव इस प्रकार हैं:

मुख्य मुद्दे

- भारतीय रेलवे के सामने एक वित्तीय संकट है जिससे तुरंत निपटने की आवश्यकता है।
- निम्न गुणवत्ता और महंगी सेवाओं की वजह से मालभाड़ा बाजार के शेयर गिरते जा रहे हैं।
- समुचित संसाधनों के अभाव में राज्य सरकार में निवेश का संचय हो गया है जिसे राज्य सरकार मौजूदा व्यवस्था में निधिबद्ध नहीं कर सकती।
- भारतीय रेलवे को केवल लाभकारी परियोजनाओं में ही निवेश करना चाहिए।
- विशाल कार्मिक वर्ग, कम उत्पादकता और कर्मचारियों की बढ़ती संख्या कुल लागत का अनुपात है।
- अकर्मण्यता और बाजारगत प्रेरणाओं का अभाव।

DESTINATION IAS ACADEMY

IAS/ PCS (Pre-CUM-Mains - 2005-06)
U.G.C. / NET/ SLET

भूगोल
द्वारा
संजय सिंह
लेखक :
1. क्रॉनिकल भूगोल
2. क्रॉनिकल वस्तुनिष्ठ भूगोल
3. क्रॉनिकल भारत एवं विश्व का भूगोल

सामान्य अध्ययन /G.S.
द्वारा
कैलाश मिश्रा
संजय सिंह
डी आचार्य

समाज शास्त्र / Sociology
द्वारा
प्रवीन किशोर
First Time By Tecnocrat

इतिहास
डी आचार्य
(के दक्ष निर्देशन में)
फाउंडेशन कोर्स के लिए नामांकन आरंभ
Maximum Output in Minimum input

राजनीति विज्ञान / Pol. Sci.
द्वारा कैलाश मिश्रा

मुख्य संपादक : ट्रेण्ड एनैलिसिस
1. भारतीय अर्थव्यवस्था
लेखक 2. भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
3. बदलते हुए परिदृश्य में भारत की विदेश नीति

किन्हीं दो विषयों पर विशेष छूट, पत्राचार सुविधा उपलब्ध

at B-12, COMMERCIAL COMPLEX
DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-9
Mob. : 9868080491, 9868338235, 9818329854

- स्पष्ट है कि वर्तमान व्यवस्था और ढांचे को बनाए रखना सही नहीं है।

पुनर्गठन की आवश्यकता

- ग्राहक-केंद्रित नजरिए का अभाव- भारतीय रेलवे के तीन बाजारों (माल भाड़ा, अंतरराज्यीय यात्री और उपनगरीय यात्री) के लिए भिन्न-भिन्न संगठनों की आवश्यकता है। भारतीय रेलवे का वर्तमान प्रबंधन ढांचा और सरकारी विभाग वाला रवैया ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।
- स्पष्ट उद्देश्य का अभाव है, वाणिज्यिक उद्देश्य और सामाजिक भूमिका के बीच अस्पष्टता है, इन्हें अलग करना चाहिए।
- पुराना व्यापारिक ढांचा, बाजारगत परिवर्तन के अनुसार कार्यवाही के लिए सीमित लचीलापन, क्योंकि भारतीय रेलवे एक सरकारी विभाग की तरह काम करती है और अत्यधिक सीधा एकीकरण - इसके परिवहन के मुख्य व्यापार से ध्यान बंटता है।
- स्वायत्तता का अभाव और राजनैतिक दबाव।

सुझाव

- संगठन का पुर्नगठन

रेलवे पुर्नगठन पर पिछले दो दशकों में अंतरराष्ट्रीय अनुभव तीन सिद्धांतों पर आधारित था:

- रेलवे और सरकार के संबंधों में पर्याप्त दूरी बनाना:
- वाणिज्यिक क्षमताओं वाले ऐसे प्रबंधकों की भर्ती जो संगठन को ग्राहक-केंद्रित बना सकें और
- उचित व्यापारिक केंद्र बिंदु को परिभाषित करना तथा नॉन-कोर व्यापार की रचना।

सुझाए गए परिवर्तन इस प्रकार हैं:

- रेलवे को सरकार से अलग करके एक स्वतंत्र नियामक की स्थापना।
- रेलवे का वाणिज्यिक प्रबंधन जिसके केंद्र में व्यापार और बाजार खंड हों।
- मुख्य व्यापार और उससे उत्पन्न नॉन-कोर गतिविधियों पर जोर और स्टाफ घटाने का लक्ष्य।

व्यापार खंडों के लिए रणनीति

- मालभाड़ा : सेवा की बेहतर गुणवत्ता के लिए कम समय लेने वाली प्रीमियम सेवाएं, किराये में कमी, गड़बड़ियों दूर करना और दूर हुई वस्तुओं को पुन: पाने के लिए ग्राहक की आवश्यकताओं पर ध्यान देना।
- यात्री: यात्री किराये में पुनर्संतुलन, लचीलापन और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए निजी प्रबंधन की शुरुआत।
- कार्यक्षमता में सुधार करना, सात वर्षों में 25 प्रतिशत सुरक्षाकर्मी कम करना।

भारत इस बात के लिए बेहतर स्थिति में है कि वसूली की ऊंची लागत और यात्रियों को विलंब कराने वाले छोटे-छोटे चुंगी खंडों की समस्या को कम करने या इससे बचने के लिए चुंगी वित्त-पहल का समूहीकरण राज्य या क्षेत्रीय राजमार्ग निगम द्वारा करे जो परिसंपत्तियों का संयोजन कर सके ताकि संचालन मूल्य कम हो, खतरा-प्रबंधन बेहतर हो और नेटवर्क-विस्तार सरल हो

- निजी क्षेत्र और संयुक्त उद्यम सहित अन्य गैर-सरकारी स्रोतों से धन जुटाना।
- भारतीय वाणिज्यिक प्रथाओं और प्रारूपों के अनुसार लेखा-जोखा रखना।
- उच्च विकास परिदृश्य को लक्षित करना क्योंकि सामान्य व्यापार परिदृश्य भारतीय रेल को जल्द ही दिवालिया कर सकता है।
- राजस्व बढ़ोतरी, लागत मूल्य में कमी और अधिकतम निवेश जैसे मुख्य क्षेत्रों में सूचना-प्रौद्योगिकी का उपयोग।

भारतीय रेल का पुनराविष्कार

शीघ्र ही बड़े परिवर्तन के लिए स्पष्ट, बाध्यकारी और दबावपूर्ण स्थिति है कि भारतीय रेल के कार्य में स्वायत्तता होनी चाहिए और राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए कुछ देशों में पूर्णरूपेण निजीकरण हो रहा है। लेकिन भारत में अभी उसका समय नहीं आया है और निजीकरण के बजाय वाणिज्यीकरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सुझावों में निम्न सम्मिलित हैं:

- अलग नीति, नियम और व्यापार प्रबंधन : नीति निर्माता नीति निर्धारण करें और उसके लिए धन का प्रावधान करें और नियामक, प्रतिद्वंद्विता और अर्थप्रबंधन के नियम तय करें। भारतीय रेल का इस तरह निगमीकरण किया जाना चाहिए और इसे सरल बनाने के लिए सरकार स्पष्ट तौर पर प्रतिबद्ध हो कि भारतीय रेल को प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी और उसे व्यापारिक तरीके से काम करने दिया जाएगा।
- सामाजिक जिम्मेदारियों और प्रतिबद्धताओं के बीच स्पष्ट अंतर।
- वाणिज्यीकरण (नॉन-कोर व्यापार, व्यापारिक ढांचे की रूपरेखा और व्यापारिक लेखांकन को समाप्त करें)।
- नवीन प्रबंधन जो यथास्थिति बदलने को कटिबद्ध नेतृत्व दल जुटाए। इसके लिए आवश्यकता होगी अनुभवी व्यापारिक प्रबंधकों की।

हालांकि दोनों देशों की स्थिति में कई अंतर स्पष्ट हैं मगर तर्क दिया जाता है कि चीन में असामान्य आर्थिक विकास ने परिवर्तनकारी आंदोलन, वास्तव में 'जॅगरनॉट' पैदा कर दिया जिसने निष्क्रियता के दायरे तोड़ दिए और ऐसी कई बाधाओं पर विजय पाई जैसी भारत में भी मौजूद हैं। यदि भारत को अपनी परिवहन संबंधी समस्याओं को सुलझाना है और भविष्य में आर्थिक प्रगति बरकरार रखनी है तो उसे भी निष्क्रियता से उबर कर परिवहन की बुनियादी संरचना के निर्माण और उपयोग में कार्य प्रदर्शन के नए स्तर कायम करने होंगे। चीन में प्रयुक्त कई नीतियां और संस्थागत निर्माण को भारत में यहां की परिस्थितियों और उद्देश्यों के अनुसार अपनाया जा सकता है। साथ ही, संभावित नुकसान से बचने के लिए, चीन से सड़क संरचना के मूल्य निर्धारण और अर्थप्रबंधन में भी सबक लिया जा सकता है। ❑

ALS

2005 Calendar of Events

at *Interactions* IAS Study Circle

DELHI WORKSHOPS
ENGLISH MEDIUM SCHEDULE

23, 24, 25 May
02, 03, 04 June
15, 16, 17 June
23, 24, 25 June

DELHI WORKSHOPS
HINDI MEDIUM SCHEDULE

28, 29, 30 June
09, 10, 11 July
26, 27, 28 July

GEOGRAPHY
ENGLISH MEDIUM SCHEDULE

22 May 2005

GENERAL STUDIES
ENGLISH MEDIUM SCHEDULE

GS (Integrated) 01 June 2005
GS Crash Course 16 Aug 2005

GENERAL STUDIES
HINDI MEDIUM SCHEDULE

General Studies 08 July 2005

HISTORY, SOCIOLOGY, PUBLIC ADMINISTRATION, POLITICAL SCIENCE, PSYCHOLOGY & PHILOSOPHY
ENGLISH & HINDI MEDIUM SCHEDULE

ENGLISH MEDIUM
01 June & 22 June 2005

HINDI MEDIUM
27 June & 08 July 2005

Admissions Open: May 1, 2005

IAS Study Circle *interactions* Shaping dreams into success

Note: Payment should be made either in **Cash** or **DD**. In case of DD, it must be in favour of Alternative Learning Systems (P) Ltd, payable at Delhi

Corporate Office : ALTERNATIVE LEARNING SYSTEMS (P) LTD
B-19, ALS House, Near UTI ATM, Dr Mukherjee Nagar, Delhi-9. Ph : 27651700, 27651110 Cell : 9810312454

Divisions of ALS

interactions MiPS EDUCATION NIDI WIZARD ISGS Indian School of General Studies

बुनियादी ढांचे के लिए वित्त व्यवस्था

○ अपर्णा सिन्हा

"ऐसी सभी बुनियादी सेवाएं जिनके बगैर प्राथमिक, माध्यमिक तथा तीसरे स्तर की उत्पादन गतिविधियां न चलाई जा सकें" उन्हें बुनियादी ढांचे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बुनियादी ढांचे में निवेश का मकसद आगे चलकर अन्य उत्पादक गतिविधियों में निवेश को प्रोत्साहित करना होता है। सरल शब्दों में कहें तो बुनियादी ढांचे में सड़क, रेल, बंदरगाह तथा नागर विमानन जैसी परिवहन से जुड़ी सेवाएं और दूरसंचार, ऊर्जा, जल आपूर्ति, स्वच्छता तथा ठोस कचरा प्रबंधन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। भारत के प्रशासकीय साहित्य में बुनियादी ढांचे का उपयोग काफी ढीले-ढाले अर्थ में किया जाता है और इसमें इस्पात, सीमेंट, खाद, तथा पेट्रोलियम उत्पादों जैसे खरीदे बेचे जाने वाली वस्तुओं को शामिल किया जाता है। इनका चाहे जितना महत्व हो, इन सबका आयात किया जा सकता है। इसलिए इनका विकास न करने से देश की अर्थव्यवस्था के विस्तार में वे उस तरह से अवरोधक नहीं बन सकते जिस तरह से खरीद-बेच न की जा सकने वाली वस्तुएं)।

लेकिन राजनीतिज्ञों और मतदाताओं सहित अब सभी लोगों ने यह समझ लिया है कि इस प्रतिस्पर्द्धी विश्व में उच्च विकासदर प्राप्त करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचागत सेवाओं का क्या महत्व है। यह इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि अब चुनावी नारे भी 'बिजली, सड़क, पानी' होते हैं, न कि पूर्व की तरह 'जय जवान जय किसान' अथवा 'गरीबी हटाओ'।

बुनियादी ढांचे के लिए वित्त व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है ?

भारत में अथवा भारत के बाहर दुनिया में कही भी बुनियादी ढांचे के लिए वित्त व्यवस्था एक चुनौती विषय है। यह एक व्यापक रूप से स्वीकृत तथ्य है कि बुनियादी ढांचे की समुचित व्यवस्था के लिए निजी क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। क्योंकि इसमें घोषित रूप से बाहरीपन, जनता की भलाई, अप्रतिद्वंद्विता तथा अवर्जना के तत्व व्याप्त हैं। जोखिम भरी तथा दीर्घ प्रतीक्षा अवधि वाली परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निजी क्षेत्र से बड़ी मात्रा में संसाधन इकट्ठा करना एक कठिन काम है। खासकर इस आलोक में कि अनेक मामलों में ऐसी परियोजना के द्वारा केवल उपभोक्ता प्रभार से मुनाफा कमा पाना आसान नहीं होता। इसी प्रकार, केवल सार्वजनिक क्षेत्र पर बुनियादी ढांचागत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह निर्भर नहीं हुआ जा सकता। इसके दो कारण हैं- पहला, केंद्र और राज्य दोनों की वित्तीय सीमाओं के मद्देनजर व्यापक बजटीय समर्थन की संभावनाएं बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं होतीं। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के निष्पादन को लेकर आमतौर पर एक मोहभंग की स्थिति है जिससे यह धारणा बनी है कि सार्वजनिक क्षेत्र के संचालन में ही अकुशलता तथा उपभोक्ता के सरोकारों के प्रति तुलनात्मक संवेदनहीनता का गुण अंतर्निहित है।

इस तरह सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्र बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने में अपर्याप्त पाए गए हैं। अतः बुनियादी ढांचे के लिए वित्त व्यवस्था की इस उलझी हुई समस्या का समाधान संभव है कि सार्वजनिक-निजी साझेदारी के रूप में दोनों के सहजीवी संबंध में ही अंतर्निहित हो जो इन दोनों की आंतरिक शक्तिओं और कमजोरियों पर आधारित होगा। आमतौर पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र अलग-अलग, लेकिन एक-दूसरे की पूरक भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। इसके मद्देनजर, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की साझेदारी में उच्च गुणवत्तायुक्त बुनियादी ढांचे के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की साझेदारी की संकल्पना को अनेक विकासशील देश अंगीकार कर रहे हैं।

सार्वजनिक-निजी क्षेत्र की साझेदारी क्या है?

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की साझेदारी अनिवार्यतः सरकार और निजी क्षेत्र के बीच पैसे का बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए संरचना तैयार करने हेतु किया जाने वाला सहयोग है। यह करदाताओं को दी जाने वाली गुणवत्ता के बारे में सरकार की समग्र जिम्मेदारी को कम करके आंके बगैर नवोन्मेष और जोखिम का बेहतर प्रबंधन कर सकने वाले निजी पक्ष की भागीदारी द्वारा हासिल किया जा सकता है।

इसका मकसद सरकार, निजी क्षेत्र और प्रयोक्ता- सबके दोनों हाथों में लड्डू वाली स्थिति पैदा करना है। सरकार की जीत इस बात में निहित है कि वह अपने लोगों को समुचित सेवाएं प्रदान करने के दायित्व को पूरा कर पाने की सामर्थ्य आती है। निजी क्षेत्र के हाथ में लडडू यों है कि वह अपने निवेश को पर उचित लाभ कमा सकता है। प्रयोक्ता गुणवत्तायुक्त बुनियादी ढांचागत सेवाओं की उपलब्धता, समर्थता और सुगमता से लाभान्वित होंगे।

यह मान्यता कि बजटीय वित्त की तुलना में व्यावसायिक वित्त महंगा होता है, सही नहीं है। अनेक बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं का क्रियान्वयन वर्षों कोष के अभाव में लटका रहता है। इससे लागतों में भारी वृद्धि हो जाती है, प्रभार बढ़ते जाते हैं तथा मुद्रास्फिति होती है। यह याद रखना जरूरी है कि ऐसी स्थिति की अवसर लागत निषेधात्मक होती है। इससे अनेक मामलों में कीमतें प्रतिगामी हो जाती हैं। फलतः निर्धनों को समृद्धों के मुकाबले अधिक भुगतान करना पड़ता है।

सार्वजनिक और निजी साझेदारी का बुनियादी सिद्धांत यह है कि निजी क्षेत्र की सेवा की डिजाईन, वित्त व्यवस्था, निर्माण तथा प्रचालन के लिए उत्तरदायी होगा। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच जोखिम के आवंटन

IAS-2005/06 IAS-2005/06 IAS-2005/06 IAS-2005/06 IAS-2005/06

प्रशासनिक अध्ययन संस्थान
Institute Of Administrative Studies

पेशेवर दृष्टिकोण, परिमार्जित अध्यापन, परिष्कृत व्यवहार

With galaxy of experts we are the source to enrich your quality for becoming moral and model civil servant.

Course Offered

लोक प्रशासन By **ASHOK KR. DUBEY** Batch Starts From - 17th June

समाजशास्त्र By **RENOWNED EXPERT** Batch Starts From - 16th June

इतिहास By **K. D. SINGH** (इलाहाबाद) Batch Starts From - 14th June

सामान्य अध्ययन-विशेषज्ञों के दल द्वारा

लोक प्रशासन जल्द ही इलाहाबाद में भी

माड्यूलर G.S. By भारतीय अर्थव्यवस्था - **K. BASHAR** Batch Starts From - 14th June

राष्ट्रीय पत्राचार प्रशिक्षण कार्यक्रम
लोक प्रशासन- प्रारंभिक -1500/-, मुख्य- 3000/-

Note - पत्राचार के छात्रों के लिए एक सप्ताह का विशेष कक्षा कार्यक्रम (दिल्ली में)

SC/ST/OBC/HC/Women के लिए शुल्क में रियायत **HOSTEL FACILITY**

102/B-14, Ist Floor, Commercial Complex, Near HDFC ATM, Mukherjee Nagar, Delhi-9

Ph. 55368702, 9312399055, 9811291166

IAS-2005/06 IAS-2005/06 IAS-2005/06 IAS-2005/06 IAS-2005/06

के आधार पर इसकी मूल योजना में अनेक बदलाव होते हैं। आमतौर पर इनके जो प्रचलित स्वरूप हैं वे ये हैं : बनाओ-चलाओ-हस्तांतरित करो, बनाओ-चलाओ-स्वामित्व में लो-हस्तांतरित करो, बनाओ-स्वामित्व में लो-पट्टे पर दो-हस्तांतरित करो, डिजाईन बनाओ-निर्माण करो, वित्त दो-चलाओ तथा मुक्त परियोजनाएं।

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की साझेदारी से जुड़ी संकल्पनाएं

पैसे का मूल्य

इसका मूल विचार यह है कि लोगों को न केवल कम से कम लागत पर, बल्कि गुणवत्ता पूर्ण तथा समयबद्ध रूप से सेवाएं देना सुनिश्चित किया जाए। इसमें मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक तुलना शामिल है। मौद्रिक तुलना में सार्वजनिक और निजी साझेदारी की लागत की तुलना पारंपरिक सार्वजनिक क्षेत्र की प्राप्ति से की जाती है जिसे साझेदारी की अवधि में नकद प्रवाह पर दी गई छूट के रूप में व्यक्त किया जाता है। गैर-मौद्रिक तुलना में ऐसे अनेक तत्वों पर विचार किया जाता है जिनकी मात्रा निर्धारित करना कठिन होता है, लेकिन जिनके पैसे का मूल्य निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये तत्व सरकार और आमलोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरणार्थ, परियोजना पूरा करने की गति, सेवा की गुणवत्ता, आपूर्ति की सुरक्षा और सेवाओं तक पहुंच जैसे समता मूलक मुद्दे।

पैसे का मूल्य निर्धारित करने के लिए कुछ ऐसे मानक तय करना आवश्यक होता है जिनके आधार पर निजी क्षेत्र के भागीदार के निष्पादन का मूल्यांकन किया जाए। इसके लिए अवधारणात्मक स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र के तुलनाकारी का निरूपण कर लिया जाता है। मान लिया जाता है कि इस तुलनाकारी के अंतर्गत बेहद कुशल बुनियादी ढांचे का न्यूनतम लागत तथा न्यूनतम समय में निर्माण किया गया है। अब इस मानदंड की तुलना में निजी भागीदार के निष्पादन के बारे में निर्णय किया जाता है।

उत्पादन विनिर्देश

अच्छी तरह तैयार की गई साझेदारी संविदा की सफलता की कुंजी यह है कि निजी क्षेत्र के भागीदारी से मांगा गया अंतिम परिणाम स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट हो तथा जहां कहीं संभव हो, उसकी मात्रा भी साफ-साफ वर्णित हो। इससे आगे पैदा होने वाले विवादों को कम करने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए, सड़क परियोजना की संविदाओं में खुरदरेपन का मान्य स्तर, प्रति किमी गड्ढों की संख्या, लेन-देन बंद करने की अधिकतम अवधि, नालों का रखरखाव आदि का उल्लेख होना चाहिए। दीर्घावधि प्रसंविदाओं की सफलतापूर्वक समाप्ति के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, बेहद उत्पादन विनिर्देशों को भुगतान प्रविधि के द्वारा वित्तीय प्रभाव दिया जाता है। इसके द्वारा भागीदारों के जोखिम और जिम्मेदारियों का आवंटन किया जाता है। भुगतान प्रविधि को वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी तथा सरल होना चाहिए।

जोखिम आवंटन

परियोजना के लिए वित्त सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि उससे जुड़े विभिन्न जोखिमों का खुलासा किया जाए और जो पक्ष जिस जोखिम से बेहतर तरीके से निबटने में समर्थ हो, उसे उक्त जोखिम आवंटित किया जाए। जोखिम आकलन में विशेष रूप से इस पर बल दिया जाए कि कौन सा पक्ष उस जोखिम का बेहतर प्रबंधन करने में सक्षम है, अथवा उक्त जोखिम से मिलजुल कर निबटना चाहिए। जोखिम के प्रारंभिक आवंटन से परियोजना के विशिष्ट स्वरूप तथा प्रत्येक पक्ष की अंतर्निहित शक्तियों और कमजोरियों का पता चलता है। निजी क्षेत्र को हस्तांरित जोखिम का स्तर प्रत्येक परियोजना में दूसरे से अलग होगा तथा उसका निर्धारण आवधिक समीक्षा प्रक्रिया और समझौते में आपसी संबंध विश्लेषण के आधार पर किया जाएगा। अधिकांश मामलों में आमतौर पर डिजाईन, निर्माण, प्रचालन और रखरखाव वित्त तथा राजस्व जोखिम निजी भागीदारी द्वारा उठाए जाते हैं जबकि सरकार कानूनी स्थिति अनूकूल बनाने के साथ-साथ संस्थागत एवं राजनितिक समर्थन प्रदान करती है।

प्रसंविदा का मानकीकरण

इसका लक्ष्य बुनियादी रूप से पिछले अनुभवों के आधार पर भावी समझौतों के लिए कुछ मानक निर्धारित करना होता है। प्रसंविदों का मानकीकरण विभिन्न क्षेत्रों में जोखिम के बंटवारे, वित्त तथा मूल्य निर्धारण जैसे मुद्दों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इससे समझौते में लगने वाले समय तथा लागत को कम करने में मदद मिलती है और सभी संबद्ध पक्ष ज्यादा वक्त लगाए बगैर अनेक मामलों में सहमत हो जाते हैं। कौन सा दृष्टिकोण किस क्षेत्र के अनुकूल है, इस पर अनेक अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों में जो एक बात सबने स्वीकार की है वह यह है कि जहां कहीं भी निष्पादन मानदंड तुलनात्मक रूप से सरल तथा उच्च स्तर के मानकीकरण के अधीन होते हैं वहां सार्वजनिक निजी साझेदारी अधिक सफल होती है। लेकिन यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि मानकीकरण की स्पष्ट सीमाएं होती हैं। क्योंकि अलग-अलग परियोजनाओं के अपने विशिष्ट अंतर तथा जोखिम होते हैं।

बोली लगाने की विधि

बोली लगाने की तैयारी पर आने वाली लागत को कम करने तथा चयन प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाने के लिए इसे क्रियान्वित करने वाली सरकारी एजेंसी को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। इसमें डिजाईन और रेखाचित्रों सहित निर्माण के विस्तृत मानक तथा विनिर्देश हों, प्रचालन और रखरखाव के सुपरिभाषित मानदंड हों। समझौते की अवधि में निजी भागीदार को इन मानकों का पालन करना होगा। निजी प्रचालक के चयन की प्रक्रिया खुली प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली लगाने की प्रक्रिया हो सकती है ताकि परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित तकनीकी कौशल तथा वित्तीय संसाधन वाले पक्ष का चयन किया जा सके। यह भी देखना होगा कि वह प्रयोक्ता को उसके पैसे के सर्वोत्तम मूल्य दे सके। प्राय: न्यूनतम लागत की बोली लगाने वाले को परियोजना सौंप दी जाती है। चूंकि वित्तीय मानदंड का आसानी से मूल्यांकन किया जा सकता है, इसलिए इससे वस्तुनिष्ठता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो जाती है।

सार्वजनिक-निजी क्षेत्र की साझेदारी के लाभ

सरकार को लाभ

- वित्तीय सीमाओं तथा बुनियादी ढांचे में लगने वाले भारी निवेश के मद्देनजर निजी क्षेत्र की भागीदारी से दुर्लभ बजटीय संसाधनों के उत्तोलन में मदद मिलती है।
- निर्मित परिसंपत्ति का स्वामित्व सरकार के पास बना रहता है।
- निजी क्षेत्र केवल वित्त ही नहीं, वरन नवीन तथा आधुनिक प्रबंधकीय, प्रशासकीय एवं

तकनीकी समर्थन भी प्रदान करता है।

- निर्माण संबंधी जोखिम, प्रचालन संबंधी जोखिम, राजस्व संबंधी जोखिम तथा वित्त संबंधी जोखिम निजी भागीदार को हस्तांतरित हो जाते हैं।
- सबसिडियों को अधिक कुशल, लक्षित तथा पारदर्शी बनाया जाता है।
- अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से ज्ञात होता है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से समय और लागत दोनों न्यूनतम स्तर पर बने रहते हैं।

निजी क्षेत्र के भागीदार को लाभ

- नीतिगत तथा संवैधानिक समर्थन के लिए सरकार की भागीदारी।
- सरकार को सहभागिता के परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, पर्यावरण संबंधी अनापत्तियां एवं अनुमोदन जैसे प्रमुख अवरोधों का शीघ्रतापूर्वक समाधान करने में मदद मिलती है।
- निजी कोष के द्वारा चालू परियोजना को कार्यक्षम बनाने के लिए सरकार 'कार्यक्षमता अंतराल कोष' पर विचार कर सकता है।
- सरकार के लिए भागीदारी तथा सस्ता कोष प्राप्त करना सरल हो जाता है।
- परियोजना की पूरी अवधि के दौरान सरकार की ओर से नीतिगत तथा प्रचालन एवं रखरखाव संबंधी सतत समर्थन।

लेकिन, इनसे अंततः लाभ प्रयोक्ताओं को ही होगा। जो उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी ढांचागत सेवाओं के समयबद्ध रूप से पूरा होने से बेहद लाभान्वित होंगे और उनके पैसे का मूल्य सुनिश्चित हो पाएगा।

सार्वजनिक-निजी क्षेत्र की साझेदारी के मुद्दे

- बोली लगाने की प्रक्रिया पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए।
- प्रयोक्ता प्रभार को सावधानीपूर्वक निर्धारित करना चाहिए तथा छूट की पूरी अवधि के दौरान उनकी आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए। इस क्रम में यह ध्यान रहे कि प्रयोक्ताओं में भुगतान करने की इच्छा अत्यल्प होती है।
- दिल्ली-नोएडा पुल के अनुभव के आधार पर एक दीर्घ प्रयोक्ता अधिगम आरेख तैयार किया जाना चाहिए।
- परियोजना सतत रूप से प्रयोक्ताओं के पैसे के मूल्य चुकाने के लिए तत्पर रहें।
- समाज, राजनीतिक प्रतिष्ठान, विशिष्ट प्रयोक्ता समूह जैसे हितधारियों के साथ प्रभावी संवाद हो। उन्हें परियोजना के चालु होने के पहले तथा बाद में इस संवाद में शामिल करना चाहिए तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप परियोजना में संशोधन किया जाना चाहिए।
- सार्वजनिक-निजी क्षेत्र की साझेदारी का अभिप्राय नीजिकरण नहीं है, इसके बावजूद सरकारी अधिकारियों को यदा-कदा परिसंपत्तियों पर नियंत्रण समाप्त करने के का भय होता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक नीजि साझेदारी से जनहित में वृद्धि हो, सरकारी क्षेत्र की भागीदारी की लागत तथा लाभों की सार्वजनिक क्षेत्र के विकल्पों से तुलना करते हुए विस्तृत समीक्षा की जानी चाहिए।
- निजी वित्त विवादस्पद होता है क्योंकि इससे सार्वजनिक प्राप्ति की यथास्थिति में उल्लेखनीय बदलाव आता है और विदेशी निवेश से यदि राष्ट्रवादी भावनाएं जाग्रत हो जाएं तो कई निहित स्वार्थ सक्रिय

Aspiring for M.E. or M.Tech from a prestigious institution?

BRILLIANT'S POSTAL COURSES FOR

GATE 2006

SUBJECTS OFFERED • Computer Science & Engg. • Information Technology • Electronics & Comm. Engg • Electrical Engg. • Instrumentation Engg. • Mechanical Engg. • Production and Industrial Engg. • Civil Engg. • Geology & Geophysics • Mathematics • Physics • Chemistry • Engg. Sc. (Engg. Maths, Electrical Sc., Materials Sc., Solid Mechanics, Fluid Mechanics, Thermodynamics) • Life Sc. (Chem., Biochem., Microbiology)

Two of Brilliant's students have secured the No.1 rank in GATE 2004.

With 69 ranks above the 99th Percentile and 461 ranks above the 90th Percentile, a whopping 648 of our students were successful in GATE 2004.

Aspiring for
Junior Research Fellowship?
Want to be a
University / College Lecturer?

Be guided by Brilliant Tutorials

CSIR-UGC NET
JRF/L EXAM
June & Dec '05

UGC NET
JRF/L EXAM
June & Dec '05

SUBJECTS OFFERED
• Chemical Sciences
• Mathematical Sciences
• Physical Sciences
• Life Sciences
The course is a comprehensive, extensively researched package covering your subject of specialisation. 8 sets of study material cover the syllabus thoroughly while a Doubt Letter Scheme allows you to clarify doubts with our professors.

SUBJECTS OFFERED
• Economics • Commerce
• History • English
The course covers all the requirements of Papers I, II, III(A) and III(B) of the subject of your specialisation. 8 sets of study material cover the syllabus thoroughly while a Doubt Letter Scheme allows you to clarify doubts with our professors.

AIEEE & BITSAT 2006

Your gateway to the National Institutes of Technology

All the Regional Engineering Colleges have been upgraded to National Institutes of Technology and accorded the status of Deemed Universities. And, admission to all of them, as well as to many other institutions of specialized engineering education, will be on the basis of the AIEEE [All India Engineering Entrance Examination].

BITSAT [Birla Institute of Technology and Science Admission Test]: BITS Pilani conduct a separate Online Test for admission to their Institutes at Pilani and Goa.

Who can equip you for success in these highly competitive exams, better than Brilliant Tutorials – a 30-year veteran who has helped produce thousands of winners and hundreds of top-rankers in competitive entrance exams all over India.

Course Highlights:

• 8 sets of lesson material and assignments • 3 Postal Tests in each subject • A ready-reference compendium of important formulae, equations and data in Maths, Physics and Chemistry • 4 National Sit-down Tests at 26 centres across the country • 4 Home-based Mock Test Papers • Doubt Letter Scheme

Admission open, write, call or fax for free prospectus.

BRILLIANT TUTORIALS

Box: 4996-YOH 12, Masilamani Street, T. Nagar, Chennai-600 017.
Ph: 24342099 (4 lines) Fax: 24343829 e-mail: enquiries@brilliant-tutorials.com

ADMISSION ALSO OPEN FOR THE FOLLOWING POSTAL COURSES FROM BRILLIANT
• IIT-JEE 2006, 2007 & beyond • MBBS Ent. 2006, 2007 & beyond
• MBA Ent. 2006 • MCA Ent. 2006 • IAS 2006 • ESE 2006
• GRE • TOEFL • BANKING • GEOLOGISTS' Exam. 2005

हो उठते हैं।

- सार्वजनिक-निजी साझेदारी के कई तरीके होते हैं जिनमें से प्रत्येक की अपनी ताकतें और कमजोरियां होती हैं। उनका सावधानी पूर्वक अध्ययन कर प्रयोग करना चाहिए।
- आरंभ में यदि राजनीतिक सहमति प्राप्त भी कर ली जाए, तो भी वह कमजोर होती है और उसे लगातार मजबूत बनाते रहना जरूरी होता है।
- भावी साझेदारियों को विशेष, रूप से जल क्षेत्र की साझेदारियों में नीचे से ऊपर बढ़नेवाला तरीका अपनाया जाना चाहिए ताकि उनमें स्थानीय पंचायतों और नगरपालिका का दखल रहे। ग्राहकों को परियोजना का साझेदार मानना चाहिए, न कि सेवाओं का मौन प्राप्तकर्ता।

भारत में सार्वजनिक-निजी साझेदारी के कुछ उदाहरण

जल एवं मलव्ययन क्षेत्र में साझेदारी

- तमिलनाडु जल निवेश कंपनी ने तमिलनाडु सरकार और आईएल एंड एफएस के बीच संयुक्त उद्यम बना कर न्यू तिरूपुर एरिया डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. स्थापित किया। तिरूपुर का यह उद्यम देश में निजी क्षेत्र में पहला जलापूर्ति कार्यक्रम का एसपीवी बना। इसकी कुल परियोजना लागत 1,000 करोड़ रुपये भी अधिक है जबकि इसमें सरकार का योगदान 55 करोड़ रुपये है। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकारी कोष को लगभग 20 गुणा उत्तोलन प्राप्त हुआ। परियोजना की जोखिम का बंटवारा अंतरराष्ट्रीय निजी एजेंसियों के अनुरूप क्षमता के आधार पर किया गया।
- ऐसी ही पहल विज़ाग में की गई है। वहां 205 किमी लंबी नहर के पुनरोद्धार तथा उसकी फीडर नहर के क्षमतावर्द्धन का काम लिया गया। विजाग परियोजना से मौजूदा परिसंपत्तियों की कुशलता बढ़ाने, उनका मूल्य बढ़ाने तथा सेवाओं का दायरा व्यापक करने में सार्वजनिक-निजी साझेदारी की सामर्थ्य का प्रदर्शन होता है।

सड़क क्षेत्र में साझेदारी

- सड़क क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी साझेदारी 1992 में मउ पीतमपुर मार्ग चालू होने के साथ शुरू हुई।
- आईएलएंडएफएस तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने 1994 में दिल्ली-नोएडा पुल विकसित करने के लिए एक एसपीबी स्थापित किया।
- 95 किमी लंबी छह लेन वाली कंक्रीट की मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे को 40 करोड़ अमरीकी डॉलर की लागत से बनाओ-चलाओ-हस्तांतरित करो आधार पर आरंभ किया गया।
- मध्य प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम बनाओ-चलाओ-हस्तांतरित करो के आधार पर एक एक्सप्रेस-वे विकास कार्यक्रम चला रहा है। इसके अंतर्गत 21 किमी लंबी सड़क के निर्माण के लिए 15 परियोजनाएं आवंटित की जा चुकी हैं।
- 1999 में स्थापित कर्नाटक सड़क विकास निगम लि. को कर्नाटक में सड़कों का विकास और रखरखाव करने तथा बनाओ-चलाओ-हस्तांरित करो आधार पर निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने का अधिकार प्राप्त है।
- बनाओ-चलाओ-हस्तांतरित करो आधार पर गुजरात में अनेक सड़क परियोजनाएं शुरू की गई हैं।
- तमिलनाडु में तमिलनाडु सड़क विकास कं. लि. का गठन तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम तथा आईएल एंड एफएस

निर्माण, संचालन हस्तांतरण विधि (बीओटी) से बुनियादी ढांचे का मार्ग प्रशस्त होता है - प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री ने कहा है कि 1990 के दशक में प्रथम चरण के सुधार कार्यक्रम बहुत आसान थे क्योंकि वे ज्यादातर विदेश व्यापार के उदारीकरण और औद्योगिक लाइसेसिंग हटाने से संबंधित थे। उन्होंने कहा कि अब हम ऐसी स्थिति में हैं जब प्रमुख बाधाएं भौतिक के साथ साथ मानवीय ढांचागत विकास से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ज्यादा पेचीदा क्षेत्र है और इसका हल इतना आसान नहीं है।

डा. मनमोहन सिंह पंजाब, हरियाणा और दिल्ली वाणिज्य और उद्योग मंडल के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। डा. सिंह ने कहा कि अब ग्रामीण विकास, लघु उद्योगों और कृषि के क्षेत्र में ढांचागत विकास में आने वाली अड़चनों को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे में आने वाली बाधाओं को दूर करना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य में कुछेक को छोड़कर सभी सड़क विकास परियोजनाएं निर्माण, संचालन और हस्तांरण विधि (बीटीओ) पर आधारित होंगी। इससे निजी पूंजीनिवेश के लिए नये अवसर खुलेंगे। आने वाले वर्षों में 7-8 प्रतिशत की कुल आर्थिक विकास दर हासिल करने के लिए पहले सड़कों का त्वरित विकास सुनिश्चित करना होगा। डा. मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत पूर्ण विकास का लक्ष्य हासिल करने के करीब पहुंच गया है और सरकार ऐसी नीतियां लागू करने के प्रति वचनबद्ध है जिससे विकास का यह लक्ष्य प्राप्त करने हेतु जरूरी माहौल बने।

उन्होंने कहा कि वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम ढांचागत परियोजनाओं के लिए पूंजीनिवेश उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किए जा रहे 'विशेष उद्देश्यीय वाहक' (एसपीवी) व्यवस्था के संबंध में ब्यौरा उपलब्ध कराएंगे। निजी माल डिब्बों के बारे में उन्होंने कहा कि विशेष माल गाड़ियों की शुरुआत, ढांचागत विकास की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। नगर विमानन क्षेत्र में उत्प्लावकता का जिक्र करते हुए डा. सिंह ने कहा कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और यदि यह गति बनी रही तो हम बुनियादी ढांचागत समस्याओं का हल निकालने में जरूर कामयाब होंगे। ❑

(राकेशरेणु सहायक संपादक (हिंदी) एवं मनोज्ञान आर.पाल, उप संपादक (अंग्रेजी)

के बीच संयुक्त उद्यम के रूप किया गया था जो सार्वजनिक-निजी साझेदारी प्रारूप के अनुरूप सड़क क्षेत्र में पहलों को विकसित करता है।

- दसवीं योजना में भारतीय राष्ट्रीय उच्चपथ प्राधिकरण को सक्रिय बनाया गया और निजी भागीदारी से राष्ट्रीय उच्चपथ विकास परियोजना की घोषणा की गई।

रेल में साझेदारी

रेल परियोजना में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए रेल विकास निगम लि. नामक एक एसपीवी का निर्माण किया गया। रेल क्षेत्र की कुछ साझेदारियां इस प्रकार हैं:

- सुंदर नगर-पीपा भाव बड़ी लाईन के विकास के लिए पीपा भाव रेल निगम।
- हासन-मंगलौर रेल विकास निगम (गेज परिवर्तन हेतु)।
- पालनपुर तथा गांधीधाम के बीच गेज परिवर्तन हेतु कच्छ रेल कंपनी।

बंदरगाह में साझेदारी

जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह न्यास ने 1997 में पीएंडओ, आस्ट्रेलिया के साथ दो बर्थ वाले कंटेनर टर्मिनल के विकास के लिए 30 साल के लिए बनाओ-चलाओ-हस्तांतरित करो आधार वाले समझौते पर हस्ताक्षर किया। पी एंड ओ ने समय से पहले यह परियोजना पूरी कर ली तथा 1999 में इसका प्रचालन आरंभ कर दिया। नए टर्मिनल का नाम नवसेवा अंतरराष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल रखा गया है।

हवाई अड्डों में साझेदारी

भारतीय विमानपत्तनन प्राधिकरण संशोधन, विधेयक, 2003 में नवीन तथा मौजूदा हवाई अड्डों में निजी निवेश के लिए वैधानिक ढांचे का प्रावधान किया गया है। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद का निर्माण सार्वजनिक-निजी साझेदारी के प्रारूप के अनुरूप किया जा रहा है।

ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी

गुजरात में बृहत विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए टॉरेंटो प्राईवेट लि. अहमदाबाद बिजली कं. तथा सूरत बिजली कं. ने एसपीवी के रूप में दी टॉरेंट पावर जेनरेशन लि. की स्थापना की है।

निष्कर्ष

भारत जैसे विकासशील देशों में वित्त व्यवस्था के लिए बड़े पैमाने पर कोष की कमी के मद्देनजर बुनियादी ढांचे के विकास में सार्वजनिक-निजी क्षेत्र साझेदारी की सकारात्मक विशेषताएं अधिक आकर्षक लगने लगती हैं। लेकिन बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का बड़े पैमाने पर प्रावधान करना ही एकमात्र समाधान नहीं है। इन्हें सार्वजनिक सुविधाओं के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले अनेक विकल्पों में से एक मानना चाहिए। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि सार्वजनिक-निजी साझेदारी कुछ क्षेत्र में अधिक सफल हो सकती है और दूसरों में कम। इस पर जोर देने के दौरान पारंपरिक सार्वजनिक-सार्वजनिक प्रारूप जैसे अन्य विकल्पों को छोड़ नहीं देना चाहिए।

भारत में बुनियादी ढांचे के लिए वित्त हेतु सार्वजनिक-निजी साझेदारी जैसे नए और नवाचारी कार्यक्रम तैयार करने के साथ-साथ सरकार को निम्नांकित पर भी विचार करना चाहिए:

- राजस्व हानि कम करने के लिए वित्तीय सुधार करें पूंजीगत व्यय के लिए वित्त व्यवस्था की गुंजाइश पैदा करें। सतत वित्तीय सुधार से धीरे-धीरे ब्याज दर नमनीयता बढ़ेगी।
- सार्वजनिक क्षेत्र की संबद्ध इकाइयों का वित्तीय निष्पादन बेहतर बनाने से आंतरिक अधिशेष में वृद्धि होगी। इसका उपयोग बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश के लिए किया जा सकेगा। दूरसंचार क्षेत्र के अनुभव से यह प्रकट होता है कि उचित दरों के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण के लिए वित्त जुटाना संभव है। इस सब का इस्तेमाल ऊर्जा, बंदरगाह तथा रेल क्षेत्र में भी लाभकारी तरीके से किया जा सकता है। सड़क क्षेत्र में भी मार्ग कर संग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, डीजल तथा पेट्रोल पर प्रभार लगाकर वित्त व्यवस्था की जा सकती है। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि दुर्लभ संसाधनों की कम कीमतों के कारण वे समाप्त हो रहे हैं। समय आ गया है कि लोग यह महसूस कर लें कि नि:शुल्क पानी, नि:शुल्क बिजली, नि:शुल्क अथवा सब्सिडी युक्त परिवहन आदि की अब कोई गुंजाइश नहीं है।
- लेकिन बुनियादी ढांचे में क्षमता-विस्तार की सार्वजनिक क्षेत्र की सामर्थ्य को अवरुद्ध करनेवाली एकमात्र समस्या केवल संसाधनों की कमी नहीं है। राज्य विद्युत बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट तथा लोक कार्य विभागों जैसी विभिन्न सरकारी एजेंसियों में अन्य अनेक गंभीर संगठनात्मक कमजोरियां हैं। संस्थागत सुधार का एक संभव तरीका यह है कि जहां कहीं गुंजाइश हो, इन एजेंसियों का निगमों की तर्ज पर पुनर्गठन किया जाए, सरकारी विभागों की तर्ज पर नहीं। इससे व्यावसायिक संस्कृति का विकास होगा तथा बेहतर वित्तीय और पेशेवराना प्रबंधन होगा।
- भारत में बुनियादी ढांचे के वित्त के एक प्रमुख स्रोत के रूप मे निजी निवेश के महत्व को स्वीकार करते हुए सरकारी नीतियों में स्पष्टता तथा कार्यविधियों में पारदर्शिता होनी चाहिए। यही कार्यविधियां निजी निवेशकर्ता तथा सरकारी प्राधिकारियों के बीच अंतरफलक का काम करती हैं। दर-संरचना ऐसी हो कि उससे निवेशक लाभ प्राप्त करने के बारे में आश्वस्त हो सकें। सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश शुरू करने के लिए कदम उठाने चाहिए। आखिर में, निजी निवेशकों के साथ उचित बर्ताव के लिए गठित स्वतंत्र नियामक एजेंसियों को सही अर्थों में स्वतंत्र बनाना चाहिए। रियायती समझौतों का प्रारूप विकसित करने से भी निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।
- भारत में एक स्वस्थ दीर्घावधि ऋण बाजार का विकास करने के लिए बीमा तथा पेंशन के क्षेत्र में सुधार आरंभ करना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि दीर्घावधि ऋण के लिए इनका स्वरूप अनुकूल होता है। विकास वित्त संस्थानों का उन्नयन इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि वे वित्त व्यवस्था से पहले परियोजना विकास के आरंभिक चरण में जोखिम पूंजी तथा तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान कर सकते हैं। पूंजी बाजार में सुधार की अभी भारी संभावना है।
- बुनियादी ढांचे के वित्त के लिए विदेशी मुद्रा कोष का उपयोग करने के हालिया दृष्टिकोण पर अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। ❑

(लेखिका योजना आयोग के चेन्नई स्थित कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी हैं)

चामत्कारिक प्रगति का संसार : दूरसंचार

○ विजय ठाकुर

यदि कोई ऐसा क्षेत्र है जिसके तीव्र विकास ने देश के योजनाकारों को भी अचंभित कर दिया हो, तो वह भारतीय दूरसंचार का क्षेत्र है। इसने सभी सीमाओं को तोड़ते हुए, पिछले सारे रिकार्डों को ध्वस्त करते हुए विश्व का सबसे ऊंचा विकास दर दर्ज किया है। दूरसंचार क्षेत्र के विशेषज्ञों की मानें तो यह विकास गति अभी थमने वाली नहीं है, इसके कम से कम एक दशक तक और जारी रहने की संभावना है। उनका आकलन है कि 2007 तक भारत का टेलीफोन नेटवर्क 25 करोड़ की संख्या का पार कर जाएगा। यदि पूर्व की भांति यह लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर ली जाए तो किसी को भी आश्चर्य नहीं होगा।

जितनी तेजी से इस क्षेत्र मे संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बहुत कम क्षेत्रों मे उतनी तेज गति से परिवर्तन हो पाया है। दूरसंचार क्षेत्र में इस आशातीत परिवर्तन से एक ऐसा विशाल और अछूता बाजार उभरा है जो समुचे देश और खासकर ग्रामीण इलाकों पर आने वाले वर्षों में छा जाएगा। अगले दो वर्षों में इस क्षेत्र मे 1,25,000 करोड़ रुपये का निवेश (इसमें टेलीफोन, ब्रॉडबैंड तथा अन्य संरचनात्मक विकास में सरकारी और गैर सरकारी निवेश शामिल हैं) होने का अनुमान है। लेकिन यह तो अभी शुरुआत है। टेलीफोन के बाद अगला नंबर ब्रांडबैंड का है जिसमें विकास की गति अभी भी शिथिल है। भारत में पर्सनल कंप्यूटर, ब्रांडबैंड और इंटरनेट का प्रसार विश्वस्तर से अभी काफी पीछे है। लेकिन दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास तथा जिला स्तर पर बीपीओ उद्योग के उदय के मद्देनजर ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड तथ इंटरनेट की पहुंच आसन्न है। और, संभवत: ब्रॉडबैंड के विकास की गति टेलीफोन की विकास गति से भी तीव्र हो।

सरकार ने 2010 तक ब्रॉडबैंड के 2 करोड़ तथा इंटरनेट के 4 करोड़ ग्राहकों का अनुमान लगाया है। मौजूदा विकास दर के आलोक में यह विकास दर हासिल कर पाना मुश्किल लगता है, लेकिन दूरसंचार उद्योग को उम्मीद है कि इस क्षेत्र में भी वही चमत्कार होगा जो मोबाइल टेलीफोन के क्षेत्र में हो चुका है।

दूरसंचार

भारत का दूरसंचार नेटवर्क संसार के सबसे बड़े नेटवर्कों में एक है। इसमें 9.5 करोड़ से भी अधिक कनेक्शन हैं तथा हर महीने लगभग 20 लाख नए कनेक्शन और जुड़ रहे है। आरंभ में यह नेटवर्क 21 प्रतिशत की वार्षिक दर से प्रगति कर रहा था, लेकिन पिछले दो सालों से इसकी विकास दर 40 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है जो दुनियाभर में अबतक की सबसे ऊंची विकास दर है।

इस विकास की परख इस तथ्य के आलोक में की जा सकती है कि 1947 में आजादी के समय भारत में कुल 80 हजार टेलीफोन कनेक्शन थे जिनमें अगले 34 वर्षों में केवल बीस लाख कनेक्शनों का बढ़ोतरी हो पाई जबकि अब इस क्षेत्र में हर महीने लगभग 20 लाख कनेक्शनों की वृद्धि हो रही है, अर्थात हर महीने लगभग उतने कनेक्शन जुड़ रहे हैं। जितने स्वतंत्रता के बाद के 34 वषो " की अवधि में जुड़ पाए थे।

1947 में टेलीफोन घनत्व (100 व्यक्तियों पर टेलीफोनों की उपलब्धता) 0.02 था जो अब नौ पर पहुंच रहा है। यह लगभग 450 गुणा वृद्धि है। 1981 तक इसके विकास की गति बहुत तेज नहीं थी क्योंकि आजादी के उपरांत पहले 34 वर्षों में इसमें मात्र 20.5 लाख कनेक्शन जुड़ पाए। इसके बाद 1995 तक विकास की गति ने तेजी पकड़ ली। किंतु असल विकास 1995 से मोबाइल और टेलीफोन के क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश के बाद आरंभ हुआ।

नई दूरसंचार नीति, 1999 की घोषणा से वर्ष 2000 से इसमें और तेजी आई। इन नई नीति के परिणामस्वरुप कॉल दरों में कमी आई। इसके बाद में 2003-05 की अवधि में इस क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति हुई और टेलीफोन कनेक्शन मार्च 2003 की 5,462 करोड़ की संख्या से बढ़कर जनवरी 2005 में 9.5 करोड़ हो गए। अर्थात दो वर्ष से कम की अवधि में 4.1 करोड़ नए टेलीफोन कनेक्शन जोड़े गए।

केवल 2003-04 में ही 21.72 टेलीफोन कनेक्शन जोड़े गए जो 1999 तक स्थापित कुल टेलीफोनों की संख्या से अधिक है। मोबाइल फोन को एक समय उच्च मध्य वर्ग तथा विलासिता की वस्तु माना जाता था। लेकिन इसने समाज के निचले तबके में भी अपनी जगह बना ली तथा छोटे उद्यमियों के व्यापार को आगे बढ़ाने के वाली अनिवार्यत: वस्तु बन गया। मोबाइल फोन के बारे में दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों तथा इसकी अल्प लागत के कारण गत अक्तूबर में देश में फिक्स लाइनों की तुलना में मोबाइल फोनों की कुल संख्या अधिक हो गई है। यही नहीं, दोनों के बीच की दूरी तेजी से बढ़ती जा रही है।

ग्रामीण टेलीफोन

यह सही है कि दूरसंचार क्षेत्र में अनुमानित लक्ष्यों से अधिक तेज गति से वृद्धि हो रही है, बावजूद इसके ग्रामीण क्षेत्रों में इसके तीव्र विकास की जरूरत है। क्योंकि आज भी चार

RAO IAS
LUCKNOW

Director - Anshuman Dwivedi

❖Pre-Cum-Mains & Mains Batch from 24th May'05

❖Hindi/English Medium

❖Boys & Girls Hostel Available

2 years advance batch, with foundation course basically for under graduates

Subjects:

History : Anshuman Dwivedi (Author : हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति) & Ved Nidhi Dwivedi

Sociology: Pawan Mishra

Pol. Science : Brijesh Shukla

Economics : Dharmendra Singh

Zoology : Subhash Tripathi

Geography : Anurag Pathak

Psychology : Alpana Rastogi & Archana Shukla

Pub. Ad. : Nagendra Pal Singh, Ved Nidhi Dwivedi & others

Philosophy (only for Mains) : D. Singh & Brijesh Shukla

भाषा विज्ञान के लिए 25 दिन का विशेष पैकेज

G.S. : A team of 12 experts from Delhi, Allahabad and Lucknow

U.G.C. (Net) Batches also available

विशेषताएँ

- ❖ नियमित टेस्ट
- ❖ विचार–विनिमय परक पठन–पाठन
- ❖ विभिन्न आयोगों द्वारा विगत वर्षों में कराई गयी परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों पर चर्चा और उनका हल।
- ❖ राव आई. ए. एस. संस्थान में ज्ञान की वर्तमान प्यास को सिर्फ शमित ही नहीं किया जाता है वरन् नित–नूतन नये ज्ञान की प्यास जगाई भी जाती है जिससे विद्यार्थी ज्ञान की नयी ऊँचाईयों को छूता रहे।
- ❖ RAO IAS संस्थान का वातावरण शांत, अनुशासित और विचारोत्तेजक है। पठन–पाठन के लिए अनुकूल और उपयुक्त। छिछले विचार और कृत्य अपवर्जित हैं। अध्यापक और विद्यार्थी के बीच मशीनी रिश्ता नहीं है। शिक्षणकार्य दो जीवित–स्पंदित कियाशील मानव इकाईयों के बीच घटित होने वाला व्यापार है और यहाँ इस बात की समुचित चिंता की जाती है। गतानुगतिका के स्थान पर विद्यार्थी की मौलिक प्रतिभा को उभारना हमारा ध्येय, संकल्प और व्रत है।

हमारे लिए भाषा सिर्फ विभिन्न ध्वनि आवेगों का संयोग मात्र नहीं है। एक जीवित स्पंदन है। भाषिक संस्कार देना हमारा उद्देश्य है। अच्छे अंक पाने के लिए भाषा का त्रुटिहीन होना आवश्यक है। वर्तनी गत दोष और व्याकरणिक अशुद्धियाँ अच्छे से अच्छे विद्यार्थी का भविष्य खराब कर देती है। विद्यार्थी इसके प्रति बहुत असजग है। ऐसा हम अनुभव से जानते हैं। हम इसका परिहार करने में आपकी मदद करते हैं।

Add.20, Ravindra Garden, Sector-E, Aliganj, Lucknow. Ph.: 0522 - 2331548, 9335247918

HO. : 14/1 Stainley Road opposite Lok Seva Aayog Allahabad, Ph.: 0532-2601624

में से तीन गांवों में दूरवर्ती टेलीफोन सेवा उपलब्ध नहीं है तथा भारत के केवल 5 प्रतिशत गांवों में दूरवर्ती टेलीफोन सेवा उपलब्ध है। गांवों में टेलीफोन सुविधा प्रमुख रूप से सरकारी स्वामित्व वाला भारत संचार निगम लि. उपलब्ध कराता है। बहुत थोड़े से निजी कंपनियों ने ही इस दिशा में कदम बढ़ाया है। लेकिन शहरी बाजार में आ रहे ठहराव के कारण अब निजी कंपनियां अपनी विकास गति बनाए रखने के लिए गांवों में टेलीफोन संचार गतिविधियों में संलग्न होने के लिए विवश हो रही हैं। दूरसंचार उपकरणों की कीमत में आई भारी कमी से गांवों में संचार गतिविधियां फैलाना मुनाफे का धंधा हो गया है। माना जा रहा है कि अगले पांच वर्षों में ग्रामीण दूरसंचार में निवेश में भारी वृद्धि होगी। वर्तमान समय में गांवों में टेलीफोन का प्रसार शहरों में इसके प्रसार का दसवां हिस्सा ही है। वायरलेस टेलीफोन सुविधा की कम होती लागत से कम टेलीफोन प्रचालकों के लिए यह कार्य और आसान हो गया है।

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

हलांकि विगत वर्षों में यहां टेलीफोन घनत्व में तीव्र वृद्धि हुई है, इसके बावजूद भारत अब भी ब्राजील और चीन जैसे देशों से पीछे है जहां टेलीफोन घनत्व 42 से अधिक है। इनके समकक्ष पहुंचने के लिए सरकारी नीति के साथ-साथ नवीन प्रौद्योगिकी, नई कंपनियों के प्रवेश तथा सस्ती टेलीफोन सेवा के संदर्भ में तीव्र प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता है।

अधिकतर यूरोपीय देशों में टेलीफोन घनत्व 100 से भी ऊपर है जबकि भारत अभी दहाई अंकों में भी नहीं पहुंच पाया है। विकसित देशों की तो छोड़ें, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे छोटे देशों में भी टेलीफोन घनत्व भारत की तुलना में अधिक है।

विश्व का औसत टेलीफोन घनत्व 36 के आस-पास है जिसका अभिप्राय यह हुआ कि विश्व औसत तक पहुंचाने के लिए भारत को अपना टेलीफोन घनत्व चार गुणा बढ़ाना होगा। इसके साथ ही, विश्व औसत तक पहुंचने के लिए भारत को अगले एक दशक तक अपनी मौजूदा विकासदर बनाए रखनी होगी।

दूरसंचार में निजी क्षेत्र

इस तथ्य से कोई इंकार नहीं कर सकता कि दूरसंचार के क्षेत्र में तीव्र प्रगति इसे निजी क्षेत्र के लिए खोले जाने के बाद ही आरंभ हुई। दूरसंचार क्षेत्र की प्रगति मुख्यत: मोबाइल, टेलीफोन के कारण हुई।

निश्चित रूप से दूरसंचार उद्योग में प्रगति में निजी क्षेत्र ने प्रमुख भूमिका निभाई है। देश के कुल टेलीफोन का 47 प्रतिशत निजी क्षेत्र में है। पिछले वित्त वर्ष (2004-05) के पहले दस महीनों के दौरान हुई विस्तार का 77 प्रतिशत निजी क्षेत्र में हुआ। सरकार द्वारा लाईसेंसिंग प्रक्रिया को एकीकृत करने तथा 74 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दिए जाने के बाद अब इस प्रवृत्ति के जारी रहने की संभावना है।

तालिका

दूरसंचार राजस्व एवं लाभ

वित्तीय वर्ष	प्रचालन राजस्व (करोड़ रुपये में)	शुद्ध लाभ (करोड़ रुपये में)
1980-81	657.80	171.18
1984-85	1242.63	371.77
1989-90	2777.48	1150.44
1994-95	7653.72	3985.71
1999-2000	18,628.59	11975.05

दूरसंचार क्षेत्र में प्रमुख नीतिगत पहल

- 14 अक्तूबर, 2004 को ब्रॉडबैंड नीति की घोषणा की गई।
- अगस्त, 2004 से 2.4 गीगाहाटर्ज बैंड वाले अल्पशक्ति उपकरणों के परिसर के भीतर उपयोग को लाईसेंसमुक्त किया गया।
- अप्रैल 2004 में यूएएस के लाईसेंस शुल्क को 2 प्रतिशत कम कर इसे 6-10 प्रतिशत की सीमा में लाया गया जबकि सीएमटी के लिए लाइसेंस शुल्क 8-12 प्रतिशत की सीमा में ही है।
- एनएलडीएस लाइसेंस के संदर्भ में निष्पादन बैंक गारंटी को जून 2004 में प्रत्येक चरण के लिए 100 करोड़ रुपये से कम कर 50 करोड़ किया गया।
- संरचना प्रदाता-II के लिए लाईसेंस को जून 2004 में कम करके एजीआर के 15 प्रतिशत से 6 प्रतिशत किया गया।

निजी अंतिम मील संपर्क संस्थापित करने के लिए आईएसपीज को जमीन के अंदर ताम्र तार के प्रयोग की अनुमति दी गई है।

- बजट 2004-05 में :
  - 31 मई, 2004 के बाद आरंभ होने वाली कंपनियों को धारा 80-I ए के तहत लाभ प्रदान किया गया।
  - एकीकृत सेवा प्रदाताओं के मोबाइल स्वीचिंग केंद्रों को ऑप्टिकल फाईबर केबल तथा ऑप्टिकल फाईबर के लिए जरूरी कच्चे माल पर सीमा शुल्क में छूट दी गई।
- आई पी-II वर्ग के लिए बैंक गारंटी को मार्च 2004 में 100 करोड़ रुपये से कम कर 5 करोड़ रुपये किया गया।
- आटोमेटेड स्पेक्ट्रम प्रबंधन प्रणाली ने काम आरंभ किया।
- सितंबर 2003 से फरवरी 2004 के बीच राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित किए गए।
- जनवरी 2004 में परिमंडल के भीतर एकीकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।
- एकीकृत अभिगम सेवा व्यवस्था (यूएसएल) आरंभ होने के उपरांत सभी बुनियादी सेवा लाईसेंसधारियों ने इस व्यवस्था की अंगीकार कर लिया है।

एक ऐसी संस्था जो कम समय में ही अपने ड्रीम टीम द्वारा सफलता का पर्याय बना

सा० अध्ययन → आर० कुमार एवं टीम (दिल्ली)
इतिहास → नीरज श्रीवास्तव
समाजशास्त्र → डा० एस०आर० सिंह (दिल्ली)
राजनीति विज्ञान → राजीव रंजन मिश्रा एवं धर्मेन्द्र चौबे
दर्शनशास्त्र → कौशलेन्द्र तिवारी (K. Tiwari)

निःशुल्क कार्यशाला	निःशुल्क कार्यशाला	निःशुल्क कार्यशाला	निःशुल्क कार्यशाला	निःशुल्क कार्यशाला
11 जून 9 बजे	15 जून सायं 5 बजे	16 जून सायं 5 बजे	17 जून सुबह 9 बजे	17 जून सायं 4.30 बजे
सा0 अध्ययन	इतिहास	समाज शास्त्र	राजनीति शास्त्र	दर्शनशास्त्र

- सूचना एवं प्रौद्योगिकी
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- भारतीय राज्यव्यवस्था
- भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आन्दोलन

R. Kumar

भारत एवं विश्व (भूगोल) → **A. Shekhar** (BPSC 1st Topper)

मानसिक योग्यता एवं सांख्यिकी
समसामयिकी एवं अन्तराष्ट्रीय घटनाक्रम एवं सामाजिक मुद्दे → **K. Tiwari**

आवासीय सुविधा एवं पत्राचार पाठ्यक्रम उपलब्ध है।

MIMANSA IAS Academy

74ई, लाउदर रोड, मेडिकल चौराहा (निकट जैन अस्पताल)
फोन : 09335150414, 09335142369, 09415212970

प्रवेश प्रारम्भ नामांकन जारी

आर्थिक सर्वेक्षण की दृष्टि में बुनियादी ढांचा

इस पर व्यापक मतैक्य है कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि और गरीबी उन्मूलन पर आधारभूत ढांचे के सुधार का बहुत प्रभाव पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय अनुभव यह बतलाता है कि उचित आधारभूत नीति ढांचे को निश्चित करने में कई जटिल समस्याएं आती हैं। निजी क्षेत्र को समुचित ढंग से निवेश करने के लिए उचित प्रोत्साहन देने तथा साथ ही साथ उन्हें एकाधिकार के फायदे लेने से रोकने के लिए प्रोत्साहनों के सावधानीपूर्वक अंशांकन के साथ-साथ सम्यक नियंत्रण और संतुलन की आवश्यकता है। नियमों का एक ढांचा स्थापित करना और राज्य की स्वेच्छाचारी शक्तियों पर अंकुश लगाना इसका एक प्रमुख भाग है, जिससे निजी क्षेत्र को इन परियोजनाओं की दशकों पुराने अनुभव को प्रयोग में लाने के लिए आत्मविश्वास मिले।

सबसे महत्वपूर्ण सफलता दूरसंचार के क्षेत्र में दृष्टिगोचर होती हैं। टेली-घनत्व में नाटकीय वृद्धि हुई है, और पूरा उद्योग ही निजी क्षेत्र के आगमन से सामने आया है, वीएसएनएल के साथ ही निजीकरण प्रारंभ हो गया है और नई प्रौद्योगिकियों का आगमन हुआ है। दूरसंचार में प्रतिस्पर्धा से लाभ प्राप्त हुए हैं। यह अर्थव्यवस्था के अधिकतर आधारभूत संरचना के क्षेत्रों के लिए आदर्श हो सकता है। भविष्य की ओर ध्यान देते हुए, टेलिकॉम क्षेत्र कई निजी फर्मों के मध्य सतत प्रतिस्पर्धा को जन्म देगा, जिसमें प्रतिस्पर्धा के पक्ष में टीआरएआई नीतियों के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। वर्ष 2004 के अंत में ब्रॉडबैंड मूल्यों में भारी गिरावट, ब्रॉडबैंड दूरसंचार क्षेत्र के पर्याप्त विस्तार का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। साधारण वॉइस टेलिफोनी की तुलना में अर्थव्यवस्था पर इसका और भी अधिक प्रभाव पड़ सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल के लिए प्रयोग जाने वाली राज्य चालित योजना दृष्टिकोण के विस्तार को कम करना, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें नई नीतियों को प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है।

सड़कों के क्षेत्र में स्वर्ण चतुर्भुज के महत्वपूर्ण भाग पूरे हो चुके हैं, उन्होंने देश में उत्पादन की वृद्धि में योगदान देना शुरू कर दिया है। इसके लिए पूरे किए जा चुके हिस्सों में निर्माण से हटकर गलियारा प्रबंधन पर ध्यान दिया जा रहा है। अर्थात ज्यादा से ज्यादा लाभ तथा विश्वस्तरीय सड़क सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों का सर्वोत्तम उपयोग करना। साथ ही साथ एक सतत प्रतिस्पर्धा-संचालित प्रक्रिया की आवश्यकता है ताकि घनी आवाजाही वाले चार लेन राजमार्गों का एक्सप्रेस-वे के रूप में उन्नयन किया जा सके और मुंबई से कोलकाता के बीच राजमार्ग जैसे नए संपर्कों के निर्माण का कार्य किया जा सके।

पत्तन क्षेत्र में नए तरह के अनुबंधों के द्वारा दक्षता मानदंडों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इसे अंतर्पत्तन तथा अंत:पत्तन प्रतिस्पर्धा के उत्साहशील स्तरों से लाभ प्राप्त हुआ है। हालांकि, जैसा कि हाल ही में जेएनपीटी की समस्याओं से पता चलता है, एक समुचित नीतिगत ढांचे के निर्माण के लिए काफी कार्य किये जाने आवश्यक हैं। इससे पत्तनों के रेल और सड़क मार्गों से पत्तन संपर्क तथा निष्पादन मानदंडों और मूल्यों पर अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क के प्रश्नों के नए सिरे से पुनरीक्षण की आवश्यकता उठती है। भारत को अंतरराष्ट्रीय व्यापार की उच्च वृद्धि एक भावी तरीके से

दिल्ली में निजीकरण का अनुभव

दिल्ली में विद्युत वितरण का जुलाई 2002 में निजीकरण किया गया था। कार्य-विवरण ढांचे का प्रमुख केंद्र बिंदु बिजली की चोरी में कमी लाना था। निजीकरण से पूर्व, सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानि का स्तर 50.7 प्रतिशत था। निजी वितरण कंपनियों के लिए पांच वर्ष की अवधि के दौरान 17 प्रतिशत की हानि में कटौती की कार्य योजना निर्धारित की गई। इन निजी कंपनियों द्वारा इन लक्ष्यों को समय से पूर्व प्राप्त कर लिए जाने के लिए उनके समक्ष आकर्षक प्रोत्साहन है क्योंकि हानि में कमी को उपभोक्ताओं और वितरण कंपनियों के बीच बराबर बांटा जाएगा। दिल्ली में बिजली की कमी 2002-03 में 1.9 प्रतिशत से घटकर 2003-04 में 1.4 प्रतिशत रह गई है। बिजली उपलब्धता के सूचकांक में भी सुधार हुआ है।

मानदंड	जुलाई 2002 को			2003-04			2004-05(*)		
	बीआरपीएल	बीवाईपीएल	एनडीपीएल	बीआरपीएल	बीवाईपीएल	एनडीपीएल	बीआरपीएल	बीवाईपीएल	एनडीपीएल
विश्वसनीयता सूचकांक (%)	96.98	96.46	98.5	उ.न.	उ.न.	99.57	98.84	98.64	99.64

(*)-अक्तूबर 2004 तक

संक्षिप्ताक्षर:

बीआरपीएल : बीएसई एस राजधानी पावन लिमिटेड

बीवाईपीएल : बीएसई एस यमुना पावर लि.

एनडीपीएल : नार्थ दिल्ली पावर लि.

आधारभूत क्षेत्रों में विकास दर की प्रवृत्तियां (प्रतिशत में)								
							अप्रैल-दिसंबर	
	मद	इकाई	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2003-04	2005-05
1.	ऊर्जा	मिलियन टन	3.5	4.2	4.6	5.1	3.9	6.8
2.	उत्पादित बिजली (केवल उपयोगिताएं)	बिलियन किवा.	3.9	3.1	3.2	5.0	3.4	6.5
	(क) पनबिजली	"	-7.6	-0.7	-13.7	15.6	10.5	17.6
	(ख) तापीय (नाभिकीय सहित)	"	7.4	2.5	6.2	3.5	2.4	4.7
3.	पेट्रोलियम							
	(क) कच्चा तेल उत्पादन	मिलियन टन	1.5	-1.2	3.2	1.0	-0.5	2.9
	(ख) शोधनशाला उत्पाद	"	20.3	3.7	4.9	8.2	7.2	6.7
II.	इस्पात	मिलियन टन	6.4	3.6	10.1	6.9	12.2	3.8
III.	सीमेंट	मिलियन टन	0.9	7.4	8.8	6.1	5.6	6.9
	I से III की भारित औसत वृद्धि दर		5.1	3.2	5.6	5.4	5.8	5.4
IV.	परिवहन और संचार							
1.	रेलवे द्वारा राजस्व अर्जक माल की ढुलाई	"	3.7	4.0	5.3	7.5	7.0	7.7
2.	प्रमुख पत्तनों पर ढोया गया माल	"	3.4	2.3	9.0	9.9	7.5	11.1
3.	दूरसंचार उपलब्ध कराए गए नए दूरभाष	"						
	कनेक्शन (डाइरेक्ट एक्सचेंज लाइनें)	हजार में	27.2	23.9	21.5	40.1	29.1	21.4
4.	नागर विमानन							
	क. निर्यातित माल की ढुलाई	हजार टन	5.1	4.1	13.3	1.0	0.0	11.8
	ख. आयातित माल की ढुलाई	"	3.6	-1.0	18.6	13.8	9.7	30.1
	ग. अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनलों पर यात्रियों की आवाजाही	मिलियन	4.6	-5.0	4.8	6.5	4.7	15.7
	घ. घरेलू टर्मिनलों पर यात्रियों की आवाजाही	"	7.7	-5.7	9.6	13.1	10.4	25.9

अनतिंम डब्ल्यूएलएल फिक्स्ड और सेल्यूलर

स्रोत : मद सं. I से III वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, IV.2 और 4 सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा 3 संचार मंत्रालय

निर्धारित की जानी है जिसमें यातायात की आवश्यकताओं पर बल दिया गया हो, न कि विद्यमान आवश्यकताओं की पूर्ति पर इससे भारत की जरूरतों की समुचित रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जा सकेगा।

रेलवे एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है, क्योंकि विकल्पों की तुलना में इसके द्वारा माल ढुलाई सबसे अधिक ऊर्जाक्षम होती है। यह इस ओर इंगित करता है कि यदि संस्थागत प्रणाली की स्थापना हो जाए तो रेल के द्वारा ढुलाई की कीमत सड़क मार्ग से ढुलाई की तुलना में काफी कम हो जाएगी। तथापि, इसके लिए रेलवे की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता होगी। दूरसंचार, सड़कों और पत्तनों के रूपांतर के अनुभव यथा आवश्यक सुधार के स्तर के लिए आदर्श स्वरूप होंगे।

नागर विमानन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वर्ष 2004 में काफी उन्नति हुई है। यह पूर्णतया स्पष्ट हो गया है कि नागर विमानन क्षेत्र के दो अतिविशिष्ट आयाम हैं। एक ओर है विमान उद्योग जो कि जहाजरानी उद्योग के समतुल्य है, जहां सरकारी नीति का एक मात्र उद्देश्य हैं- निम्न प्रविष्टि बाधाएं और प्रतिस्पर्धा का उच्च स्तर। दूसरी ओर हवाई अड्डे हैं जिनकी विशेषताएं लोकहितकारी हैं जहां राज्य से बड़ी भूमिका अदा करना अपेक्षित है। हाल के महीनों में, इन दोनों पक्षों में सीमित विकास हुआ है। विशेष तौर पर, प्रतिस्पर्धा के स्तर में सुधार से मूल्यों में गिरावट और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के यातायात में तीव्र वृद्धि में सहायता मिली है।

विद्युत के क्षेत्र में, उत्पादन, पारेषण और वितरण में पृथक मुद्दों के बारे में स्पष्टता है। उत्पादन से लोकहित के मार्ग में समस्या उत्पन्न नहीं होती तथा यह एक सामान्य निजी उद्योग हो सकता है, बशर्ते नीचे की कड़ी में क्रेता एक स्वस्थ संस्थागत ढांचे में कार्य कर रहे हों। एक बार जब संचारण और वितरण में सुधार व्यवस्थित हो जांएगे, तब उत्पादन क्षेत्र में निजी निवेश आकृष्ट करना मुश्किल नहीं होगा। बिजली अधिनियम और वितरण के हाल ही के सुधारों ने इस क्षेत्र में निवेशों को पुनर्जीवति करने में सहायता की है। गैर-अनुसूचित विनिमय बाजार, बिजली के लिए सामान्य स्पाट बाजार की दिशा में बढ़ने की ओर एक महत्वपूर्ण प्रगति है, जिसकी तुलना अन्य वस्तुओं के लिए स्पॉट मार्केट्स तथा अर्थव्यवस्था में वित्तीय उत्पादों से की जा सकती है। तथापि, निजी क्षेत्र की ओर से गैर-अनुसूचित विनियम बाजार में विद्युत की आपूर्ति में नीतिगत बाधाएं सतत रूप से विद्यमान हैं।

देश में विद्युत वितरण में अत्यधिक घाटा हैं। वह एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में अर्थात राजकोषीय सुधार करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। केवल वितरण सुधार करने पर ही सकल घरेलू उत्पाद के एक प्रतिशत के बराबर राजकोषीय सुधार किया जा सकता है।

अंततः भारत की आधारभूत संरचना का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है शहरी आधारभूत संरचना। जो तकनीकें और रणनीतियां राष्ट्रीय लोकहित की दिशा में कार्यकर रही थीं उन्हें सीधे तौर पर स्थानीय लोकोपयोगी सेवाओं के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए, अब ध्यान संविधान के 74वें संशोधन पर, शहरों में संस्थागत सुधारों को समर्थन देने पर और राजकोषीय अंतरणों को संक्रमण लागतों की अदायगी करने और गरीबी को कम करने के लिए उपयोग पर होना चाहिए। ❑

क्या है विशेष उद्देश्यीय व्यवस्था (एसपीवी)

वित्तमंत्री ने उधार की सीमा 10,000 करोड़ रुपये तय की है। सड़कें, बंदरगाह, हवाई अड्डे और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को एसपीवी से सबसे अधिक फायदा हो सकता है

वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने अपने बजट भाषण में बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय विशेष उद्देश्यीय व्यवस्था (एसपीवी) का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित एसपीवी से परियोजनाओं को बैंकों और वित्तीय संस्थानों की बजाए सीधे धन उधार लेने, खास कर दीर्घावधि परिपक्वता वाले ऋणों के लिए अवसर प्राप्त होंगे। प्रस्ताव के अनुसार एसपीवी सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और पर्यटन क्षेत्र के लिए धन के प्रवाह के लिए एक वाहक का काम करेगा।

एसपीवी क्या है?

इस परिवर्णी शब्द का अर्थ है - *स्पेशल पर्पज व्हीकल यानी* 'विशेष उद्देश्यीय व्यवस्था'। बाजार के अनुसार *व्हीकल* शब्द की अदला-बदली हो सकती है। अमरीका में यह विशेष उद्देश्यीय तत्व (एसपीवी) के रूप में जाना जाता है। एसपीवी नाम किसी एक खास व्यवस्था को दिया जाता है। किसी गैर-कानूनी उद्देश्य या ऐसी गतिविधियों के लिए, जो कानूनी प्रावधानों अथवा सरकारी नीति के खिलाफ हो, एसपीवी नहीं बनाया जा सकता। कोई एसपीवी शुरू में, एसोसिएशन में शामिल होने वाले पात्र तत्वों या व्यक्तियों का व्यावसायिक समूह है। प्राइस वाटर हाउस कोआपरेट्स के जोए जॉन के अनुसार एसपीवी का गठन मुख्यत: भविष्य की आवश्यकताओं के लिए धन जुटाने के लिए किया जाता है।

विशेष उद्देश्यीय व्यवस्था और एक कंपनी के बीच क्या कोई अंतर है?

एसपीवी का गठन मुख्यत: बाजार से धन जुटाने के उद्देश्य से किया जाता है। तकनीकी रूप से एसपीवी एक कंपनी हैं। इसे कंपनी अधिनियम में वर्णित कंपनी के गठन से संबंधित नियमों का पालन करना होता है।

सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि यह खतरों को कम करने और पूंजी को मुक्त रखने में मददगार होता है। इसके परिणामस्वरूप एसपीवी और प्रायोजक कंपनी का संचालन के दौरान कंपनी के दिवालिया होने जैसे खतरों से बचाव हो जाता है। एसपीवी में प्रबंधकीय संबंधों को प्रभावित किए बगैर परिसंपत्तियों के प्रतिभूतीकरण की अनुमति भी रहती है

कंपनी की तरह एसपीवी एक कृत्रिम व्यक्ति है। इसमें एक कानून सम्मत व्यक्ति वाले सभी गुण रहते हैं। एसपीवी के शेयरों के मामले में सदस्य स्वतंत्र होते हैं। कानून की नजरों में एसपीवी का अपना अस्तित्व है। इस पर और इसके नाम मुकदमा चलाया जा सकता है। एसपीवी को कंपनी अधिनियम में वर्णित सभी विनियमों का अनिवार्यत: पालन करना होता है। किसी एसपीवी के सदस्य ज्यादातर कंपनियां और प्रायोजक व्यक्ति होते हैं। एसपीवी एक साझेदारी फर्म भी हो सकती है, हालांकि यह एक असहज स्थिति होगी।

एसपीवी से भिन्न कंपनी को, सामान्य उद्देश्यीय व्यवस्था (जीपीवी) कहा जा सकता है। कोई कंपनी उसके 'मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन' (एमओए) में वर्णित अथवा कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुरूप बहुत से कार्य कर सकती है। एसपीवी भी ये सब कुछ कर सकता है लेकिन इसके कार्य का क्षेत्र सीमित और विशिष्ट होता है। यदि ये सब न हो तो एसपीवी को कंपनी कहना बेहतर होगा। एसपीवी के मामले में एमओए ज्यादा सीमित रहता है। मुख्यत: यह अपने निवेश के प्रति चिन्तित उधारदाता को आश्वासन देने से संबंधित होता है।

एसपीवी की स्थापना कैसे होती है?

कंपनी की तरह एसपीवी के भी प्रोमोटर या प्रायोजक होने चाहिए। सामान्यत: प्रायोजित निगम एसपीवी में शेष कंपनी से अपनी परिसंपत्तियों और गतिविधियों को अलग रखती है। ऐसा करना निवेशकों का साहस बनाए रखने के लिए जरूरी है। मूल कंपनी से परिसंपत्तियों और गतिविधियों की दूरी बनाए रखने से नई संस्था का कामकाज मूल कंपनी के आर्थिक उतार-चढ़ाव से प्रभावित नहीं होगा। एसपीवी में बहुत कम खतरा होता है

इसलिए उधारकर्ता ज्यादा निश्चित रहते हैं। यहां महत्वपूर्ण है - प्रायोजक कंपनी और एसपीवी के बीच दूरी बनाकर रखना। प्रायोजक और नई संस्था के बीच पर्याप्त दूरी के अभाव में यह एसपीवी न होकर उसकी सहयोगी कंपनी बनकर रह जाएगी।

एक अच्छी एसपीवी प्रायोजकों से मुक्त हो और वह अपने ही पैरों पर खड़ा होने में सक्षम हो। दुर्भाग्य से व्यवहार में ऐसा नहीं होता। एनरॉन एसपीवी के विफल होने का एक कारण यह भी था कि यह निगमित फाइनेंसिंग और अकाउंटिंग संबंधी सभी स्थापित नियमों का उल्लंघन करते हुए मूल कंपनी को ही समाप्त करने की दिशा में योगदान करने लगी।

एसपीवी स्थापित करने के क्या फायदे हैं?

सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि यह खतरों को कम करने और पूंजी को मुक्त रखने मे मददगार रहता है। इसके परिणामस्वरूप एसपीवी और प्रायोजक कंपनी का संचालन के क्रम में पैदा होने वाले खतरों के कारण दिवालिया होने जैसे खतरे से बचाव हो जाता है। एसपीवी में प्रबंधकीय संबंधों को प्रभावित किए बगैर परिसंपत्तियों के प्रतिभूतीकरण की अनुमति भी रहती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत निश्चित परिसंपत्तियों से अर्जित किसी भी संभावित आय का प्रतिभूतीकरण किया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार विश्वव्यापी प्रतिभूति बाजार का कारोबार 1985 के 1.2 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2003 में 544 अरब अमरीकी डॉलर हो गया। बुनियादी तौर पर कंपनी धन जुटाकर भविष्य की अपनी आय में वृद्धि कर सकती है।

क्या एसपीवी बुनियादी ढांचा क्षेत्र में धन उपलब्ध कराने में मददगार होगा?

इस क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा धन की जरूरत है। आधारभूत ढांचा विकास वित्त कंपनी (आईडीएफसी), पावर फाइनेंस (आईआरएफसी) आदि ऐसे विभिन्न संगठन हैं जो अपने कार्यों से संबंधित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकास के लिए धन जुटा रही हैं। प्रस्तावित एसपीवी, जिसके एक सरकारी कंपनी बनने की संभावना है, बुनियादी ढांचा क्षेत्र हेतु दीर्घावधि के लिए धन उपलब्ध कराने में मददगार साबित होगा। ❑

RAO IAS

THE MOST POPULAR INSTITUTE FOR IAS AND PCS

14/1, स्टैनली रोड, (लोक सेवा आयोग के सामने), इलाहाबाद फोनः 2601624

पत्राचार कोर्स एवं क्लास कोचिंग, छात्रावास उपलब्ध

हिन्दी माध्यम

IAS/PCS (Pre & Main) बैच 7 जून से

भूगोल विजय कुमार मिश्र

वैकल्पिक विषय (Pre & Main) द्वारा

- नवीनतम परीक्षा प्रणाली के अनुसार विषय की तैयारी
- 500 से अधिक मानचित्रों का अभ्यास
- प्रतिदिन होमवर्क तथा उनका सूक्ष्मता से परीक्षण
- सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पर भरपूर अध्ययन सामग्री
- पॉच महीने का गहन शिक्षण एवं प्रशिक्षण
- अभ्यास हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नावलियाँ, नियमित टेस्ट
- सर्वोत्तम शिक्षण परिवेश

Now We have no Branch at Dehradoon

विषय उपलब्ध :- सामान्य अध्ययन और निबन्ध, इतिहास, लोक प्रशासन, राजनीति शास्त्रा, समाज शास्त्रा,

विवरण पुस्तिका हेतु रू0 50/- M.O. से भेजें

SATYA

दसवीं योजना का मध्यावधि मूल्यांकन

प्रधानमंत्री ने कहा है कि दसवीं योजना अवधि (2002-07) में 7 प्रतिशत विकासदर को पार कर पाना संभव नहीं है। योजना दस्तावेजों में लक्षित विकासदर 8.1 प्रतिशत है।

दसवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन पर विमर्श के लिए आयोजित योजना आयोग की पूर्ण बैठक के अध्यक्ष के रूप में चर्चा का आरंभ करते हुए डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि रोजगार-सृजन तथा कृषि का विकास असंतोषजनक रहा है। उन्होंने कहा, "कई सकारात्मक पहलू दिखाई पड़ते हैं लेकिन इस बात के संकेत भी हैं कि अर्थव्यवस्था योजना के अनेक महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल कर पाने वाले रास्ते पर नहीं है, इसलिए सुधारात्मक नीतियों की तत्काल जरूरत है।"

डॉ. सिंह ने कहा कि सामाजिक तथा बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में सरकार की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए विकासदर को तेज करने तथा समुचित संसाधन जुटाने की आवश्यकता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर निजी निवेश बढ़ाना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा, "अपरिचित इलाकों में निजी क्षेत्र के प्रवेश के लिए सरकार को उन्हें बेहतर सार्वजनिक-निजी साझेदारी के प्रारूपों के द्वारा आकर्षित करना होगा।"

प्राथमिकता के सात क्षेत्र

डा. मनमोहन सिंह ने कहा कि कार्यवाही के लिए सरकार ने प्राथमिकता के सात क्षेत्र रेखांकित किए हैं। ये क्षेत्र हैं- कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शहरी नवीकरण तथा बुनियादी ढांचा। मध्यावधि मूल्यांकन में इनमें से प्रत्येक क्षेत्र पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम आधुनिक, तीव्र गति से प्रगति करने वाले, समतामूलक अर्थतंत्र का जो भवन बनाना चाहते हैं, उसकी ये सभी क्षेत्र बुनियाद हैं।

असमानता के मुद्दे को उठाते हुए तथा उच्च एवं संतुलित प्रगति का आह्वान करते हुए डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा, "यह महत्वपूर्ण है कि एक देश के रूप में हम दो कदमों पर चलना सीख लें, इनमें से एक कदम तीव्र प्रगति की प्रक्रिया तथा दूसरा पुनर्वितरण और संतुलित विकास का आलिंगन करे। इनमें से दूसरे के लिए संसाधन जुटाने के लिए पहला जरूरी है।" प्रधानमंत्री ने कहा, "प्रगति से जहां धन की प्राप्ति होती है, वहीं समतामूलक समाज तथा भौतिक बुनियादी ढांचे में उनका निवेश भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है ताकि समाज के हाशिये पर स्थित वर्गों और पीछे छूट गए इलाकों को उन्नत इलाकों का हमकदम बनाए जा सके।"

उन्होंने कहा कि योजना को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी नीतियां इन दोनों पक्षों का ध्यान रखे। मध्यावधि मूल्यांकन में इन दोनों पहलुओं का ध्यान रखा गया है। इन दोनों के संदर्भ में हमें नवोन्मेषी तरीके से सोचना जारी रखना चाहिए।

और समीक्षाएं जरूरी

11वीं योजना अवधि (2007-08 से 2011-12) से और अधिक नमनीय दृष्टिकोण का आह्वान करते हुए डॉ. मनमोहन सिंह ने योजना प्रक्रिया का और अधिक बारंबारता के साथ मूल्यांकन करने की जरूरत का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि पंचवर्षीय योजना के फायदे स्पष्ट हैं, लेकिन उपभोक्ताओं की मांग शैली और उत्पादन के अवसरों में तीव्र तकनीकी परिवर्तनों द्वारा नियंत्रित विश्व में यह पर्याप्त नहीं है। प्रधानमंत्री ने प्रश्न किया, "बुनियादी ढांचे के विकास में दीर्घकालिक दृष्टि के लिए क्या पांच वर्ष की अवधि पर्याप्त है? किसी भी बजट की अधिकांश रचनात्मक चर्चा योजनागत व्यय पर बल देती है। यदि ऐसा है तो क्या यह आवश्यक है कि योजना-प्रक्रिया में पुनः शामिल होने के लिए पांच वर्ष के अंतराल तक प्रतीक्षा की जाए? अथवा क्या हम यह कार्य कुछ क्षेत्रों के लिए वार्षिक आधार पर तथा कुछ अन्य इलाकों के संदर्भ में दीर्घावधि आधार पर कर सकते हैं?"

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की पूर्ण बैठक में दसवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में शामिल विभिन्न क्षेत्रवार सुधारात्मक उपायों का अनुमोदन किया गया। बैठक के बारे में संवाददाताओं को बताते हुए योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने कहा कि मध्यावधि मूल्यांकन की लगभग 56 संस्तुतियों का लक्ष्य अर्थतंत्र को रास्ते पर पुनः वापस लाना है ताकि वह दसवीं योजना के संबद्ध क्षेत्रगत लक्ष्यों के अनुरूप बन सके। दसवीं योजना अवधि के शेष दो वर्षों के दौरान यदि इन्हें हासिल कर लिया गया तो 11वीं योजना के लक्ष्यों को हासिल कर पाना संभव हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दसवीं योजना के दौरान अर्थव्यवस्था लगभग 6.5 प्रतिशत की दर से प्रगति करेगा। आगामी दो वर्षों में यह दर 7.7 से 7.8 प्रतिशत तक रह सकती है। उन्होंने कहा कि विकास दर को बढ़ाने के लिए कृषि पर अधिक बल अपेक्षित होगा। आयोग कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर कृषि क्षेत्र को और गतिशील बनाने के लिए दीर्घावधि कार्य क्रम पर संयुक्त पत्र तैयार करेगा। श्री अहलूवालिया ने कहा कि सिंचाई, जल प्रबंधन तथा सूखे इलाकों में मृदा संरक्षण के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता है।

दूरसंचार और ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना है। इनके अतिरिक्त, मध्यावधि मूल्यांकन में माध्यमिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी साझेदारी की संभावना जताई गई है। ❑

(योजना (हिंदी और अंग्रेजी) संपादकीय टीम द्वारा संकलित)

नामांकन प्रारम्भ
25 मई, 2005

लोक प्रशासन

By (हिन्दी माध्यम)

Atul Lohiya

(A person who believes in hard work and scientific approach)

UGC-NET

QUALIFIED IN TWO SUBJECTS

HISTORY & PUB. ADMINISTRATION

Course Offered:
* Mains
* Mains + Prelims (Foundation Course)
* Test Series for Mains
* Answer Formating Session for Mains
* Test Series with Answer Formating Session
* Test Series for Prelims

पत्राचार पाठ्यक्रम भी उपलब्ध
(पूर्णतः कम्प्यूटराइज्ड नोट्स)

MAINS - 2500/-
MAINS + PRE. - 3500/-
डाक खर्च - 200/- अतिरिक्त

Send DD/MO in favour of Atul Lohiya

UPSC के साथ *UP, MP, Raj., Bihar, Uttaranchal, Jharkhand Chhattisgarh, Haryana, Himachal PCS* की भी तैयारी

नया सत्र : दिल्ली - 1 जून, 2005 ★ इलाहाबाद - 5 जून, 2005

अन्य विषय	सामान्य अध्ययन अतुल लोहिया, शैलेन्द्र सिंह, शशि भूषण, अनामिका सिंह एवं अन्य नया सत्र : दिल्ली - 1 जून, 2005 ★ इलाहाबाद - 5 जून, 2005	हिन्दी साहित्य अनामिका सिंह 2 जून, 2005

'अतुल लोहिया'

शिक्षक, मार्गदर्शक और मित्र भी

Cell.: 9810651005, 0532-3217608

Sanjay Singh
Regional Director (Allahabad)
Cell. : 9839746184

Shashi Bhushan
Director
Cell. : 9868378728

"PRABHA"

AN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION

105, VIRAT BHAWAN (MTNL BLDG.), NEAR BATRA CINEMA, MUKHERJEE NAGAR, DELHI-9
Phone : 27655134. Mobile: 9810651005 • e-mail : atullohiya@rediffmail.com
Branch : 305/250, COLONELGANJ, NEAR COLONELGANJ POLICE STATION, ALLAHABAD.

शारीरिक विकलांगों के लिए स्कूटर

धनजीभाई केरई (31) गुजरात के कच्छ जिले के मुंदड़ा तालुका के एक मध्यम श्रेणी के किसान परिवार से हैं। वह स्कूल तो नहीं गए लेकिन बाद में स्वेच्छा से सरकार के प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के तहत खोले गए 'प्रौढ़ शिक्षण केंद्र' में तीन माह तक गए जहां उन्होंने कुछ हद तक पढ़ना-लिखना सीखा। धनजीभाई जन्म से ही शारीरिक रूप से विकलांग थे। लेकिन उनमें गजब का निश्चय भरा है। मुश्किल से वह डेढ़ फुट (0.5 मीटर) लंबे हैं और उनका वजन मात्र 19 किग्रा. है। दो वर्ष की आयु में पोलियो के जबर्दस्त दौरे ने उन्हें स्थाई रूप से विकलांग बनाकर रख दिया और तब से उनकी टांगें और एक हाथ काम नहीं करता। उनका चलना-फिरना बहुत कष्टकारी है। लेकिन इस विकलांगता के बावजूद उनमें उत्साह भरा पड़ा है। हालांकि उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण तो प्राप्त नहीं किया लेकिन बिजली उपकरणों और आटोमोबाइल की मरम्मत का काम सीख लिया है और वह अपने क्षेत्र में एक अच्छे मैकेनिक के रूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं। स्वयं-शिक्षा प्राप्त यह नौजवान हमेशा अपने जीवन को उपयोगी और सरल बनाने के रास्ते खोजता रहता है। उन्होंने अपने लिए एक विशेष स्कूटर तैयार किया है जिसके जरिए वह एक दिन में 150 किमी. तक की यात्रा कर सकते हैं। धनजीभाई अविवाहित हैं और अपने माता-पिता के साथ ही रहते हैं। उनकी 20 एकड़ सिंचाई सुविधा रहित भूमि है और उनके पिता खेती करते हैं।

धनजीभाई हमेशा स्कूटर चलाने की इच्छा रखते थे। लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके दोनों पैर और एक हाथ काम नहीं कर रहा हो, यह बिल्कुल असंभव था। धीरे-धीरे उनकी चाह दृढ़ निश्चय में परिवर्तित हो गई। अपना स्वप्न पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत सी चीजें एकत्र करना शुरू कर दिया ताकि उनसे वह एक ऐसा स्कूटर तैयार कर सकें जिसे चलाने में उन्हें बाधा महसूस न हो।

पहली मुश्किल तो यह थी कि वह अपने दोनों हाथों के साथ किसी दुपहिये का न तो हैंडल ही ठीक से संभाल सकते थे और न ही संतुलन बना सकते थे। इसीलिए उन्होंने दुपहिये को चार पहिया में बदलने की सोची। यह अपने आप में एक अनुपम प्रयोग था। उन्होंने आटोरिक्शा के दो पुराने पहिए खरीदे और स्टील की एक मजबूत पाइप जुटाई। इनके साथ वह काम में जुट गए और स्कूटर में बदलाव करने तथा उसे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के मुताबिक ढालने में कामयाब हो गए ताकि वह स्वयं इस गाड़ी को चला सकें।

खोज

मूलत: यह अलग-अलग पुर्जे जोड़कर बनाया गया स्कूटर है जिसका चेसिस और ईंजन बजाज प्रिया का तथा बाहरी हिस्सा बजाज चेतक का है। स्कूटर के साथ दो अतिरिक्त पहिए साइडों में (संशोधित लूना, दोनों ओर एक-एक) लगाए गए हैं ताकि वाहन का संतुलन बना रहे। धनजीभाई के लिए हैंडल तक पहुंचने हेतु सामान्य ड्राईवर सीट के सामने एक रिमूवेबल सीट लगाई गई है। पिछले व्हील ब्रेक के साथ एक लीवर जोड़ दिया गया है ताकि चालक अपने हाथ से ब्रेक लगा सके। पीछे के दो पहिए थोड़े से ऊंचे रखे गए हैं ताकि वाहन पलटे नहीं। इस व्यवस्था से चालक सुविधाजनक रूप से गाड़ी चला सकता है तथा अधिकतम 60-70 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है।

धनजीभाई को प्रयोग के तौर पर चलाने के लिए गाड़ी सौंपने से पूर्व उसके मित्र, कमलभाई ने इस स्कूटर को दो दिनों तक परीक्षण के तौर पर चलाया। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग तीन माह लग गए और धनजीभाई इस स्कूटर को दो दिन में चलाना सीख गए। इस प्रयोग पर करीब 3,000 रुपये खर्च किए गए। उसके सामने एक ही दिक्कत थी कि इसे स्टार्ट करने में किसी और की मदद लेनी पड़ती थी। धनजीभाई को एक व्यक्ति उठाकर स्कूटर की सीट पर बैठाता है और वह अपना स्थान ग्रहण करके हैंडल को संभालते हैं। वह व्यक्ति किक पैडल मारकर स्कूटर को स्टार्ट करता है तब धनजीभाई उसे कच्ची-पक्की सड़कों पर दौड़ाते हैं। इस खोज का यह महत्व है कि इससे इस शारीरिक विकलांग व्यक्ति की दूसरे लोगों पर निर्भरता खत्म हो गई और उसे इधर-उधर घूमने का यह एक अच्छा साधन मिल गया।

निर्भरता से आत्म निर्भरता

धनजीभाई याद करते हुए कहते हैं कि जब तक वह 15 वर्ष के थे, अपनी मां की पीठ पर बैठकर, जहां कहीं भी वे

'शोधयात्रा' नामक यह श्रृंखला हमने नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, अहमदाबाद के सहयोग से आरंभ किया है। यह श्रृंखला आगे के अंकों में भी जारी रहेगी।

Y.D. Misra's IAS

(Head Office:) 30/27, East Patel Nagar Centre

ADMISSION OPEN **IAS Main-2005**

IAS Prelim-cum-Main-2006

ONE YEAR COMPACT COURSE

We work for your success.

One year compact course includes both the Optional Subjects+GS+Essay+ Qualifying Languages+Interview Guidance

Covering the entire course twice+ two revisions+ 40 Prelim Test 2 hrs. each+ 20 Main Exam Tests 3 hrs. each in every subject.

Or Join 5 Months Course in individual subjects: to begin in June 2005

General Studies, History, Pub. Admn, Sociology, Geography, Pol. Sc., Philosophy, Psychology, Hindi Lit.

★ Ultramodern infrastructure & fabulous library facility. ★ Hostel facility available.

Y. D. MISRA'S IAS *offers* **DESTINATION IAS**

15 Days' Prelim 2005 Test Series

Inclusive of 3 Days' Prelim Personal Guidance
To begin on 15th March/1st April/15th April
Only at: East Patel Nagar Centre
Minimum 40 Tests in each subject
(G. S., Hist., Geog., Pub. Admn., Socio.)
Come, see and decide wether you want to take our tests.
Believe it or not, it is a "Must do" and 100% Improvement Test Series

Postal Guidance/Previous Years PT/Main Question Series

Postal Guidance (Every subject Rs. 2200/-)
(Send your M.O./ Demand Draft in favour of "Y.D. Misra's IAS" Addressed to : 30/27, East Patel Nagar, New Delhi-8)
Ph. 55486332/55486334/ 55486335 Mobile: 9312168121, 9810573354

Previous years IAS/PCS Prelim/ Main Exam Question Analysis Series
Essential for every serious IAS/PCS aspirant
(All subjects: Available at Leading Bookshops and at Y. D. Misra's IAS, 30/27, East Patel Nagar, New Delhi-8
Ph. 55486332/55486334/ 55486335 Mobile: 9312168121, 9810573354)

Also join 3yrs./ 2yrs/ 1yr.
Launched for the 1st time in India **IAS Foundation Course**
at Y.D. Misra's IAS While doing your **B.A./B.Com.**
30/27, East Patel Nagar, New Delhi-8, Ph: 55486332/34/35

We help you score high marks in your B.A./B.Com. Exams. & Ensure your success in IAS Examination.

Y.D. Misra's IAS

Contact: Manoj K. Singh (Director: Y. D. Misra's IAS)
B-17, Ist Floor, Satija House, Commercial Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9
Ph.011-55486332, 011-55486331 Cell: 9810573354, 9312168121, 9810345023

Y.D. Misra's IAS

Contact: Jaya Sharma (C. E. M.: Y. D. Misra's IAS)
30/27, East Patel Nagar, New Delhi-8 (Opp. Mughal Mahal Restaurant, Close to Siddhartha Hotel Main Gate Road)
Ph. 55486332/55486334/ 55486335 Mobile: 9312168121, 9810573354

जाती थीं, यात्रा करते थे। फिर उनके जीवन में नया मोड़ आया और उन्होंने मामला अपने हाथ में लिया और आत्मनिर्भर होकर दिखा भी दिया। तब से लेकर अपने सभी व्यक्तिगत कामों के लिए वह खुद जाते हैं। वह इससे भी संतुष्ट नहीं हुए और पूर्णत: आत्मनिर्भर होने के लिए खुद कमाई करना चाहते थे।

एक बार धनजीभाई के मामा ने, जो लंदन में रहते हैं, उन्हें एक टू-इन-वन भेजा। कुछ ही दिन बाद धनजीभाई ने इस टेप रिकार्डर के पुर्जे-पुर्जे खोलकर रख दिए और इसे दोबारा उसी स्थिति में लाने का फैसला किया। लेकिन लगातार तीन दिनों की कोशिश के बावजूद वह ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए। तब उन्होंने टेप रिकार्डर को छोड़ दिया और अपनी साईकिल पर एक मोपेड का ईंजन लगाने पर ध्यान केंद्रित किया। उनके एक मित्र कमलभाई सिंघल ने साईकिल पर ईंजन वेल्ड करने में उनकी मदद की। चार दिन में मोपेड ईंजन वाला यह साईकिल तैयार था। अपनी इस सफलता से उत्साहित होकर धनजीभाई एक बार फिर टेप रिकार्डर पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वायरिंग की ध्यानपूर्वक जांच-परख के बाद उन्होंने इसे पुन: जोड़ना शुरू कर दिया और इस बार वह सफल हो गए।

अपने मामा के टू-इन-वन रेडियो पर सफलता ने धनजीभाई को बिजली और इलेक्ट्रानिक उपकरणों की मरम्मत करने का उत्साह दिया। शीघ्र ही वह टेलीविजन सेटों, रेडियो सेटों और बिजली या अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों पर अपनी योग्यता को आजमाने लगे। अपने काम में मुस्तैद होने के लिए उन्होंने कुछ पुराने टेप रिकार्डर और रेडियो सेट उन पर काम करने के उद्देश्य से खरीद लिए। उन्होंने बताया कि "अनेक लोगों ने स्वेच्छा से अपने पुराने उपकरण मुझे दे दिए।" उन्होंने उनकी मरम्मत की तथा ऐसे लोगों को बेच दिया जो एकदम नया आइटम खरीदने में असमर्थ थे।

धनजीभाई अपनी यादों और अन्वेषणात्मक अनुभव को बताते हुए कहते हैं :

"हमारे गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसके पास लोग अपने टेपरिकार्डर, रेडियो सेट या घड़ी में कुछ खराबी आने पर ले जा सकें और उन्हें इन वस्तुओं को छोड़ ही देना पड़ता था। सबसे पहले मैंने एक रिपेयरिंग किट खरीदी और काम शुरू कर दिया। मैंने अपना मेहनताना बहुत ही सामान्य रखा। पूरी लगन के साथ मेरा प्रयास यह रहता था कि वह सामान फिर से काम करना शुरू कर दे। इसके बाद मैंने बाइसिकलों की मरम्मत और तथा स्कूटर टायरों का काम शुरू कर दिया। धीरे-धीरे मैंने आडियो से वीडियो का कार्य शुरू कर दिया। मैंने एक संबंधी से वीसीआर

लिया, उसके उपकरणों संबंधी जानकारी हासिल की और इसकी मरम्मत का काम भी सीख लिया। जैसे-जैसे मैं एक काम में निपुण होता जाता, दूसरे काम को समझना और उसका अध्ययन करना शुरू कर देता।"

तेजी के साथ उनके पास अपने को व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त काम हो गया। इस प्रकार उन्होंने बिजली उपकरणों की मरम्मत का काम एक व्यवसाय के रूप में अपनाया और यह उनके जीवनयापन का एक अच्छा जरिया बन गया।

मैकेनिक के बाद का जीवन

धनजीभाई ने अब इलेक्ट्रानिक मार्केट से हिस्से-पुर्जे लेकर नए टेप रिकार्डर और टेलीविजन सेट तैयार करना शुरू कर दिया। उन्होंने 150 टेपरिकार्डर, 80 रेडियो रिसीवर और 50 टेलीविजन सेट, 20 रंगीन टीवी और 30 श्याम-श्वेत टीवी बनाकर बेचे। उन्होंने स्टाक के लिए कभी कोई सेट नहीं बनाया बल्कि आर्डर मिलने पर ही वह काम शुरू करते हैं। वह रोजाना औसतन 200 रुपये से 300 रुपये कमाते हैं और इस तरह अपने को वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर बना लिया है।

भुज, मुंदड़ा और मांडवी के इलेक्ट्रानिक सामान की दुकानों के मालिकों का मानना है कि धनजीभाई विश्वास का और कुशल मैकेनिक हैं। उन्हें मिलने वाले रिपेयरिंग के काम वे धनजीभाई को ही उपलब्ध कराते हैं।

कई दफा वे यहां तक जोर देते हैं कि मुझे अत्याधुनिक और नए माडल के उपकरणों की भी मरम्मत करनी चाहिए। "ऐसे ही समय मैंने महसूस किया कि किसी आदमी की सीखने की सीमा तो आकाश की तरह अनंत है", - धनजीभाई गौरवपूर्ण लहजे में बताते हैं। धनजीभाई द्वारा तैयार उपकरणों का उपयोग करने वाले उसके उत्पाद को लेकर बेहद खुश हैं और उनका दावा है कि ये प्रतिष्ठित कंपनियों के ब्रांड वाले सामान से भी बहुत अच्छे हैं।

आशा के साथ भविष्य की राह

धनजीभाई अपने मित्रों के प्रति बहुत आभारी हैं जिन्होंने उनकी हमेशा मदद की है और समर्थन किया है। चूंकि वह खुद स्कूटर स्टार्ट नहीं कर सकते अत: जब भी उन्हें कहीं जाना हो तो उन्हें अपने मित्र को साथ ले जाना पड़ता है। इस निर्भरता को वह अच्छा नहीं मानते और एक स्वस्टार्टिंग सुविधायुक्त स्कूटर तैयार करना चाहते हैं, जिसका वे खुद ही विकास करना चाहते हैं।

1999 में उन्हें 'सृष्टि सम्मान' से सम्मानित किया गया और 'सृष्टि' ने कई स्कूटर कंपनियों से संपर्क भी किया लेकिन उन्होंने आज तक प्रत्युत्तर नहीं दिया है। लेकिन देर-सवेर किसी-न-किसी कंपनी को उत्तर देना ही पड़ेगा। इस संसार में धनजीभाई जैसे अनेक लोग हैं जो स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। बाजार को इन शारीरिक विकलांगों की अपूर्ण आवश्यकताओं पर जरूर ध्यान देना होगा। ❑

आप हमारे साथ परिश्रम करें, हम आप पर आपसे ज्यादा परिश्रम करते हैं।

इतिहास
रजनीश राज

रजनीश सर पत्थर में छिपी मूर्ति की सम्भावना को तराशने की कला जानते हैं। Manoj Tewari
62nd Rank :UPSC-2002
Marks in History : 358

इतिहास में पढ़ा था कि हर्षवर्धन को कार्य करने से ही उर्जा मिलती थी। रजनीश सर को देखकर ही लगा कि ऐसा भी संभव है। Alok Jaiswal
Selected for D.S.P. (UP) 2001

पिछले वर्ष हमारे यहाँ से 15 छात्रों ने 325 से 360 के बीच अंक प्राप्त किए।

P.T.

तथ्यों के अम्बार से नहीं, तकनीकी स्तर पर तैयारी। कैसे?

- प्रति अध्याय प्रश्न पूछने की प्रवृति का विश्लेषण और टेस्ट।
- प्रत्येक 3 टॉपिक पर एक टेस्ट।
- प्राचीन/मध्यकालीन और आधुनिक भारत पर पृथक टेस्ट।
- स्रोत/प्रशासन/समाज/अर्थव्यवस्था/धर्म/संस्कृति प्रत्येक पर पृथक टेस्ट।
- कक्षा समाप्त होने पर पूरे पाठ्यक्रम पर टेस्ट
- प्रत्येक अध्याय का विशद विश्लेषण।
- पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के आधार पर पुनरावलोकन।

मेन्स

हम आपको प्रशासक बनाते हैं, इतिहासकार नहीं। कैसे?

- इतिहास के साथ ही इतिहास दर्शन का विश्लेषण।
- पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र सहित प्रति अध्याय 10 प्रश्नों के उत्तर की संरचनागत व्याख्या।
- मॉडल उत्तर लिखवाना।
- सावधिक और आकस्मिक टेस्ट।
- पुनरावलोकन के लिए पृथक कक्षा

सामग्री :- मेन्स और P.T. दोनों के लिए उच्चस्तरीय एवं परीक्षोपयोगी सामग्री।

- पढ़ाई व लेखन सम्बन्धी रणनीति पुस्तिका।
- प्रश्न पत्र संकलन।

निःशुल्क कार्यशाला 10 जून प्रातः 10 बजे से

नामांकन प्रारम्भ

SIHANTA IAS

632, Mukherjee Nagar, Delhi-9
(Near Aggarwal Sweets)
9873399588

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु समूह उद्यमिता का मॉडल

○ वीरेंद्र कुमार विजय

देश में गांवों की बसावट के स्तर, छोटे, मध्यम एवं बड़े गांवों के आकार एवं स्थानीय संसाधनों एवं परिस्थितियों के मध्य शोधकार्य करके एक मॉडल का विकास किया गया है जिससे स्थानीय आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में निश्चय ही मदद मिलेगी एवं ग्रामीण रोजगार में वृद्धि होगी। इस मॉडल में कारीगरों, खेतीहर मजदूरों, छोटे किसानों को लक्ष्य बनाया गया है

ग्रामीण क्षेत्रों में आज गरीबी एवं बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी है। संगठित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर घट चुके हैं। सत्तर के दशक में उद्योग जगत में काम की तलाश वालों को 10 प्रतिशत रोजगार मिलता था। वह अस्सी के दशक में घटकर पांच प्रतिशत रह गया और नब्बे के दशक में आकर स्थिर हो गया। कृषि क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के भी कार्य करने के अवसर कम होते जा रहे हैं। जब संगठित एवं कृषि दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं तो आशा अब असंगठित क्षेत्र (ग्रामीण उद्योग-धंधों) पर है जिससे बढ़ती जनसंख्या को रोजगार एवं व्यवसाय मिल सके। इससे गांवों से शहरों में पलायन रुकेगा, गरीबों, कारीगरों मजदूरों आदि की आमदनी बढ़ेगी एवं गांवों में कच्चे माल से पक्का माल तैयार कर मूल्य संवर्द्धन किया जा सकेगा जिसका लाभ गांव वालों को ही मिलेगा।

अब बात आती है कि यह सब होगा कैसे? देश में गांवों की बसावट के स्तर, छोटे, मध्यम एवं बड़े गांवों के आकार एवं स्थानीय संसाधनों एवं परिस्थितियों के मध्य शोधकार्य करके एक मॉडल का विकास किया गया है जिससे स्थानीय आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में निश्चय ही मदद मिलेगी एवं ग्रामीण रोजगार में वृद्धि होगी। इस मॉडल में कारीगरों, खेतीहर मजदूरों, छोटे किसानों को लक्ष्य बनाया गया है। धीरे-धीरे ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले कारीगर, बढ़ई, मोची, तेली, कुम्हार, लुहार, सुनार, रंगरेज, सुनार आदि कम हो रहे हैं। उनके कार्य से जीविकोपार्जन मुश्किल हो गया है। इनकी विद्या को ग्रहण करने वाले कम हो रहे हैं एवं ये लोग खुले बाजार की प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पा रहे हैं। ऐसे में इनकी तकनीक को विकसित कर बाजार में प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाना आवश्यक है। इसलिए मॉडल में बहुपक्षीय अर्थव्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसमें सम्मिलित सभी व्यक्ति/परिवार जैसे - कारीगर, मजदूर, किसान आपस में एक-दूसरे से संबंधित एवं निर्भर हैं। ये लोग ही मिलकर गांव की अर्थव्यवस्था की रचना करते हैं। जैसे किसान के कृषि उपकरण हल, बैलगाड़ी आदि में बढ़ई, लुहार, मजदूर सभी का योगदान होता है। परंतु अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार के लोगों का आपसी संबंध होता है। अत: लोगों की उद्यमिता योग्यताओं एवं उनकी उत्पादन एवं वितरण तकनीकों को क्षेत्रीय एवं स्थानीय विविधताओं के अनुसार ढालने की आवश्यकता है। साथ ही लोगों की वर्षों से अस्तित्व वाली उत्पादन व्यवस्था को ध्यान में रखना जरूरी है। इन सबको करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का समावेश लोगों की उत्पादन व्यवस्था में करना पड़ेगा। इसमें उपर्युक्त मशीन, उपकरण, यंत्र का समावेश उत्पादन की संबंधित विधि एवं क्रिया में करना मॉडल का अभिन्न अंग है। इससे क्रियाविधि पर निर्भरता कम हो जाती है एवं यह कार्य करने वाले की वैयक्तिक कुशलता की जगह सभी उत्पादनकर्ताओं से एक समान उत्पादन/ परिणाम एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्राप्त करने में सहायक होता है। यह सत्य है कि अकेली उत्पादन की छोटी इकाई कच्चा माल इकट्ठा किए बगैर, वितरण करने आदि के नेटवर्क के बिना उद्देश्य पाने में सफल नहीं हो सकती। अत: एक नई कच्चा माल इकट्ठा करने, पक्का माल बेचने आदि से संबंधित तंत्र का विकास मॉडल में समाहित किया गया है जिससे छोटी-छोटी इकाइयां मिलकर बड़ी इकाई के उत्पादन से कीमत व गुणों में टक्कर ले सकें। अत: कस्बे/तहसील स्तर पर जहां स्थानीय एवं गैर स्थानीय चीजों की उपलब्धता रहती है वहां पर उससे संबंधित सभी गांवों के काम करने वालों के लिए इकट्ठा सामान खरीदा व बेचा जाए जिससे

उनको अधिक लाभ मिल सके। इन सबको करने के लिए गांवों के स्तर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित कार्य करने वालों की जरूरत है। इस स्तर पर आवश्यकताओं के अनुरूप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हमारे देश की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थाएं उपलब्ध करवाएं। इन दोनों स्तरों, निचले स्तर (गांव के) एवं उच्च स्तर (वैज्ञानिकों एवं तकनीशियनों) के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए मध्यम स्तर की कड़ी की आवश्यकता है। यह कार्य स्वयंसेवी संस्थाएं एवं अन्य सरकारी संस्थाएं कर सकती हैं।

इस मॉडल का केंद्र बिंदु समाज का गरीब तबका है जैसे कारीगर, दस्तकार, मजदूर, किसान आदि। इसमें माना गया है कि व्यवसाय जो इनको बांधता है वह एक-दूसरे का पूरक है अत: इनके लिए समूह उद्यमिता को ध्येय बनाया गया है जिसमें उपर्युक्त सभी सदस्य होते हैं। समूह उद्यमिता वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति में उत्पादन के उनके कार्य में आने वाली बाधाओं एवं समस्याओं पर आधारित है। इससे उनके विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन नेटवर्क के तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलता है। इसमें मुख्यतया ध्यान स्थानीय प्राथमिक उत्पादन का प्रसंस्करण कर मूल्य संवर्धन का काम करने वाले समूह के सदस्यों को अधिक लाभ पहुंचाना है।

ग्रामीण क्षेत्रों की बसावट के आधार पर यह पाया जाता है कि गांव अपने आप में आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से एक संपूर्ण इकाई नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र को विभिन्न स्थानों के समूह के एक कांप्लेक्स के रूप में प्रकट किया जा सकता है जो कि मूलभूत आवश्यकताओं को विभिन्न प्राथमिक उत्पादन एवं क्रियाओं के कर्ताओं के माध्यम से प्रकट करते हैं। विभिन्न कर्ताओं/क्रियाओं की आपसी निर्भरता एक कड़ी रूपी ढांचा बनाती है जो ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादन को स्थापित करती है। यह स्थानीय प्राथमिक उत्पादन (कृषि एवं पशुपालन) तथा द्वितीयक उत्पादन (कारीगरों का काम) आर्थिक स्तर पर भी आपस में एक इकाई प्रदर्शित करता है जिसमें कस्बा, उसके आसपास के बड़े गांव, प्रत्येक बड़े गांव के इर्द-गिर्द के मध्यम गांव एवं प्रत्येक मध्यम स्तर के गांव के आसपास के छोटे-छोटे गांव सम्मिलित हैं। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से छोटे गांव से लेकर कस्बे तक एक स्थानीय तालमेल होता है जो स्थानीय अर्थव्यवस्था का निर्माण करता है।

अध्ययन करने पर पाया गया है कि देश भर में लगभग 3,500 कस्बे हैं जो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से स्थानीय ग्रामीण व्यवस्था की इकाई के रूप में हैं। औसतन प्रत्येक कस्बे के चारों ओर 7-8 बड़े गांव, प्रत्येक बड़े गांव के चारों ओर लगभग 7-8 मध्यम स्तर के गांव एवं प्रत्येक मध्यम स्तर के गांव के आसपास 2-3 छोटे-छोटे गांव मिलकर स्थानीय इकाई की अर्थव्यवस्था संरचना को पूरा करते हैं। छोटा गांव वह गांव है जहां पर केवल कृषि व पशुपालन होता है तथा कोई मजदूर, कारीगर

Entrepreneurship Development Institute of India Ahmedabad, Gujarat.

Promoted by the IDBI, IFCI Ltd., ICICI Ltd. & SBI, with support from the Govt. of Gujarat. EDI is recognised as **'Centre of Excellence in HRD Training'** by UN-ESCAP, Bangkok. The Institute announces admission to **Eighth Batch** of its one-year

POST GRADUATE DIPLOMA IN MANAGEMENT OF NGOs (PGDMN) 2005- 06

Aims at developing aspiring men/women to either launch their own NGO or provide management expertise to an NGO.

Salient features • 100% placement record • Jobs in national & international NGOs

Eligibility: Graduation in any discipline.

Written test will be held at 35 centres across the country including Mumbai.

Important Dates

Written Test : May 15, 2005 • Personal Interview : June 13 - 15, 2005

For prospectus - cum-application form (can also be down loaded from www.ediindia.org) please send a demand draft of Rs. 500/- drawn in favour of EDI, Ahmedabad. Last date for submitting application form is **25 April, 2005.**

EDI, P.O. Bhat 382 428, Dist. Gandhinagar, Gujarat.

Phone : 079-23969161, 23969163 Fax : 079-23969164 E-mail : pgdbem@ediindia.org Website:www.ediindia.org

EDI Regional Offices : Lucknow (0522) 2780820 • **Bangalore** (080) 23119360 • **Guwahati** (0361) 2461063

Admission for Post Graduate Diploma in Business Entrepreneurship & Management (PGDBEM) is also open.

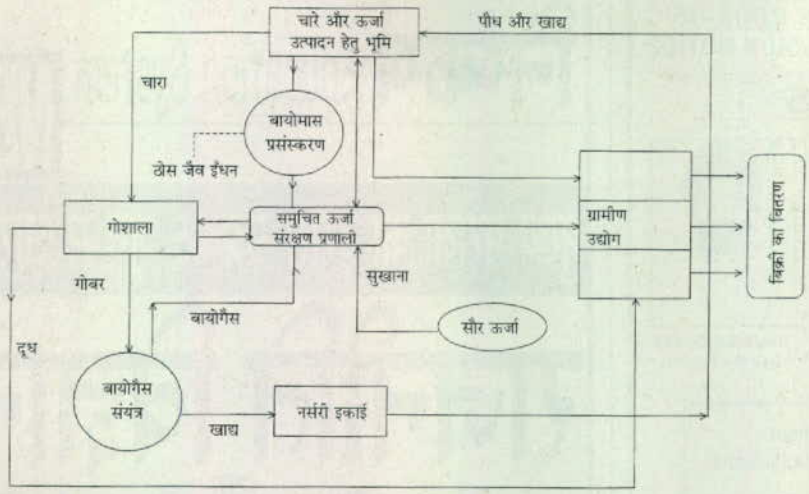

मध्यम स्तर के गांव में प्रस्तावित ग्रामीण औद्योगिक परिसर का मॉडल

आदि वहां नहीं होते। मध्यम श्रेणी का गांव वह गांव है जहां पर अधिकांशतया किसान होते हैं, साथ ही कुछ मजदूर, कारीगर आदि मिलते हैं एवं आवश्यकतानुरूप छोटे-छोटे बाजार, हाट एवं कृषि उपकरणों आदि की मरम्मत की सुविधा मिल जाती है। इन सभी प्रकार के गांवों में अधिकांशतया स्थानीय सामान ही उपलब्ध होता है। कस्बा या तहसील ऐसा स्थान है जहां पर आसपास के ये सभी गांव वाले अपनी पैदावार, सामान लाकर बेचते हैं एवं जरूरत का सामान खरीदते हैं।

ऐसे एक क्षेत्र में बहुआयामी उद्यमिता विकसित करने के लिए वहां के संसाधनों, संभावनाओं एवं क्षमताओं का विश्लेषण किया जाता है। यह कार्य पांच भागों में किया जाता है जिसमें प्रथम भाग में क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी, जैसे- जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थितियां, पशुधन, कृषि, प्राकृतिक संसाधन, कारीगर, मजदूर, भूमि का उपयोग आदि सम्मिलित हैं। द्वितीय भाग में जिस सेक्टर में उद्यम लगाना है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी, जैसे- अभी उसकी स्थिति क्या है, तथा किस-किस स्थान पर कैसा-कैसा कार्य किया जाता है, प्राप्त की जाती है। तृतीय भाग में तकनीकी एवं क्रियाओं की दृष्टि से क्या-क्या माल चाहिए, उपकरण चाहिए, काम करने वाले का कौशल चाहिए तथा उत्पाद आदि का आकलन किया जाता है। चतुर्थ भाग में उत्पाद की मांग, आपूर्ति का विश्लेषण किया जाता है तथा कितनी स्थानीय मांग है एवं उसकी आपूर्ति कैसे हो, इसका विवरण तैयार किया जाता है। पंचम भाग में चतुर्थ भाग के विश्लेषण के आधार पर मांग के मद्देनजर क्या-क्या उद्यम संभव हैं एवं उनको किस प्रकार क्रियान्वित किया जाए तथा किस-किस गांव में कौन-कौन इसमें भाग लेगा, तकनीकी-आर्थिक विश्लेषण आदि को समाहित किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों की संभावना के मद्देनजर कुछ प्रमुख सेक्टर इस प्रकार हैं : दूध, बंजर भूमि विकास, पशुपालन, ऊर्जा, प्रबंध, रेशम, शहद, अभियांत्रिकी, चमड़ा, बुनाई आदि। एक कस्बे/तहसील में यदि छोटे स्तर के 200 गांव हैं एवं मध्यम स्तर के 60-70 गांव हैं तो दो-तीन सेक्टर लेने पर मॉडल के अंतर्गत पांच हजार परिवार परोक्ष-अपरोक्ष रूप से उत्पादन क्षेत्र में जुड़ जाते हैं एवं अपनी आय बढ़ा सकते हैं। यदि दूध सेक्टर का उदाहरण लें तो स्थानीय आवश्यकता के बाद बचा हुआ दूध मध्यम स्तर के गांव में इकट्ठा कर प्रसंस्कारित कर बेचा जाए तो उसकी मात्रा तहसील स्तर पर दस हजार लीटर प्रतिदिन से अधिक हो जाती है। जब दूध का व्यवसाय किया जाए तो उसके साथ पशुपालन, उन्नत चारा आपूर्ति, पशुआहार, बंजर भूमि पर उन्नत विधि से चारा उत्पादन आदि स्वत: ही जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार अन्य सभी सेक्टरों में उद्यम एवं रोजगार संभव हैं जो स्थानीय कामगारों, किसानों, मजदूरों द्वारा संगठित रूप से मिलकर किया जा सकता है। इसके लिए धन की व्यवस्था प्रारंभिक स्तर पर विभिन्न बैंकों या सरकारी योजनाओं के अंतर्गत की जा सकती है जिसे कमाई होने के उपरांत लौटाया जा सकता है।

मध्यम स्तर के गांव पर प्रस्तावित मॉडल का प्रारूप चित्र में दर्शाया गया है। इसके अनुसार गांव के पशुधन को उन्नत कर उसकी एक गोशाला स्थापित की जाए तथा उससे मिलने वाले गोबर से बायोगैस पैदा कर विद्युत उत्पादन किया जाए जिससे ऊर्जा आपूर्ति हो। बायोगैस की खाद से पौधशाला तैयार हो तथा उससे बंजर भूमि का विकास हो, फल, सब्जी, चारा तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन स्थानीय स्तर पर हो। आवश्यकता से अधिक उत्पाद का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण कर बेचने का नेटवर्क स्थापित हो तथा गुणवत्ता पर नियंत्रण हो। लाभ का अधिकांश भाग पैदा करने वाले व काम करने वाले को मिले। इस मॉडल पर आधारित एक अध्ययन के अनुसार एक 40,000 परिवारों वाले तहसील क्षेत्र में दस हजार से अधिक परिवारों को इन व्यवसायों/उद्यमों से जोड़ा जा सकता है जिससे लाभ कमाकर वे अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं। ❑

(लेखक ग्रामीण विकास एवं प्रौद्योगिकी केंद्र, आईआईटी में प्रोफेसर हैं)

कृपया ध्यान दें

योजना का जून 2005 अंक जल प्रबंधन पर केंद्रित होगा। इस अंक में राजेंद्र सिंह तथा वंदना शिवा सहित अनेक विचारकों और समाजसेवियों के आलेख शामिल होंगे।

अपनी प्रति के लिए स्थानीय विक्रेता से संपर्क करें, अथवा इस पते पर लिखें -

विज्ञापन एवं प्रसार व्यवस्थापक
प्रकाशन विभाग
ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम
नई दिल्ली-110066

Be with the Performer!

IAS 2005-06
ADMISSION NOTICE

OUR TOPPERS

ARSHDEEP SINGH
IAS 3rd Topper

"I found guidance from *Dr. Majid Husain* at CIVILS INDIA very useful one. CIVILS INDIA provides good environment for studying Optionals and General Studies."
Arshdeep Singh

"With labour and commitment Proper guidance matters the most which I got at CIVILS INDIA"
Shurbir

SHURBIR SINGH
IAS 4th Topper

OTHER RESULTS

138th - Dinesh Kumar
145th - Dheeraj Garg
252nd - Shyam Kanu Mohanta
318th - Punam
402nd - Babulal Sonal

OUR HIGHEST IN 2003
Geog.-362; G.S.-361; Essay-142; Interview-220

We offer the most time-tested and performance-oriented classroom courses in India (Eng. & हिन्दी)

GEOGRAPHY by Prof. Majid Husain
Registration Open/Screen Test: 25.5.05/Classes Start June Ist Week

GEN. STUDIES by Dr. Ramesh Singh

ECONOMY by Dr. Ramesh Singh

समाजशास्त्र by Dr. S.S. Pandey

All courses commencing FIRST WEEK OF JUNE
**Registration Open*

Important Books for PT & Mains :

Geography Workbook MAJID HUSAIN

भूगोल वर्कबुक माजिद हुसैन

General Geography and Geography of India MAJID HUSAIN

Now available at Bookstalls

CIVILS INDIA
A Quality Institute for IAS
A/12-13, 202-203, Ansal Building, Behind Batra Cinema, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9
Ph.: 27652921, 27651344, 9810553368, 9818244224

निष्कर्ष Education System NES

मुख्य परीक्षा का दूसरा सत्र 15 जून से आरम्भ

राजनीति विज्ञान
द्वारा
नवाब सिंह सोमवंशी

दर्शन शास्त्र
द्वारा
यशवंत सिंह

सामान्य अध्ययन
विशेष टीम द्वारा

नामांकन 20 मई से आरम्भ

कक्षाएं - 15 जून - 20 सितम्बर तक
टेस्ट - प्रत्येक यूनिट के समाप्त होने पर
रिवीजन - 25 सितम्बर से 5 अक्टूबर

NES *Where Success is always yes*

011-55863622
09868333384

ग्रामीण समुदाय और प्रति संरक्षण से जुड़ी लघु खनिज नीति

○ भारत डोगरा

राष्ट्रीय खनन नीति की चर्चा चलने पर प्राय: तेल, कोयले, लौह अयस्क जैसे व्यापक महत्व के खनिजों की चर्चा अधिक होती है और उन लघु खनिजों की बात पीछे पड़ जाती है जिनसे संबंधित नीतियां दसियों हजारों गांवों व कस्बों की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को नजदीकी तौर पर प्रभावित करती हैं। तरह-तरह के पत्थर और बालू, चूना, खड़िया मिट्टी जैसे लघु खनिजों का दोहन इस समय अल्पकाल में अधिकाधिक दोहन के ठेकेदारी दृष्टिकोण से हो रहा है जिसमें मजदूरों की भलाई, पर्यावरण की रक्षा, स्थायी रोजगार की उपलब्धि इन सभी सार्थक उद्देश्यों की उपेक्षा हो रही है और कई स्तरों पर भ्रष्टाचार पनप रहा है। चाहे चित्रकूट/भरतकूप (बुंदेलखंड) के पास का खनन हो या टिहरी गढ़वाल में कटाल्दी गांवों का विवाद (उत्तरांचल) हो, चाहे शंकरगढ़ (जिला इलाहाबाद) की सिलिका खनन का मामला हो या दून घाटी के पुराने विवाद, इन सभी में स्थानीय गांववासियों के हितों की उपेक्षा, पर्यावरण के दीर्घकालीन विनाश और भ्रष्टाचार के खेल के ऐसे उदाहरण सामने आते हैं जिन्हें दूर करने के लिए लघु खनिज संबंधी एक समन्वित और संतुलित नीति अपनाना जरूरी है।

विभिन्न क्षेत्रीय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए लघु खनिज प्राप्त करने के तौर-तरीके व तकनीक उनके अनुरूप होने चाहिए। उदाहरण के लिए उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश के अस्थिर और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में डायनामाइट और भारी मशीनों के प्रयोग से होने वाला खनन बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इन पर्वतीय क्षेत्रों में खनन के मामले में बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है अन्यथा दीर्घकालीन सामाजिक दृष्टि से जो हानि होगी वह अल्पकालीन लाभ से कहीं अधिक है। किसी जगह खनिज उपलब्धि का अर्थ यह नहीं है कि वहां खनन अवश्य ही हो। इस खनिज के दोहन का आसपास के क्षेत्र के खेत, वन, चरागाह, जल-स्रोत पर क्या असर पड़ेगा, इसे ध्यान में रखकर ही यह निर्णय लिया जा सकता है कि यहां खनन कार्य हो या न हो, अथवा यदि हो तो किन तौर-तरीकों से हो। सामान्यत: ऐसे क्षेत्रों में हाथ के औजारों वाले श्रम सघन तकनीक ही उपयुक्त हैं। जब गांववासी स्वयं इन श्रम-सघन तकनीकों से कार्य करते हैं तो चाहे खनन कार्य बेशक धीरे-धीरे आगे बढ़े, पर इससे विनाश की संभावना कम होती है। साथ ही जहां गड्ढे बन रहे हों या धरती को अन्य क्षति हो रही हो, वहां वृक्षारोपण जैसे उपायों से साथ-साथ उपचार-कार्य भी किया जा सकता है। इस तरह के उपचार-कार्य को खनन का जरूरी हिस्सा बनाया जाना चाहिए। यह कार्य उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ठीक से हो सकता है जो अपने दिल से गांव के खेत, चरागाह, वन, जल-स्रोत आदि की रक्षा करना चाहते हैं।

वैसे तो पर्यावरण के संरक्षण का ध्यान रखना हर क्षेत्र के खनन कार्य के लिए आवश्यक है, पर यह उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए तो सबसे निर्णायक पक्ष है। आज से कई वर्ष पहले जब दून-घाटी के कई गांवों में पर्यावरण संरक्षण की पूरी तरह उपेक्षा कर विनाशकारी तौर-तरीकों से खनन कार्य किया गया था, तो इन गांवों के खेत, वन, जल-स्रोत सब उजड़ गए थे। यहां के कुछ गांवों पर खनन कार्य में डायनामाइट के अधिक उपयोग के बाद पत्थर इस तरह गिरते थे जैसे किसी युद्धक्षेत्र के गांव में गोले बरस रहे हों। कुछ गांवों का तो अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया था। इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के खनन कार्य संबंधी निर्देशों से इन गांवों को राहत मिली। दूसरी ओर, यदि आरंभ से ही खनन कार्य विशेष रूप से चुने हुए अनुकूल स्थानों पर श्रम-सघन उपायों से किया जाता व साथ-साथ प्रकृति के उपचार के उपाय अपनाए जाते तो इतनी तबाही की नौबत कभी न आती।

बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में, विशेषकर जो सबसे निर्धन समुदाय हैं, जैसे सहरिया व कोल उनकी समितियों या स्वयं सहायता समूहों को यदि खनन के अधिकार मिले तो इससे उनके आर्थिक उत्थान की महत्वपूर्ण संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। पर इस तरह के प्रयासों में भी पर्यावरण संरक्षण पर तो ध्यान देना ही होगा।

कुछ क्षेत्रों में तो यह देखा गया है कि खनन कार्य का मलबा काफी दूर तक नहरों व नदियों में जाकर सिंचाई का संकट उत्पन्न करता है। इस तरह की क्षति की संभावनाएं उन परिस्थितियों में ही अधिक बढ़ती हैं जब राजनीतिक पहुंच रखने वाले ठेकेदार अपनी मनमानी से खनन करते हैं व पर्यावरण बचाने के नियमों की कोई परवाह नहीं करते। इस स्थिति में कितने ही किसानों की जो क्षति होती है, मजदूरों का जो शोषण होता है, प्रकृति का जो विनाश होता है उन सबको उपेक्षित कर दिया जाता है।

खनन के संदर्भ में कई बार पर्यावरण संरक्षण व रोजगार के हितों के टकराव की बात की जाती है, पर यदि अल्पकालीन रोजगार के स्थान पर स्थायी आजीविका पर वांछित ध्यान दिया जाए तो यह टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। गांववासियों की स्थायी

आजीविका का आधार उनके खेत, चरागाह, जल-स्रोत व वन हैं। इनमें वर्तमान पीढ़ियों को ही नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों को भी रोजी-रोटी का आधार मिलेगा। इसके अतिरिक्त अन्य रोजगारों के उपाय के बारे में सोचना भी जरूरी है, पर यह उपाय ऐसे नहीं होने चाहिए जो स्थायी आजीविका पर चोट पहुंचाएं अथवा खेत, वन, चरागाह, जल-स्रोत आदि को क्षतिग्रस्त करें।

खनन कार्य का उस रूप में ही स्वागत है जिसमें वह खेती, पशुपालन और वानिकी के टिकाऊ रोजगारों को क्षति न पहुंचाए। इस तरह की तकनीकें उपलब्ध हैं। वे प्राय: श्रम सघन तौर-तरीकों से जुड़ी हुई हैं। श्रम-सघन, हाथ के औजारों वाले उपाय स्थानीय गरीब लोगों को अधिकतम रोजगार दे सकते हैं साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी उचित हैं।

दूसरी ओर, कई दशकों से ऐसी प्रवृत्तियां पनपती रही हैं कि कुछ शक्तिशाली तत्व बड़े-बड़े क्षेत्रों के लघु खनिज अधिकार तरह-तरह के वैध-अवैध तरीकों से हथिया लेते हैं। जितने क्षेत्र के खनन का हक उन्हें मिलता है, अपने बाहुबल से वे वास्तव में उससे कहीं अधिक क्षेत्र में खनन करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की एक बड़ी भूमिका रहती है। कई जगह पैसा बांटते हुए ठेकेदार कम से कम समय में अधिक से अधिक खनिज दोहन करने की चेष्टा करता है जिससे प्रकृति बुरी तरह बर्बाद होती है। अधिकांश स्थानों पर मजदूरों की हालत बहुत दयनीय होती है। उन्हें न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिलती और दुर्घटनाओं की स्थिति में मुआवजा भी नहीं मिलता है। कई मजदूरों के मरने और घायल होने के समाचार खनन क्षेत्र से बाहर ही नहीं पहुंचते हैं। हरियाणा जैसे समृद्ध राज्य में भी बंधक मजदूरी जैसे हालात में काम करने वाले खनन मजदूरों के कई समाचार मिलते रहे हैं।

लघु खनिज दोहन यदि आर्थिक मुनाफे की दृष्टि से देखा जाए तो उतना 'लघु' क्षेत्र नहीं है और इसमें कई स्तरों पर काफी भारी-भरकम आर्थिक स्वार्थ जुड़े हैं। कुछ समय पहले टिहरी गढ़वाल जिले के कटाल्दी गांव में कई गांववासियों और पर्यावरणविदों ने अनेक तथ्यों और खनन-स्थल की जांच के आधार पर जिस खनन को बहुत विनाशकारी सिद्ध किया था, उसके अल्पकालीन लीज पट्टे को रद्द करने के स्थान पर उसे दीर्घकालीन बना दिया गया। फिर उन प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ताओं को तरह-तरह से सताने व परेशान करने का सिलसिला आरंभ हुआ जो चिपको आंदोलन में बहुत सार्थक रचनात्मक भूमिका निभा चुके हैं। इस तरह से स्थानीय विरोध को दबाने-कुचलने का प्रयास कई जगहों पर किया जाता है जिससे एक जनपक्षीय, प्रकृति-रक्षक लघु खनिज नीति की मांग उभर न सके।

किन्तु राष्ट्रीय स्तर पर लाखों मजदूरों किसानों के हितों की रक्षा और प्रकृति संरक्षण, दोनों की मांग यह है कि एक ऐसी संतुलित लघु खनिज नीति विकसित की जाए जो लघु खनिज दोहन को संकीर्ण स्वार्थों के दायरे से बाहर निकालकर उसे गांव-समुदाय की भलाई और पर्यावरण संरक्षण के व्यापक हितों से जोड़ सके। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

Delhi, Now in Patna

IAS/PCS

नामांकन जारी

सामान्य अध्ययन

By:

(Medium : हिन्दी + ENG)

शैलेन्द्र सिंह (Expert from Delhi)

(Renowned for Analytical Approach)

Features:-

- व्याख्यान पर बल
- Regular Test
- सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के नोट्स
- Personality Development Programme
- Integrated Programme for Success (I.P.S.)
- नियमित वाद-विवाद
- Emphasis on Answer formating

अन्य विषय - हिन्दी साहित्य, इतिहास, निबंध

Shailendra Singh

(With Proven Capacity) **Cell: 9431052949**

THE ZENITH

(An Innovative Institute for I.A.S.)

G-4, CHANDRAKANTA APARTMENT, OPP BATA PANDUI KOTHI LANE, BORING ROAD, PATNA-800001, Mob: 9431052949

Weekly Classes in **"PRABHA"**, Delhi & Allahabad, Cell: (1) Delhi - 9810651005 (2) Allahabad - 9839746184

फ्लाई ऐश - जैव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रबंधन

○ राजीव कुमार सिंह

फ्लाई ऐश से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए विकासशील देशों के वैज्ञानिक कार्यरत हैं। इन सभी परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य फ्लाई ऐश लैंडफिल्स (भराव) की भूमि का शोधन व सुधार करके क्षेत्रीय नागरिकों के लिए प्रदूषण मुक्त स्वस्थ पर्यावरण निर्माण करना है। फ्लाई ऐश में उपलब्ध पोषक तत्वों का उपयोग पौधों की वृद्धि व उत्पादकता बढ़ाने में किस प्रकार किया जा सकता है इस दिशा में भी महत्वपूर्ण शोधकार्य चल रहा है

भौतिकवाद की अंधाधुंध दौड़ में तथाकथित विकास के लिए मानव समुदाय के बढ़ते कदम पर्यावरण संतुलन के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर रहे हैं जिससे वातावरण में प्रदूषक तत्वों की निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्तमान में मानव जीवन के रहन-सहन के स्तर में उत्थान तथा प्राकृतिक तथा औद्योगिक संसाधनों को जुटाने की दिशा में विद्युत ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान है। देश में बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग तथा सीमित पेट्रोलियम पदार्थों को देखते हुए गत कई वर्षों से कोयले का प्रयोग विद्युत उत्पादन में अधिकाधिक किया जा रहा है। राष्ट्रीय ऊर्जा नीति, 1981 के अनुसार हमारे देश में ऊर्जा का प्रमुख आधार कोयला है। क्योंकि देश के कुल कोयला उत्पादन का 64 प्रतिशत हिस्सा विद्युत निर्माण में इस्तेमाल कर लिया जाता है। आज हमारे देश में कोयला आधारित विद्युत मांग का लगभग 60 प्रतिशत भाग इन्हीं ताप बिजली घरों से पूरा होता है। परंतु इस विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया से पर्यावरण दूषित होता है और एक अनुमान के अनुसार खनिज तत्वों से उत्पन्न अवशिष्टों में कोयले के जलने से उत्पन्न प्रदूषकों की भागीदारी लगभग 90 प्रतिशत है।

तापीय विद्युत गृहों से उत्पन्न प्रदूषक मुख्यत: दो प्रकार के होते हैं। एक, जो भारहीन होते हैं जैसे - शोर, उष्मा तथा ताप; दूसरे, जिनका भार होता है जैसे - गैस, द्रव व ठोस प्रदूषक। इनमें मुख्य वायु प्रदूषक - CO_2, CO, SO_2, NO, NO_2 इत्यादि आसपास की वनस्पतियों तथा मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इन प्रदूषित क्षेत्रों में कभी-कभी जाड़े के दिनों में धुंध, कुहरा तथा अम्लीय वर्षा की घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। तापघरों से विसर्जित द्रव तथा ठोस प्रदूषक फ्लाई ऐश (उड़न राख) में अनेक प्रकार की विषैली धातुएं रहती हैं जो हमारे पर्यावरण को अनेक प्रकार से दूषित करती हैं। इन क्षेत्रों में अधिकांश लोग श्वास रोगों से पीड़ित देखे जा सकते हैं। फ्लाई ऐश में मौजूद सिलिकॉन की अधिक मात्रा श्वास नली में चले जाने से सिल्कोसिस नामक रोग हो जाता है। वास्तव में उड़न राख एक जटिल मिश्रण होती है जो या तो महीन राख जैसी लगती है या कठोर रेतीले कणों जैसा अपघर्षी पदार्थ जो पानी के साथ गरम पिघली हुई राख के संपर्क से बनती है। ये ठोस प्रदूषक तापीय विद्युत गृहों के आसपास अव्यवस्थित रूप में फेंक दी जाती हैं परंतु कुछ आधुनिक इकाइयों द्वारा लगभग 90 प्रतिशत राख तो नजदीक के फ्लाई ऐश भराव 'तालाब' में इकट्ठा की जाती है। फिर भी 10 प्रतिशत भाग चिमनियों द्वारा आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। इस प्रकार बिजली की कीमत हमारे पर्यावरण को काफी नुकसान सहकर चुकानी पड़ती है।

फ्लाई ऐश

फ्लाई ऐश को सीमेंट एवं कंक्रीट की शब्दावली के रूप

में परिभाषित किया जा सकता है। कोयले के दहन के उपरांत विघटित अवशिष्ट पदार्थ को फ्लाई ऐश अथवा उड़न राख कहते हैं जो कि अग्नि कणों से उड़ाकर लाई जाती है। यह एक ऐसा उत्पाद है जो कि कोयले के दहन के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा बनाने वाले संयंत्रों से निकलता है।

वर्गीकरण

फ्लाई ऐश को उसके पैतृक पदार्थों के गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

वर्ग एफ फ्लाई ऐश एंप्रेसाइट एवं व्यूटिमिनस कोयले के जलने उपरांत अंतिम उत्पाद को कहते हैं।

वर्ग सी फ्लाई ऐश का निर्माण लैग्नाइट एवं सबव्यूटीमिनस कोयले के जलने के उपरांत होता है।

फ्लाई ऐश के विशिष्ट गुण

फ्लाई ऐश के अणु स्फेराइडल आकार के होते हैं। इनकी माप 250 माइक्रोमीटर होती है। इनके अणुओं की मैकेनिकल क्षमता अत्यधिक होती है। इसकी सापेक्षिक क्षमता सीमा 3 से 0.6 होती है। इसका गलनांक 1000^0 सेल्सियस होता है।

फ्लाई ऐश का हरित शोधन जैव प्रौद्योगिकी प्रबंधन द्वारा

आज बढ़ती हुई बिजली की मांग के साथ-साथ फ्लाई ऐश की मात्रा निरंतर बढ़ती जा रही है। इसमें निहित विषैली धातुएं कृषि उपज, भूमि, पौधों तथा मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। आज हम सब प्रदूषणजनित बीमारियों से अच्छी तरह परिचित हैं। ये विषाक्त धातुएं रिसाव द्वारा भूमिगत जल को भी प्रदूषित करती हैं। फ्लाई ऐश प्रभावित क्षेत्रों में विषाक्त कुएं देखे जा सकते हैं। जो तापीय गृह 'फ्लाई ऐश तालाब' जगह की कमी से नहीं बना पाते वहां से या फिर इन तालाबों से बरसात के दिनों में उड़न राख बहकर नदियों तथा अन्य जलस्रोतों में पहुंच जाती है और जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इस प्रकार पानी में मिली ये विषाक्त धातुएं भोजन शृंखला द्वारा कई गुना बढ़कर अंत में मानव स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालती हैं। फ्लाई ऐश का उत्पादन प्रतिदिन इतना अधिक है कि यदि समय रहते इसका उपचार व प्रबंधन न किया गया तो यह एक गंभीर समस्या बन सकती है।

आजकल औद्योगिक अवशिष्टों का शोधन या बिना किसी शोधन द्वारा पुन: प्रयोग करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। मौजूदा स्थिति में फ्लाई ऐश का उपयोग निर्माण सामग्री बनाने में इतना बढ़ता जा रहा है कि ये बहुत महंगे बिक रहे हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की तथा अन्य सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं ने फ्लाई ऐश से ईंटें बनानी शुरू की हैं जिनका उपयोग निर्माण कार्य में किया जा रहा है। परंतु क्या यह सब पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित है? ऐसी विषाक्त ईंटें लंबे अंतराल के बाद भारी संकट पैदा कर सकती हैं। इसका सबक हम जापान में हुए महाव्याधि कैंसर से ले सकते हैं जिसमें भवन निर्माण के लिए क्रोमियम युक्त ईंटों का प्रयोग किया गया था जो कि एक औद्योगिक इकाई के अवशिष्ट से बनी थीं। इसके अलावा फ्लाई ऐश का पुन: प्रयोग पोर्टलैंड पोंजोलाना, सीमेंट, सेल्यूलर कंक्रीट, बोल्डर, चूना, सड़क निर्माण एवं खानों को भरने तथा बंजर व कृषि भूमि सुधार में बहुतायत से किया जाता है। जहां एक तरफ फ्लाई ऐश में मौजूद पोषक तत्व उपज में वृद्धि करते हैं वहीं इसका प्रयोग मिट्टी की रासायनिक व भौतिक दशा खराब करने के अलावा इसमें मौजूद सूक्ष्म जीवों को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार मिट्टी में कुछ आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस प्रकार फ्लाई ऐश मिश्रित मिट्टी में उगने वाले पौधे विषैली धातुएं संचित करके विषाक्त हो जाते हैं और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा करते हैं।

फ्लाई ऐश से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए विकासशील देशों के वैज्ञानिक कार्यरत हैं। इन सभी परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य फ्लाई ऐश लैंडफिल्स (भराव) की भूमि का शोधन व सुधार करके क्षेत्रीय नागरिकों के लिए प्रदूषण मुक्त स्वस्थ पर्यावरण निर्माण करना है। फ्लाई ऐश में उपलब्ध पोषक तत्वों का उपयोग पौधों की वृद्धि व उत्पादकता बढ़ाने में किस प्रकार किया जा सकता है इस दिशा में भी महत्वपूर्ण शोधकार्य चल रहा है। फ्लाई ऐश में अन्य उद्योगों के अवशिष्ट जैसे - चीनी मिल का मलबा, भोज्य पदार्थ बनाने वाले उद्योगों के अवशिष्ट इत्यादि मिलाकर इसकी उर्वरक क्षमता बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। फ्लाई ऐश की जांच निर्धारित मापक विधियों द्वारा करने पर पता चलता है कि इसमें सभी पादप पोषक तत्वों की मौजूदगी के बावजूद नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी है जो प्रारंभिक चरण में पौधों की वृद्धि व उत्पादन को प्रभावित करती है। फ्लाई ऐश में इन मुख्य तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल *एनाबीना डोलीएलम* में फ्लाई ऐश पर उगने की क्षमता पाई गई। इस शैवाल के प्रयोग से फ्लाई ऐश में नाइट्रोजन, फास्फोरस व कार्बनिक रसायन की मात्रा क्रमश: 0.03, 0.02 तथा 0.113 प्रतिशत तक की वृद्धि पाई गई तथा फ्लाई ऐश के पीएच एवं ईसी में भी गुणात्मक सुधार प्रतीत हुआ जो पौधों के प्रारंभिक रोपण में काफी सहायक सिद्ध हुआ। परंतु ये सभी प्रयोग प्रयोगशालाओं में किए गए हैं जिनके फ्लाई ऐश भराव पर असफल होने का डर है। इसका मुख्य कारण फ्लाई ऐश की कम जल ग्रहण करने की क्षमता है। नील हरित शैवालों की वृद्धि के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जहां पानी की उचित व्यवस्था हो वहां के लिए यह तकनीक सर्वथा उपयुक्त है। इस प्रकार जैविक उपचार के द्वारा फ्लाई ऐश को और ज्यादा उर्वरक बनाया जा सकता है।

पौधों में प्रदूषित पानी से भारी धातुएं निकालने का गुण पाया जाता है, इनकी जड़ें मिट्टी में आसानी से चली जाती हैं तथा ये भू-क्षरण को कम करके स्वस्थ पर्यावरण बनाने में सहयोग करते हैं। फ्लाई ऐश से जुड़ी पर्यावरण समस्याओं से निपटने के लिए हमारे पर्यावरणविदों ने इन भरावों पर वृक्षारोपण करवाने का कार्य शुरू किया है तथा इस परियोजना में जैव प्रौद्योगिकी का सहारा लिया

जा रहा है। इसी प्रकार के प्रारंभिक परीक्षण प्रयोगों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में वे पौधे ज्यादा सफल सिद्ध हो रहे हैं। इसके अंतर्गत विशिष्ट प्रकार के राइजोबियम कल्चर का उपयोग करके पौधों को अधिक प्रतिरोधी बनाया जा रहा है। पौधों द्वारा उपचार की इस विधि द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी में फ्लाई ऐश से भारी व विषैली धातुएं निकालने के लिए प्रदूषण प्रतिरोधी तथा अत्यधिक धातु संचित करने वाले पौधों का भी उपयोग किया जाएगा जिससे वे मानव स्वास्थ्य की रक्षा करने में सहयोगी होंगे।

मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों राइजोबियम, ब्राडीराइजोबियम तथा एजोराइजोबियम की विशिष्ट प्रजातियों में दलहनी पौधों व वृक्षों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नोड्यूल बनाने का गुण पाया जाता है। इस गुण का उपयोग फ्लाई ऐश में नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए किया गया। राइजोबियम की विशिष्ट प्रकार की प्रजातियां फ्लाई ऐश भराव पर उगने वाले पौधे से प्राप्त की गईं। इस सूक्ष्मजीवी का स्वभाव सहजीवी होने की वजह से काफी जटिल है। अत: इसे उसी पौधे से निकालकर इसमें फ्लाई ऐश पर बढ़ने की प्रतिरोधी क्षमता विकसित की जा रही है। इस प्रकार बीज प्रजनित पौधों के बीजों अथवा अंकुरों में अनुमोदित विधियों द्वारा विशिष्ट राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करके पौधे तैयार किए जा रहे हैं जो फ्लाई ऐश भराव पर रोपण के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं। इस सस्ती जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार किए गए पौधे से सामान्य पौधों की तुलना में करीब 60 प्रतिशत अधिक जैव भार प्राप्त किया जा सकता है। आज इस प्रकार के वृक्षारोपण कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जा रहा है जिससे यह पता लगाया जा सके कि फ्लाई ऐश की भौतिक व रासायनिक दशा में सुधार हुआ है। वृक्षारोपण चुनाव का आधार सुझाया गया है जैसे कि पौधे देशी हों या विदेशी, परंतु वे जल्दी बढ़ने वाले, अधिक जैव मात्रा पैदा करने वाले, कम पानी की आवश्यकता वाले, अधिक धातु संचय करने वाले तथा वातावरण की दशा में परिवर्तन को सहने वाले होने चाहिए। हमारा इस प्रकार का प्रयास ही फ्लाई ऐश के कुशल प्रबंधन के लिए जरूरी है। पौधों पर आधारित इस जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से ऐसा प्रतीत होता है कि फ्लाई ऐश से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के दीर्घकालीन उपाय किए जा सकते हैं।

उड़न राख में पाए जाने वाले तत्वों की मात्रा (प्रतिशत में)

तत्व/यौगिक	मात्रा प्रतिशत
कार्बन	0.36 - 36.5
कैल्शियम	0.12 -14.5
सल्फर	0.12 - 24.5
सोडियम	0.2 - 0.9
पोटैशियम	2.8 - 3.0
सिलिकॉन	15.5 - 63.8
एल्युमिनियम	9.8 - 58.6
लोहा	2.0 - 26.8
मैंग्नीशियम	0.66 - 4.75
फास्फोरस	0.07 - 47.5
टाइटेनियम	0.1 - 2.8
कार्बोनेट	0.0 - 2.5

स्रोत: स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा जनजागरण, शाखा वायुप्रदूषण, चिनचिनाती, ओहियो, संघटक फ्लाई ऐश, यूनाइटेड स्टेट आफ अमरीका।

कोयला दहन से उत्सर्जित फ्लाई ऐश का उपयोग

1. कृषि योग्य भूमि के सुधार में
   - मृदा की भौतिक अवस्था पर प्रभाव
   - मृदा की रासायनिक अवस्था पर प्रभाव
   - पौधों द्वारा हानिकारक धातुओं का ग्रहण
   - मृदा के सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव
2. वाहित जल के शुद्धीकरण में
3. खनिजों की खुदाई एवं वर्ज्य पदार्थों के सुधार में
4. निर्माण संबंधी कार्यों में

भराव

1. स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र
   - एसपीएम में वृद्धि
   - हानिकारक विषाक्त तत्वों का क्षरण
   - खाद्य श्रृंखला द्वारा जैव स्थिरीकरण
   - वनस्पतियों पर प्रभाव
2. जलीय पारिस्थितिक तंत्र
   - जल की रासायनिक संरचना में परिवर्तन स्थलीय एवं भूमिगत जल
   - जलीय खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव

फ्लाई ऐश के भराव एवं उसके उपयोगों का पर्यावरण पर प्रभाव

रासायनिक गुणों के आधार पर फ्लाई ऐश की गुणवत्ता निर्धारित होती है। इस्तेमाल किए गए कोयले पर एवं ताप विद्युत गृह की क्षमता एवं स्थिति पर भी किसी तरह की उड़न राख में सिलिका, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम के आक्साइड 05 से 99 प्रतिशत के करीब पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त 0.5 से 3.5 प्रतिशत नाइट्रोजन, फास्फोरस, एवं सल्फर पाई जाती है। इसके अतिरिक्त हानिकारक विषाक्त तत्वों में क्रोमियम, लैड, पारा, निकेल, यूरेनियम, आर्सेनिक, बेरियम भी पाए जाते हैं।

उपयोग और गंदगी का गहरा संबंध है। मानव विलासिता की वस्तुएं जितनी जुटाता है प्रदूषण का खर्चा उतना ही बढ़ता जाता है। भारत में विकसित देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति कूड़ा उत्पादन की दर से चार गुना अधिक है और इस प्रकार अवशिष्टों की मात्रा दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। परंतु इस प्रकार के प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि इन ताप गृहों से पैदा होने वाली उड़न राख को पुन: प्रयोग में लाया जा सकता है। अनेक प्रकार की जैविक उपचार विधियों द्वारा इसकी भौतिक व रासायनिक दशा में गुणात्मक परिवर्तन पाया गया। इस फ्लाई ऐश का पुन: शोधन करके पौधों की वृद्धि में प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि इसमें काफी मात्रा में पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। परंतु इसका फिर से पर्यावरणीय खतरा बना न रहे, इसके लिए हम सबको वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देना होगा। इस प्रकार इस जैव प्रौद्योगिकी से इन फ्लाइंग ऐश लैंडफिल्स का वांछित सुधार हो सकता है। ❑

(लेखक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग में हैं)

IAS द हिस्टोरिका PCS

सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी को समर्पित संस्थान

सिविल सेवा परीक्षाओं में इतिहास विषय को विज्ञान के विषयों के समान सर्वाधिक अंकदायी विषयों की सूची में अग्रणी बनाने के अपने संकल्प के साथ 'द हिस्टोरिका' विकास की दिशा में अग्रसर है।

मुख्य परीक्षा में 350+ अंक प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि आप इतिहास के विभिन्न मुद्दों के संदर्भ में प्रचलित विभिन्न विचारों में से सर्वाधिक प्रामाणिक एवं नवीन विचारों/संकल्पनाओं को लिखें।

350+ अंकों की प्राप्ति प्रामाणिक एवं नवीन विचारों के प्रस्तुतीकरण पर ही नहीं अपितु प्रस्तुतीकरण के तरीकों अर्थात् आपके उत्तर लेखन की शैली एवं भाषा पर भी निर्भर करता है।

सफलता प्राप्ति के उपर्युक्त सोपानों के साथ, अपने प्रयास में नये मौलिक, तकनीकों को सम्मिलित करते हुए 'द हिस्टोरिका' नये सत्र की घोषणा करती है:

इतिहास: द्वारा रमेश चन्द्रा
नया सत्र : 05 जून

सामान्य अध्ययन: द्वारा रमेश चन्द्रा एवं अन्य अनुभवी विशेषज्ञ।
नया सत्र : 06 जून

निबन्ध : अगस्त में 15 दिवसीय कार्यक्रम

मुख्य-परीक्षा 'मुख्य-परीक्षा में सफलता विषय के प्रामाणिक ज्ञान तथा उसके सम्यक् प्रस्तुतीकरण पर निर्भर करता है।'

विशेषताएं

- तीन महीने का विस्तृत कार्यक्रम
- प्रत्येक टॉपिक पर व्याख्यान।
- टॉपिक से संबंधित संभावित प्रश्नों का उत्तर-प्रारूप एवं उत्तर लेखन।
- उत्तर लेखन पर विशेष बल, अतिरिक्त कक्षायें।
- प्रत्येक विषय पर विगत वर्षो के प्रश्नों का विश्लेषण।
- यू0 पी0 एस0 सी0 पद्धति पर साप्ताहिक मॉडल टेस्ट
- सम्पूर्ण कम्प्यूटराईज्ड अध्ययन सामग्री।

नामांकन प्रारम्भ

विशेष I.A.S. -2003 एवं I.A.S. -2004 इतिहास (मुख्य परीक्षा) में संस्थान में अध्ययन कराये गये प्रश्नों में क्रमशः 12 एवं 14 प्रश्न (कुल 16) पूछे गये। प्रश्नों से संबंधित टॉपिक पर व्याख्यान प्रश्नों का उत्तर प्रारूप, उत्तर लेखन एवं विद्यार्थियों द्वारा उन पर लेखन कार्य भी सम्पन्न हुआ।

राष्ट्रीय पत्राचार प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम का संयोजन दूर स्थित विद्यार्थियों एवं क्लास-कोचिंग लेने में असमर्थ विद्यार्थियों को दृष्टि में रखकर तैयार किया गया है।

विशेषताएं:

- अध्ययन सामग्री को मुख्य परीक्षा 2005 के लिए संशोधित कर दिया गया है।
- विद्यार्थियों के प्रश्नोत्तर जाँच की डाक द्वारा व्यवस्था।
- कार्यक्रम में नामांकित छात्रों की समस्याओं का सीधे 'रमेश चन्द्रा' सर के द्वारा साप्ताहिक निवारण।

विषय : सामान्य अध्ययन, इतिहास

फीस: मुख्य परीक्षा (प्रति विषय) - 2500/- रुपये मात्र। प्रारम्भिक परीक्षा (प्रति विषय) - 2000/- मात्र।

नोट: कार्यक्रम में नामांकन के लिए दिल्ली में भुगतान हेतु बैंक ड्राफ्ट "RAMESH CHANDRA" के नाम निम्न पते पर भेजें।

2063 (BASEMENT), OUTRAM LINES,
(IN THE LANE BEHIND D.A.V. PUBLIC SCHOOL) KINGSWAY CAMP,
DELHI- 110009 TEL.: (011) 55153204 CELL : 9818391120

समाजशास्त्र के लिए
सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रतिबद्ध संस्थान
आस की ओर से मुख्य परीक्षा-2005
में सफल प्रतियागियों को

बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ

IAS Mains 2005

Aarti Singh Parihar
D.K. Pandey,
Manoj K. Raghuwanshi
Arvind Aggrawal
Ranjan Prakash
Swapna Kishore
Lave Kumar
Manoj Sharma

Uttaranchal PCS (M)

Manish Kumar
Sangeeta Bhatt
Veerbala Arora

U.P. Lower Sub-Ordinate

Rakesh Kumar
Vijeet Singh
Jyoti Singh

Chattishgarh PCS (M)

Richa Mishra

समाज शास्त्र
द्वारा धर्मेन्द्र

रूपरेखा :

- अध्यापन की शुरुआत सतही रूप से।
- सभी छात्रों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान।
- सम्पूर्ण पाठ्यक्रम की वैज्ञानिक संरचना।
- ईक्नॉमिक एवं पॉलिटिक्ल वीक्ली, योजना एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं से समृद्ध क्लॉस नोट्स।
- पर्याप्त लेखन अभ्यास।
- नवीनतम समाज शास्त्रीय अध्ययन, विवेचना के साथ।

नया बैच प्रारम्भ
1st week of June, 2005

AAS
AN IAS ACADEMY

302, A-12-13, Top Floor, Ansal Building, Mukherjee Nagar, Delhi-9.
Ph.: 55152590 Cell.: 9891567782, 9312280722

खबरों में

सूचना प्रौद्योगिकी की दौड़ में भारत 34वें स्थान पर विश्व आर्थिक फोरम की विश्व सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट में भारत ने अपनी स्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया है। पिछले वर्ष के 45वें स्थान से प्रगति कर अब यह 39वें स्थान पर पहुंच गया है।

इस रिपोर्ट में विभिन्न देशों को इस आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है कि विश्वभर में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए विकास का लाभ उठाने में वे कितने सफल रहे हैं। इसे इंटरनेट सुविधा की वहनीयता, टेलीफोन कनेक्शन प्रभार, गणित तथा विज्ञान शिक्षण की गुणवत्ता, सरकार की प्राथमिकता तथा आईसीटी हासिल करने के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

तीन सालों तक शीर्ष पर रहने के बाद अमरीका इस रिपोर्ट में पांच स्थान नीचे आ गया है और सिंगापुर शीर्ष पर पहुंच गया है। सिंगापुर इस स्थान पर पहली मर्तबा पहुंचा है। रिपोर्ट में सिंगापुर को उपरोक्त सभी मानदंडों पर सबसे बेहतर निष्पादन करने वाला माना गया है। अमरीका का स्थान नीचे जाने में उसके वास्तविक निष्पादन में ह्रास का उतना योगदान नहीं है जितना कि उसके प्रतियोगियों की गुणवत्ता में निरंतर सुधार का विश्व सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट में 104 देशों की अर्थव्यवस्था को कवर किया गया है। लगातार चौथी बार प्रकाशित यह रिपोर्ट दुनियाभर में देशों के विकास और प्रतिस्पर्द्धा पर सूचना प्रौद्योगिकी, के प्रभाव के आकलन का अग्रणी मानक बनकर अभरा है।

● आंध्र प्रदेश की स्वसहायता समूहों को 3 प्रतिशत की ब्याज दर से ऋण मिलेगा

आंध्र प्रदेश सरकार ने स्वसहायता समूहों के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए उन्हें 3 प्रतिशत की ब्याजदर से बैंक ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है।

ब्याज की यह छूट ड्वाक्रा तथा तेलुगु के एक समन्वित कार्यक्रम इंदिरा क्रांति पदम के तहत दी जा रही है। स्वसहायता समूह की दी जाने वाली ब्याज सब्सिडी के भुगतान की विधि के बारे में सरकार ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। यह सब्सिडी अधिकतम छह प्रतिशत ब्याज की सीमा तक दी जाएगी।

तत्काल प्रभाव से क्रियान्वित की जाने वाली यह योजना बैंकों द्वारा पहली जुलाई, 2004 के बाद से दिए गए सभी ऋणों पर लागू होगी।

पहली जुलाई, 2004 के बाद से बैंक ऋण लेने वाले स्वसहायता समूहों की संख्या लगभग 2,24,635 है जिन्होंने करीब 917,84 करोड़ रुपये का बैंक ऋण लिया है। इनमें से मूलधन तथा ब्याज राशि का नियमित भुगतान करने वाले सभी स्वसहायता समूह यह लाभ प्राप्त कर पाएंगे।

● राज्यों को वैट सीमा के संशोधन का अधिकार मिला

अधिकार प्राप्त समिति ने राज्यों को अप्रैल 2005 से मूल्यवर्द्धित कर व्यवस्था के अंतर्गत आने के लिए व्यापारियों के लिए निर्धारित अधिकतम छूट सीमा को संशोधित कर 10 लाख रुपये बढ़ाने का विकल्प दिया है। वैट लागू करने के पहले वर्ष में खाद्यान्नों और बीजों को भी नए कर से मुक्त रखा जा सकता है।

● बीमा कानूनों की समीक्षा के लिए पैनल

सरकार विधि आयोग तथा आईआरडीए से प्राप्त जानकारियों के आधार पर बीमा संबंधी व्यापक कानून बनाने के बारे में संकल्पबद्ध है। आईआरडीए ने विधि आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन तथा बीमा अधिनियम में संशोधन सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया है।

के.पी. नरसिंह की अध्यक्षता में गठित यह पैनल निवेश (धारा 27, 27क तथा 27ख), परिसंपत्तियों की पर्याप्तता (धारा 64वीए), बीमा सर्वेयर (धारा 64यूए तथा 64यूए तथा 64यूएलए) एवं अंशधारक कोष और पॉलिसी धारक कोष (धारा 49) से संबंधित प्रावधानों का अध्ययन करेगा। समिति से 30 अप्रैल तक अपनी संस्तुतियां दे देने का आग्रह किया गया है।

● मिजो लोगों ने सुनामी प्रभावितों के लिए बांस भेजा

मिजोरम वासियों ने एक खास राहत सामग्री

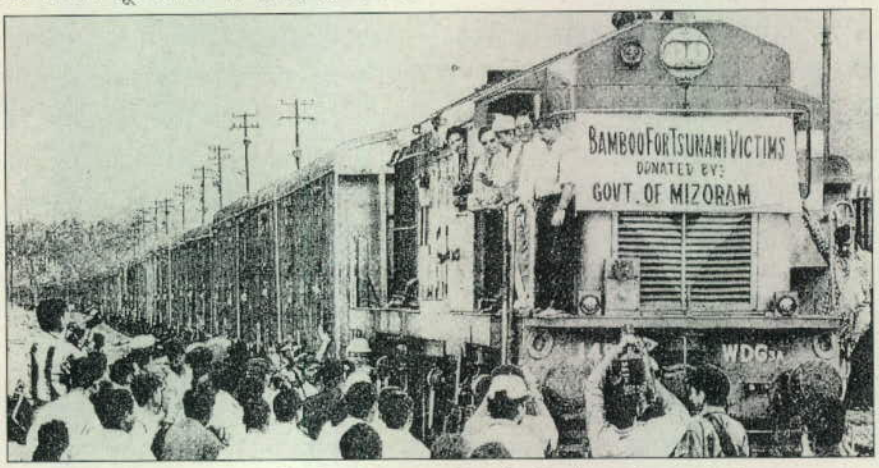

सुनामी प्रभावितों के लिए बांस की बड़ी खेप ले जाती मालगाड़ी

भेजी है। उन्होंने तमिलनाडु के सुनामी प्रभावितों के लिए आश्रय बनाने हेतु बांस भेजा है।

मिजोरम से 1,27,043 बांसों की पहली खेप औपचारिक रूप से एक मालगाड़ी में भरकर भेजी गई है जिसकी व्यवस्था नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने की। मिजोरम के लगभग 10 कारीगर सुनामी प्रभावित लोगों को बांस से घर बनाने का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने चेन्नई तक नि:शुल्क मालवहन की सुविधा प्रदान की है।

● राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना के लिए विश्व बैंक ने 50 करोड़ डॉलर देने का प्रस्ताव किया

विश्व बैंक अगले चार वर्षों के दौरान भारत के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना के लिए 50 करोड़ डॉलर प्रदान करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गया है। इसने परियोजना की संकल्पना का अनुमोदन कर दिया है तथा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना को समर्थन देने के बारे में हरी झंडी दिखा दी है।

इस योजना में मिशन मोड के रूप में 25 परियोजनाओं की पहचान की गई है जिनमें दस राज्य क्षेत्र में, आठ केंद्रीय क्षेत्र में तथा बाकी सात समन्वित रूप में हैं।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना का जोर ग्रामीण नागरिकों के सशक्तीकरण बेहतर और प्रभावी शासन, निजी क्षेत्र के विकास और संभावनाओं को बढ़ावा तथा समस्त नागरिकों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने में बैंकों के प्रभाव में नाटकीय वृद्धि करने पर है।

● विदेशी संस्थागत निवेश ने रिकॉर्ड समय में 3 बिलियन डॉलर की सीमा पार की

विदेशी संस्थागत निवेशकों का भारत प्रेम जारी है। शेयर बाजार में उनका निवेश लगभग दो महीने के रिकॉर्ड समय में या 47 व्यावसायिक सत्रों में 3 बिलियन डॉलर की सीमा को पार किया गया है। 2005 के बजट के बाद दस दिनों या आठ व्यापारिक सत्रों के सर्वाधिक अल्प समय के भीतर यह निवेश किया गया है। इससे 10 मार्च, 2005 को उनका शुद्ध इक्विटी निवेश 3.26 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। इस अवधि में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों वाले सेंसेक्स में 3.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

इसने इस वर्ष जनवरी से एक बिलियन तथा दो बिलियन डॉलर की निवेश सीमा क्रमश: 8 फरवरी तथा 28 फरवरी को पार कर ली थी।

2004 के दौरान विदेशी संस्थागत निवेश 31 मार्च को तीन बिलियन डॉलर की सीमा के पार गया था और तब यह निवेश 3.04 बिलियन डॉलर का हो गया था। 2003 के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों को यह आंकड़ा पार करने में लगभग 10 महीने का समय लगा था। 29 सितंबर, 2003 को वे 3.04 बिलियन डॉलर के शुद्ध खरीदार बने थे।

विश्लेषकों के अनुसार यह स्थिति भारतीय इक्विटी बाजार में निवेश के अधिक अवसर सुलभ होने के कारण बनी है।

● बैंडविथ की कीमतें 70 प्रतिशत गिरी, इंटरनेट और सस्ता होने की संभावना

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अंतरराष्ट्रीय बैंडविथ की कीमतों में 35 से 70 प्रतिशत तक की कटौती कर दी है। इससे लंबी दूरी के अंतरराष्ट्रीय टेलीफोन कॉलों, इंटरनेट अभिगम तथा ब्रॉडबैंड सेवाओं की दरें कम होने की संभावना है। इस कटौती से खुदरा ग्राहकों के अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं वाली कंपनियों को प्रचुर लाभ होगा।

● प्रवासी भारतीयों को हिमाचल प्रदेश का खुला न्यौता

राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास तथा अन्य संबद्ध गतिविधियों में निवेश के लिए विदेशों में बसे भारतीय लोगों को आकर्षित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रवासी भारतीयों को 'एनआईआर सिटी' की स्थापना करने का न्यौता दिया है। इसके लिए इस पर्वतीय राज्य में भूमि उपलब्ध करने के साथ-साथ सभी संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

● 1,000 करोड़ रुपये की लागत से विज्ञान अनुसंधान फाउंडेशन स्थापित किया जाएगा

केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दूरगामी प्रभाव वाले अनेक निर्णयों को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इनमें एक विश्वस्तरीय राष्ट्रीय विज्ञान एवं अनुसंधान फाउंडेशन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान एवं शिक्षण के लिए दो विश्वविद्यालयों की स्थापना शामिल है।

फाउंडेशन की स्थापना 1,000 करोड़ रुपये की लागत से की जाएगी और यह अमरीका के नेशनल साइंस फंड की तर्ज पर काम करेगा। विश्वविद्यालयों की स्थापना क्रमश: कोलकाता और पुणे में की जाएगी। इनमें से प्रत्येक पर 500 करोड़ रुपये की लागत आएगी। फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान को बढ़ावा देना होगा। यह एक स्वायत संस्था होगी और इसके प्रमुख उद्देश्यों में से एक वैज्ञानिकों के सम्मुख उपस्थित होने वाले नौकरशाही के उलझणों को कम करना होगा।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने सुरक्षित पेयजल, नई बीमारियों तथा वैज्ञानिक साक्षरता पर तीन राष्ट्रीय मिशनों को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत दो राष्ट्रीय संस्थाओं का लक्ष्य युवाओं में विज्ञान के क्षेत्र में रोजगार चयन को और आकर्षक बनाना है। ये संस्थान स्कूल की शिक्षा पूरी करके निकलने वाले छात्रों को प्रवेश देंगे और मौलिक अनुसंधान पर जोर देंगे। इसके साथ-साथ आईआईटी के समन्वित विज्ञान पाठ्यक्रमों में छात्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि मैसेस्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तर्ज पर वैज्ञानिक आधार को सशक्त बनाया जा सके। आरंभ में इस प्रस्ताव को दो आईआईटी में क्रियान्वित किया जाएगा। वर्ष 2006 से लगभग 200-300 छात्रों को प्रवेश देने की योजना है।

● आंध्र प्रदेश में कृषि प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित होगा

आंध्र प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की अध्यक्षता में एक कृषि

प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित मिशन में बैंकिंग, कृषि अनुसंधान, सहकारिता तथा कृषिगत विस्तार सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे जो किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे।

● दलितों के लिए कल्याण कार्यक्रमों की देखरेख के लिए मंत्रिस्तरीय पैनल

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दलित मामलों की देखरेख के लिए मंत्रियों की एक समिति गठित की है। यह समिति विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के द्वारा दलित-कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों और योजनाओं को समन्वित रूप से एक साथ लाकर प्रभावी तरीके से क्रियान्वित कराएगी।

यह समिति मौजूदा कार्यक्रमों की कमियों की पहचान करेगी और उन्हें समाप्त करने के लिए नए कार्यक्रम विकसित करने में मदद करेगी। समिति अनुसूचित जातियों के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण के लिए दिए गए आश्वासनों को क्रियान्वित करने के लिए विधायी कदमों की संस्तुति भी करेगी।

● एस. नागराजन और रतन लाल को बोरलॉग पुरस्कार

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक एस. नागराजन तथा ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, अमरीका में मृदा विज्ञान के प्रोफेसर एवं स्कूल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के कार्बन मैनेजमेंट एंड सिक्वेस्ट्रेशन सेंटर के प्रमुख रतनलाल को वर्ष 2005 के बोरलॉग पुरस्कार के लिए चुना गया है।

नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई.बोरलॉग के सम्मान में मुरुगप्पा समूह के कोरोमंडल फर्टिलाइजर द्वारा 1972 में स्थापित यह पुरस्कार हर वर्ष कृषि, पर्यावरण एवं विस्तार के क्षेत्र में किसी भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विशिष्ट अनुसंधान और योगदान के लिए प्रदान किया जाता है।

डा. नागराजन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गेहूं रोग विज्ञानी के रूप में जाना जाता है। गेहूं कार्यक्रम के प्रोन्नयन, गेहूं के विकारों के उन्मूलन और उपचार क्षेत्र में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है।

डा. रतनलाल को मृदा विज्ञान तथा समन्वित प्राकृतिक संसाधनों

बोरलॉग पुरस्कार 2005 से सम्मानित (बाएं से) डॉ. एस. नागराजन तथा डॉ. रतन लाल

भारतीय अर्थव्यवस्था

सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर
इतनी अद्यतन जानकारी
इतने कम मूल्य पर
अन्यत्र दुर्लभ है

Book Code : 851
Pages : 254
Price : Rs. 100/-

प्रमुख आकर्षण

• सितम्बर 2004 में जनगणना आयोग द्वारा भारत की जनगणना से सम्बन्धित प्रकाशित अन्तिम आंकड़ों का समावेश • आर्थिक सर्वेक्षण 2003-2004 • भारत 2004 • केन्द्र सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट 2003-2004 • विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2004 • अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक रिपोर्ट 2004 • रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की वार्षिक रिपोर्ट 2003-2004 • विश्व व्यापार संगठन (WTO) की वार्षिक रिपोर्ट 2004 • अंकटाड (UNCTAD) की विश्व निवेश रिपोर्ट 2004 • मानव विकास रिपोर्ट 2004 • World Economic Outlook, Sept. 2004 • Global Development Finance 2004 • Statesman's Year Book 2004 • दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-07 • 545 वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) प्रश्नों सहित

प्रतियोगिता साहित्य

Hospital Road, Agra-3 ☎ 0562-2151665 Fax 2151568
Email: info@sbpagra.com *or* visit www.sbpagra.com

Aligarh 3153072; Kanpur 2321191; 2321353; Varanasi 2354582; Lucknow 2270019; Allahabad 2461291; Bareilly 2554451; Gorakhpur 2344862; Meerut 2640540; Faizabad 260351; Jaunpur 260888; Jhansi 9839281738; Atarra 211056; Gaziabad 2748051; Moradabad 2313372; Azamgarh 220582; Muzaffarnagar 442739; Rishikesh 436532; Dehradun 2658555; Haridwar 428450; Gwalior 2325179; Bhopal 2543480; Indore 2451933, 2454372; Jabalpur 2655306; Sagar 23109; Satna 34760; Rewa 251753; Raipur 2227343; Bilaspur 505781; Bharatpur 20650; Jaipur 2327405, 2564452; Alwar 2701545; Swaimadhopur 22270; Kota 2323377; Ajmer 2620122; Udaipur 2421577, 2421375; Jodhpur 2626797; Dungarpur 230022; Rohtak 253217; Delhi 23918332; Patna 226540; Bhagalpur 24244830; Gaya 21147; Ranchi 301387; Bokaro 46001; Jamshedpur 2423508; Nagpur 2526191; Ahmedabad 25355755

यूरोपीय पेटेंट कार्यालय ने नीम पर पेटेंट अधिकार समाप्त किया

यूरोपीय पेटेंट कार्यालय ने भारतीय वृक्ष नीम पर पहले दिए गए अपने पेटेंट अधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। प्राचीन काल से नीम का भारतीय परंपरा में चिकित्सकीय उपयोग होता रहा है। पेटेंट कार्यालय ने कहा कि नीम पर पेटेंट लागू करना जैवचोरी है।

यूरोपीय पेटेंट कार्यालय ने सितंबर 1994 में अमरीकी कृषि विभाग तथा एक बहुराष्ट्रीय कृषि निगम डब्ल्यू ग्रेस को इस पर पेटेंट अधिकार सौंपने का आदेश पारित किया था। दोनों कंपनियों ने 1990 में पेटेंट कार्यालय से नीम तेल से फफूंदी नियंत्रण की विधि को पेटेंट कराने का आवेदन किया था।

इसके बाद इसका फफूंदनाशी तथा अन्य चिकित्सकीय उपयोग पारंपरिक रूप से भारत में किए जाने के पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करने पर पेटेंट कार्यालय ने मई 2000 में यह पेटेंट समाप्त कर दिया था। लेकिन तब यह विजय अल्पजीवी ही रही। दोनों संगठनों द्वारा अपील किए जाने पर पेटेंट को पुन: लागू कर दिया गया। अंतत: अब जाकर 8 मार्च, 2005 को यूरोपीय पेटेंट कार्यालय ने इस पेटेंट को हमेशा के लिए पूरी तरह समाप्त करने का अंतिम निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि आदेश अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आया। पेटेंट अधिकार की यह लड़ाई तीन महिलाओं ने लड़ी है।

जून 1995 में दिल्ली स्थित रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी की निदेशक डा. वंदना शिवा, ग्रीन ग्रुप इन यूरोपियन पार्लियामेंट की सुश्री भाग्दा एलवॉट तथा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट की सुश्री लिंडा बुलाई ने संयुक्त रूप से इस पेटेंट अधिकार का विरोध करते हुए आवेदन किया। पेटेंट अधिकार निरस्त किए जाने पर डा. वंदना शिवा ने कहा कि भारतीय महिलाओं के लिए इससे बेहतर खुशी और क्या हो सकती है। इस निर्णय के द्वारा लाखों भारतीय महिलाओं की पारंपरिक ज्ञान को स्वीकार किया गया है।

ग्रीन ग्रुप इन यूरोपियन पार्लियामेंट की पूर्व अध्यक्ष तथा वर्तमान में बेल्जियम की स्वास्थ्य एवं पर्यावरण राज्यमंत्री सुश्री एलकॉट ने कहा कि पहली मर्तबा जैवचोरी के आधार पर कोई पेटेंट अधिकार निरस्त किया गया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ आर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट की पूर्व अध्यक्ष सुश्री लिंडा ने कहा कि पारंपरिक ज्ञान का उपयोग प्राचीन ज्ञान को स्थापित करने तथा नवचार और नवीन खोज के दावे के झूठा को प्रमाणित करने में सफल रहे।

तारापुर की चौथी परमाणु भट्ठी ने काम करना आरंभ किया

पूरी तरह आंतरिक रूप से निर्मित 540 मेगावाट क्षमता वाली अब तक की सबसे बड़ी परमाणु भट्टी के काम करना आरंभ करने से भारत ने परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी सामर्थ्य का जोरदार संकेत दिया है। इसे तारापुर एटोमिक पावर प्रोजेक्ट (टैप) का नाम दिया गया है। इसे पूरी तरह देसी तरीके से भारतीय परमाण्विक ऊर्जा निगम लि. ने तैयार किया है।

परमाण्विक ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डा. अनिल काकोदकर ने इसे एक 'महत्वपूर्ण अवसर' बताते हुए कहा कि यह कार्य भारत को प्रौद्योगिकी देने से इंकार करने के बावजूद पूरा किया गया। उन्होंने बताया कि यह परियोजना निर्धारित कार्यक्रम से सात महीने पहले तथा आकलन से बहुत ही कम लागत में पूरी कर ली गई।

6 मार्च को 12.41 बजे टैप - 4 के केंद्र निदेशक द्वारा यह घोषित किए जाते ही कि भट्ठी ने विधिवत काम करना आरंभ कर दिया है, इससे जुड़े इंजीनियर खुशी से झूम उठे। टैप-4 के अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष में हर्षध्वनि गूंज उठी।

540 मेगावाट क्षमता वाली भट्ठी टैप - 4 का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। ये दोनों भट्ठियां दाबानुकूलित भारी जल भट्ठी परिवार का अंग हैं। इनमें इंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम तथा संचालक और प्रशीतक दोनों ही रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। टैप-3 तथा 4 दोनों महाराष्ट्र के ठाणे जिले में अरब सागर के नीले जल के किनारे अवस्थित हैं।

एनपीसीआईएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एस.के.जैन ने बताया कि टैप-3 तथा 4 के निर्माण की मूल लागत 8,000 करोड़ रुपये थी। इसे कम करके 6,525 करोड़ रुपये पर फिर 6,000 करोड़ पर ले आया गया। इसके परिणामस्वरूप, पश्चिमी राज्यों को जो बिजली 3.50 रुपये यूनिट की दर से दी जाने वाली थी, वह अब मात्र 2.65 रुपये प्रति यूनिट की दर से बेची जाएगी। टैप-3 और 4 से महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गोवा तथा दमन और दीव को बिजली दी जाएगी। ❑

('योजना' हिंदी और अंग्रेजी संपादकीय टीम द्वारा संकलित)

के प्रबंधन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए चुना गया है। मिट्टी की प्रकृति तथा मृदा की उर्वरा की रक्षा के महत्व के बारे में समझ बढ़ा कर विश्वस्तर पर खाद्य असुरक्षा कम करने की दिशा में अपने अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए वह ख्यातनाम हैं।

पुरस्कारस्वरूप इसमें एक लाख रुपये की नकद राशि, एक स्वर्ण पदक तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार गत 16 मार्च को डा. बोरलॉग ने प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने 'हरित क्रांति से जैव क्रांति तक : 21वीं सदी की चुनौतियां विषय पर कोरोमंडल व्याख्यान भी दिया।

● बाघों की स्थिति पर कार्यबल

प्रधानमंत्री ने बाघों की स्थिति पर एक कार्यबल गठित करने का निर्णय किया है। यह निर्णय राजस्थान के सरिस्का से बाघों के गायब होने की खबरों के बाद लिया गया है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

1. बाघों के गुम होने पर सीबीआई जांच कराए
2. एक राष्ट्रीय वन्यजीव अपराध रोकथाम एव नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना करना।
3. किसी राज्याध्यक्ष अथवा सरकार के प्रमुख द्वारा अन्य राज्याध्यक्ष या सरकार के प्रमुख को अथवा स्वदेशी चिड़ियाघरों को उपहार स्वरूप वन्यजीव देने पर पाबंदी लगाना।

● श्रमिकों के लिए बेरोजगारी लाभ कार्यक्रम

सरकार ने इस वर्ष अप्रैल से श्रमिकों के लिए एक बेरोजगारी लाभ कार्यक्रम की घोषणा की है। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना नामक यह कार्यक्रम कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत तालाबंदी, छंटनी तथा स्थायी अमान्यता के कारण रोजगार गंवाने वाले श्रमिकों को कवर किया जाएगा। उन्हें उनकी मजदूरी के 50 प्रतिशत के करीब बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। यह भत्ता अधिकतम छह महीने की अवधि तक दिया जाएगा। वे अपने परिवार सहित कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दवाखानों और अस्पतालों में चिकित्सा के हकदार भी होंगे।

तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना आरंभ

तमिलनाडु सरकार ने विश्व बैंक द्वारा समर्थित 597.15 करोड़ रुपये की लागत वाली तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना में विश्व बैंक का योगदान 502.94 करोड़ रुपये का होगा जबकि राज्य सरकार 94.21 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके तहत राज्य के सरकारी अस्पतालों में बेहतर बुनियादी ढांचे का निर्माण तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए प्रकोष्ठ

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा कार्यक्रमों की निगरानी के लिए योजना आयोग में एक विशेष प्रकोष्ठ गठित किया गया है। यह प्रकोष्ठ सार्वजनिक वितरण प्रणाली, काम के लिए अनाज कार्यक्रम, समन्वित बाल विकास कार्यक्रम तथा दोपहर का भोजन जैसे कार्यक्रमों की निगरानी करेगा।

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा निगरानी दल नामक इस प्रकोष्ठ में अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, पोषणशास्त्री तथा खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में अनुभव वाले स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ता शामिल होंगे। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पर यह प्रकोष्ठ अध्ययन कराएगा तथा उनके निष्कर्षों का उपयोग नीतियों में संशोधन और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को और बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा।

● मंत्रिपरिषद ने रक्षा खरीदों को मंजूरी दी

सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति ने अनेक रक्षा खरीदों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इनमें समुद्र क्षेत्र में निगरानी के लिए 726 करोड़ रुपये की लागत से 11 डॉर्नियर 228 विमानों की खरीद शामिल है। इसने 324 करोड़ रुपये की लागत से एक समेकित प्रक्षेपण सुविधा की स्थापना के प्रस्ताव का भी अनुमोदन कर दिया है 14 सी-हैरियर विमानों के स्तरोन्नयन के लिए 476.69 करोड़ रुपये की राशि भी आवंटित की गई है।

● भारत ने 2014 के एशियाई खेलों के आयोजन का दावा करने की योजना बनाई

केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने भारतीय ओलंपिक संघ को वर्ष 2014 में होने वाले 17वें एशियाई खेलों को नई दिल्ली में आयोजित करने का दावा करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

सरिस्का के गायब हुए बाघ

वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार जून 2004 से सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में एक भी बाघ नहीं देखा गया है। राजस्थान सरकार ने कहा है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान ने उसे सरिस्का में बाघों की ठीक-ठीक संख्या का पता लगाने तथा मौजूदा स्थिति में सुधार के रास्ते बताने की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लिखा है कि मामले की जड़ में जाकर सही कदम उठाएं।

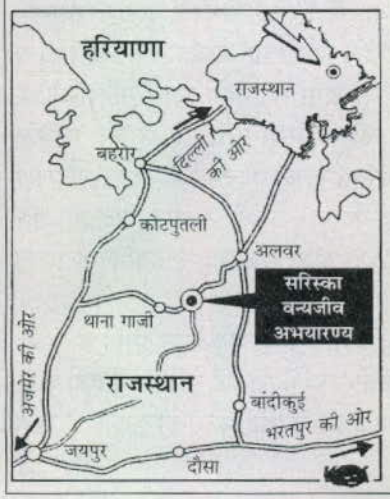

कश्मीर में फलों की खेती की धूम

जम्मू और कश्मीर बागवानी उत्पाद और विपणन निगम (एचपीएमसी) ने कश्मीर घाटी के शोपियां में एक समन्वित पैक हाउस की स्थापना के लिए भारतीय डेयरी मशीनरी कंपनी लि. (आईडीएमसी), आणंद और फ्रीक इंडिया लि. के साथ समझौता किया है। परियोजना की अनुमानित लागत 3.88 करोड़ रुपये है।

देश में अपनी तरह के इस पहले पैक हाउस को इलेक्ट्रानिक ग्रेंडिग और छंटाई मशीनों सहित अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।

आईडीएमसी का प्रधिनिधित्व उसके प्रबंधक (रेफ्रिजेरेशन), के. के. मंगलानी, जबकि फ्रीक इंडिया लि. का प्रधिनिधित्व इसके उपाध्यक्ष (परियोजना), कुलबीर सिंह ने किया। जम्मू एवं कश्मीर एचपीएमसी के प्रबंधक निदेशक गुलाम हसन शाह ने जम्मू और कश्मीर सरकार की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि फलों की ग्रेंडिंग रंग, आकार और वजन के आधार पर की जाएगी।

पैक हाउस में शीत भंडारण और प्री-कूलिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

समझौते के अनुसार पैक हाउस की स्थापना आईडीएससी करेगी जबकि शीत भंडारण और प्री-कूलिंग इकाई संबंधी कार्य फ्रीक इंडिया करेगी। कृषि और सहकारिता मंत्री अब्दुल अज़ीज ज़रगार के अनुसार इस पैक हाउस से न केवल फलों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा बल्कि इससे राज्य में ऐसी इकाइयों को नई दिशा मिलेगी जो अभी तक इन सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि देश की विभिन्न बड़ी मंडियों में बागों से प्राप्त ताज़ा फलों के रूप में रेफ्रीजेरेटेड परिवहन की व्यवस्था करना इन सुविधाओं में सम्मिलित है। उन्होंने कहा कि राज्य में सामाजिक-आर्थिक बदलाव में बागवानी क्षेत्र की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ❑

स्रोत : एजेंसियां

● देर रात की पाली में महिलाओं के काम करने का रास्ता साफ हुआ

सरकार ने कुछ उद्योगों में महिलाओं को देर रात की पाली में काम करने की अनुमति देने के लिए कारखाना अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक को फिर से प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

● मणिपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा

मंत्रिपरिषद ने पूर्वोत्तर में शैक्षिक सुविधाओं के क्षेत्र में व्याप्त असंतुलन को दूर करने के ध्येय से मणिपुर विश्वविद्यालय तथा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफाल को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक विधेयक लाया जाएगा।

सरकार ने बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों के सबलीकरण के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। 39 करोड़ रुपये की लागत से यह संस्थान चेन्नई में स्थापित किया जाएगा।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कृषि शिक्षा को मजबूत और विकसित करने के लिए 804 करोड़ रुपये की लागत वाले कार्यक्रम को भी स्वीकृति दे दी गई है।

● उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राज्य सरकारें नए मोटर वाहनों के पंजीयन के समय उनके लागत मूल्य के आधार पर एकमुश्त अग्रिम 'लाइफ टाइम टैक्स' लगाने के लिए अधिकृत हैं।

● लेखक ओ.वी. विजयन नहीं रहे

मलयालम के प्रख्यात लेखक तथा कार्टूनिस्ट ओ.वी. विजयन का 30 मार्च को हैदराबाद में देहांत हो गया।

● भारत और ब्रिटेन ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया

फिल्म उद्योगों की भारी संभावना को स्वीकार करते हुए भारत और ब्रिटेन ने फिल्मों के साझा निर्माण के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता पत्र हस्ताक्षर किया है।

● जानकी सुरक्षा कार्यक्रम को स्वीकृति मिली

सरकार ने जानकी सुरक्षा योजना नामक मातृत्व लाभ कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय मातृत्व लाभ कार्यक्रम का स्थान लेगा। केंद्रीय बजट में घोषित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का यह एक महत्वपूर्ण अंग होगा। यह कार्यक्रम गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की 19 वर्ष से ऊपर की आयु वाली महिलाओं के लिए होगा। इसके लिए धन की व्यवस्था पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। पहले दो जीवित बच्चों के जन्म के दौरान महिलाएं इस कार्यक्रम का लाभ उठा पाएंगी। इसके अंतर्गत माताओं और स्वास्थ्यकर्मियों को 200 से 800 रुपये तक का मौद्रिक लाभ प्रदान किया जाता है।

● छत्तीसगढ़ को एशियाई विकास बैंक का ऋण मिलेगा

एशियाई विकास बैंक ने छत्तीसगढ़ में सिंचाई सुविधाओं तथा कृषि संबंधी कार्यों में सुधार के लिए 4.61 करोड़ अमरीकी डॉलर के ऋण को स्वीकृति प्रदान की है। ❑

तनाव से बचाव के लिए ब्राह्मी

○ जॉब थॉमस

परीक्षा के दिन निकट आते ही बच्चे दिन-रात एक करके पढ़ने में तल्लीन हो जाते हैं। उनकी बेचैनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। मगर सिर्फ पढ़ने से क्या होगा, परीक्षा अच्छी तरह देनी है, अच्छे अंक भी पाने हैं। उसके लिए ज़रूरत है, मजबूत दिल की मधारणा शक्ति की, स्मरण शक्ति की, यानी पढ़ी हुई बातों को मन में बिठाने की क्षमता की ब्राह्मी आयुवेद की ऐसी औषधि है, जो इन जरूरतों को पूरा कर सके।

ब्राह्मी निचले प्रदेशों में पाया जानेवाला एक पौधा है। गीली और कीचट भरी मिट्टी में जमीन से सटकर उगनेवाली इस जड़ी में हल्के नीले या सफेद रंग के छोटे-छोटे फूल भी लगते हैं। वनस्पति विज्ञान में इसका नाम है बाकपा मान्नीरी लिन। यह प्रशीतक गुण वाली होती है। इसके सभी अंग औषधि योग्य हैं।

ब्राह्मी युक्त 'ब्राह्मी घृत' में बुद्धि का विकास करने तथा स्मरण शक्ति को बढ़ाने की अद्‌भुत शक्ति है। ब्राह्मी को निचोड़कर लिया गया रस ही इसका मुख्य घटक है। घी में तैयार करने से इसका गुण आवश्यकतानुसार मस्तिष्क की कोशिकाओं में ग्रहण किया जा सकता है। पांच ग्राम ब्राह्मी आधे गिलास दूध और आधे गिलास पानी के साथ मिलाकर औटाकर आधा गिलास करके रोज़ सेवन करने से बुद्धिशक्ति का विकास होता है।

बढ़ी हुई मात्रा में रोज ब्राह्मी का सेवन करने पर पढ़ने-लिखने से उत्पन्न थकान दूर हो जाती है। आधुनिक अध्ययनों से यह सिद्ध हो चुका है कि ब्राह्मी आकांक्षा के रोग को भी दूर कर सकती है। यह मानसिक शक्ति एवं उत्साह बढ़ाती है। परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र इस अनमोल औषध का उपयोग कर सकते हैं।

आजकल हमारे नगरों-महानगरों में सब जगह बच्चे, नौजवान, बूढ़े सब तनावपूर्ण जीवन बिता रहे हैं। ब्राह्मी में इस तनाव को दूर करने की क्षमता है। नगर के फ्लैटों में, जहां सूरज की रोशनी पड़ती हो, गमलों में ब्राह्मी उगाई जा सकती है। खाद के रूप में गोबर और अन्य जैव उर्वरकों का उपयोग किया जा सकता है। हां, पानी रोज़ दें। ❑

(लेखक द आर्य वैद्य फार्मेसी (कोयंबटूर) लि. के निदेशक हैं)

भारतीय राजव्यवस्था एवं भारत का संविधान

कम मूल्य में इतनी अधिक अद्यतन जानकारी अन्यत्र दुर्लभ है

Book Code : 849
Pages : 192
Price : Rs. 80/-

प्रमुख आकर्षण

• भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन की विस्तृत विवेचना • भारत के संविधान में अब तक हुए 92 संविधान संशोधन अधिनियमों का समावेश • 800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न • भारतीय राजनीति की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं सितम्बर 2004 तक का यथास्थान और आवश्यक विस्तार के साथ समावेश इस प्रकार यह पुस्तक पूर्णतया अद्यतन (Most up-to-date) है।

प्रतियोगिता साहित्य

Hospital Road, Agra-3 ☎ 0562-2151665 Fax 2151568
Email: info@sbpagra.com or visit www.sbpagra.com

Aligarh 3153072; Kanpur 2321191; 2321353; Varanasi 2354582; Lucknow 2270019; Allahabad 2461291; Bareilly 2554451; Gorakhpur 2344862; Meerut 2640540; Faizabad 260351; Jaunpur 260888; Jhansi 9839281738; Atarra 211056; Gaziabad 2748051; Moradabad 2313372; Azamgarh 220582; Muzaffarnagar 442739; Rishikesh 436532; Dehradun 2658555; Haridwar 428450; Gwalior 2325179; Bhopal 2543480; Indore 2451933, 2454372; Jabalpur 2655306; Sagar 23109; Satna 34760; Rewa 251753; Raipur 2227343; Bilaspur 505781; Bharatpur 20650; Jaipur 2327405, 2564452; Alwar 2701545; Swaimadhopur 22270; Kota 2323377; Ajmer 2620122; Udaipur 2421577, 2421375; Jodhpur 2626797; Dungarpur 230022; Rohtak 253217; Delhi 23918332; Patna 226540; Bhagalpur 24244830; Gaya 21147; Ranchi 301387; Bokaro 46001; Jamshedpur 2423508; Nagpur 2526191; Ahmedabad 25355755

AVINASH TIWARI'S

निष्ठा

सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी हेतु एक उत्कृष्ट संस्थान

नामांकन प्रारम्भ

प्रथम सत्र	द्वितीय सत्र	तृतीय सत्र	चतुर्थ सत्र
26 मई, 05	01 जुलाई, 05	06 अक्टूबर, 05	10 दिसम्बर, 05

दर्शनशास्त्र

प्रारंभिक परीक्षा
अविनाश तिवारी

- एक दशक से अधिक का सफल एवं लोकप्रिय अध्यापन अनुभव।
- तर्कशास्त्र की मानक पुस्तकों के लेखक-तर्कशास्त्र की सिद्धान्त, प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र एक अध्ययन।
- पाठ्यक्रम के तीनों भागों - दर्शन की समस्याएँ, तर्कशास्त्र तथा नीतिशास्त्र पर समान बल।
- तीनों भागों का परिष्कृत एवं परिमार्जित अध्ययन सामग्री वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर सहित।

मुख्य परीक्षा
प्रो० द्विवेदी एवं अन्य

- भारत के सर्वश्रेष्ट विशेषज्ञ समूह द्वारा।
- दर्शनशास्त्र की ख्यातिलब्ध पुस्तकों के लेखक
- तीन माह का गहन अध्यापन पाठ्यक्रमानुसार।
- विषय का विशद, समग्र तथा विश्लेषणात्मक अध्यापन के साथ परिष्कृत एवं परिमार्जित अध्ययन सामग्री।
- पाठ्यक्रम के प्रत्येक खण्ड के प्रत्येक टॉपिक पर समान बल।

सामान्य अध्ययन
(इलाहाबाद की सर्वश्रेष्ठ टीम)

भारतीय अर्थव्यवस्था	अरूणेश सिंह (लेखक)	भूगोल	सिद्धार्थ कुमार
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	एस.के.आर. वर्मा	सांख्यिकी एवं मानसिक योग्यता	असीम मुखर्जी
भारतीय राजव्यवस्था	ओ. पी. सिंह	इतिहास	विषय-विशेषज्ञ

भारतीय इतिहास विषय विशेषज्ञों द्वारा

दर्शनशास्त्र
पत्राचार नोट्स भी उपलब्ध

प्रारंभिक परीक्षा-2000/- मुख्य परीक्षा- 2500/-

दर्शनशास्त्र के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उच्चस्तरीय अध्ययन सामग्री का संकलन किया गया है। इस अध्ययन सामग्री में आप विषय सम्बन्धी सभी जानकारियाँ एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकेंगे जिससे आपके समय, ऊर्जा और संसाधन की बचत होगी। इसमें सम्पूर्ण पाठ्यक्रम तथा पिछले दस वर्षो के प्रश्नों का विश्लेषण है जिससे अन्य पाठ्य सामग्रियों की आवश्यकता नहीं।

सम्पर्क सूत्र

☎ : (0532) 2611212, 2467642

: 9415638449, 9415308157

1183, इस्लाम कॉम्पलेक्स, मनमोहन पार्क, पुराना कटरा, इलाहाबाद–211002

केला : एक संपूर्ण आहार

○ गीता रानी

भोजन के बाद फल खाना लाभदायक होता है चाहे वह कोई भी फल हो। सभी लोगों को अपनी सुविधानुसार मौसमी फल भोजनोपरांत खाना चाहिए। मौसमी फलों का महत्व यह होता है कि वे आपके शरीर को जरूरी प्रोटीन, लवण, शक्कर तथा कई विटामिन प्रदान करते हैं। इससे आपका शरीर रोग प्रतिरोधक शक्ति ग्रहण करता है।

केला अपने आप में एक संपूर्ण आहार है। कच्चा हो या पका यह दोनों रूपों में खाया जाता है। फलाहार में भी केला खाया जाता है। तेज भूख में दो-चार केले खा लेने से कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती।

पके केले में आयोडिन, शक्कर और प्रोटीन पाया जाता है जबकि कच्चे केले में कैल्शियम अधिक होता है। केले की सब्जी भी बनाई जाती है। प्रतिदिन दो केला खाने से सभी प्रकार के विटामिनों की पूर्ति हो जाती है। सुबह दो केला खाकर गुनगुना दूध पीने से व्यक्ति सदा स्वस्थ रहता है। चित्तीदार या धब्बेदार, पतले छिलके वाला केला खाना अधिक लाभदायक होता है।

बहुत छोटे बच्चों को भी ऊपरी आहार की शुरुआत आमतौर पर केले से ही की जाती है। केले के गुदे को चम्मच से फेंट कर उसमें छोटी इलाइची का पाउडर डाल कर खिलाने से बच्चे पुष्ट होते हैं। दस्त होने पर बीमार को केला खिलाया जाता है। केले पर काला नमक डाल कर खाने से हाजमा दुरुस्त होता है।

भोजन के बाद यदि दो केला रोज खाया जाय तो ये भोजन भी पचाता है और बल भी बढ़ाता है। इससे पाचन शक्ति ठीक होती है। एक गिलास दूध में एक चम्मच घी, और एक चुटकी पिसी इलायची मिला लें, एक टुकड़ा केला खाएं साथ ही एक घूंट दूध पियें। इस प्रकार दो केला नित्य खाने से शरीर सुडौल, और मोटा होता है। बल, वीर्य तथा शुक्राणु की वृद्धि होती है। दिमागी शक्ति बढ़ती है। स्त्रियों का प्रदर रोग ठीक होता है। दो केले दो चम्मच शहद के साथ रोज सुबह खाने से ताकत मिलती है। हाई ब्लड प्रेशर में सुधार होता है। मूत्र समस्या हो तो ठीक हो जाता है। रोज कच्चे केले की सब्जी खाने से पेट के कीड़े मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। दस्त व पेचिश की शिकायत हो तो उसमें भी आराम मिलता है।

दमा में - एक पका केला छिलके सहित सेंकें इसके बाद इसका छिलका हटा दें। केले के टुकड़े कर लें इस पर पन्द्रह काली मिर्च पीसकर मुरमुरा दें, गरम-गरम ही दमे के रोगी को खिलाएं, दमा के दौरे में लाभ होता है।

खांसी में - एक पके केले में आठ साबुत काली मिर्च भर दें, वापस छिलका लगा कर खुले स्थान पर रख दें, शौच जाने के पूर्व प्रातः काली मिर्च निकाल कर खा जाएं, फिर केला भी खा लें। इस प्रकार कुछ दिन करने से हर तरह की खांसी ठीक हो जाती है।

केले के पत्ते को जला कर उसका राख शहद के साथ चाटने से भी खांसी में आराम मिलता है।

केले के पत्तों पर इकट्ठा ओस की बूंदों को समेट कर साफ रूई से फोड़े-फुंसियों पर लगाया जाए तो वे बहुत जल्द ठीक हो जाती हैं। ❑

IAS - PCS प्रीलिम तथा मेन्स
में सामान्य अध्ययन के लिए एक अपरिहार्य पुस्तक
भारतीय अर्थव्यवस्था
– सर्वेक्षण तथा विश्लेषण
द्वारा प्रो० एस० एन० लाल इ० वि०
पुस्तक को जिसने भी पढ़ा उसी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की
"--In Delhi the books of this standard that too in Hindi medium are really scarce. I am sure that this book and other books written by Prof. S.N. Lal will be of immense use to the candidates for civil services." (**Dr. Adesh Sharma,** Senior Teacher of Economics University of Delhi /Director, KALP Academy, Delhi).
"प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये लिखी यह पुस्तक अत्यन्त ही उपयोगी है, विशेषतः खण्ड -5 जो मेन्स के लिये है।"
(सी.बी.पी.श्रीवास्तव, निर्देशक डिस्कवरी इन्स्टीट्यूट दिल्ली)
संशोधित संस्करण -2005, नये ग्रन्थ, आर्थिक समीक्षा तथा विदेश व्यापार नीति 2004-09 के साथ।
पुस्तक प्राप्ति के कुछ प्रमुख स्थान– संस्करण– 2005, मूल्य– Rs. 130/
अजय पुस्तक केन्द्र यूनिवर्सिटी रोड इलाहाबाद। मिश्रा बुक डीपो, आई. टी. ओ दिल्ली। अग्रवाल मैगजिन डिस्ट्रीब्यूटर नई दिल्ली, नवशक्ति पुस्तक केन्द्र मुखर्जी नगर दिल्ली। आशीर्वाद, लखनऊ। जवाहर बुक डीपो, नयी दिल्ली।
शिव पब्लिशिंग हाऊस, अलोपीबाग रोड इलाहाबाद, (प्रकाशक) –
फोन :– (0532)-2508236, 2502755
ECONOMICS
IAS कोचिंग के लिये PCS
उत्तर भारत का एकमात्र विश्वसनीय नाम
प्रो० एस० एन० लाल
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
नया बैच 10 जुलाई 2005 से प्रारम्भ
नामांकन जारी
सामान्य अध्ययन के लिये भारतीय अर्थव्यवस्था
द्वारा डा० अनूप सिंह इ० वि०
सामान्य अध्ययन विषय विशेषज्ञों के द्वारा
सम्पर्क करें– 09335154584, (0532), 2508236
ला-MERIDIAN
लेवर चौराहा, अल्लापुर, इलाहाबाद
(हास्टल सुविधा भी उपलब्ध)

अच्छा प्रयोग है दीवार लेखन

○ हीरल दवे

जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय में दो किलोमीटर लंबी दीवार किसानों के लिए सुझावों के सूचना पट्ट का काम कर रही है

किसी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में क्या अनुसंधान किए जा रहे हैं और कोई किसान और क्या जानकारी हासिल कर सकता है, यह स्वप्न अब जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय ने हकीकत में बदल दिया है। विश्वविद्यालय ने इसके वैज्ञानिकों द्वारा किए गए सभी अनुसंधानों के बारे में 175 नारे किसानों के पढ़ने और उनसे लाभान्वित होने के उद्देश्य से 2 किलोमीटर लंबी दीवार पर प्रदर्शित किए हैं। कुलपति डा. बी.के. किकानी का कहना है कि कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए अनुसंधान कार्यों के अंशों को नारों के रूप में दीवार पर लिखा गया है ताकि किसान और आने वाले अन्य लोग इन्हें आसानी से पढ़कर समझ सकें। उन्होंने कहा कि हम जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से गांव में बैठकें, शो और अन्य कार्यक्रम आयोजित करते हैं लेकिन यह एक सस्ता तथा अधिक प्रभावकारी तरीका है।

किसान परिसर में स्थित सूचना और प्रशिक्षण केन्द्र में नियमित तौर पर आते रहते हैं। वे जैव प्रौद्योगिकी, ग्रीन हाउस, सुगंधित पौधों, आयुर्वेद, पेड़ों और पौधों के औषधीय महत्व, यहां तक कि कौन-सा कीटनाशक इस्तेमाल करना चाहिए, सूखे के समय फसलों को कैसे बचाया जाए, प्याज जैसी नष्ट होने वाली चीजों को कैसे बचाया जाए और फलों की खेती कैसे की जाए, आदि के बारे में

जानकारी प्राप्त करते हैं। इन नारों से किसानों को इस बात की ताज़ातरीन जानकारी भी मिलती है कि वे अपने कृषि उत्पादों का अच्छा बाजार भाव कैसे प्राप्त करें। एक ट्रेनिंग एसोसिएट नरेंद्र भाई का कहना है कि अक्सर किसान अधिकारियों और वैज्ञानिकों से बातचीत करने में संकोच करते हैं। अत: हमने वे तमाम जानकारियां, जो किसान चाहते हैं, दीवार पर लिखने का फैसला किया।

ये नारे इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि किसानों के अनुरोध पर विश्वविद्यालय ने इन्हें 'कृषि रत्नकणिका' नाम से एक पुस्तिका के रूप में भी उपलब्ध कराया है। जल संसाधन के स्थाई प्रबंधन पर जनवरी माह में विश्वविद्यालय में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्य के कृषि मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ास्मा ने इसका विमोचन किया।

विश्वविद्यालय में 35 विभाग हैं और प्रत्येक ने कम से कम पांच नारों का योगदान किया है। सभी 25 वैज्ञानिकों से उपयोगी नुस्खे उपलब्ध कराने को कहा गया। इनमें से कुछ नुस्खों को चुनकर उनका अनुवाद किया गया। श्री बराड़ ने कहा कि ये नारे आसान गुजराती भाषा में लिखे जाते हैं ताकि सामान्य शिक्षित किसान भी इन्हें समझ सकें।

श्री किकानी का कहना है कि विश्वविद्यालय ने चार महीने पहले दीवार पर काम करना शुरू किया था। यह कार्य तीन चरणों में किया जा रहा है। दीवार की कुल लंबाई 3 किमी. है और लगभग 2 किमी. तक इस पर काम हो चुका है। चूंकि इस कार्य के लिए कोई अनुदान उपलब्ध नहीं था, अत: विश्वविद्यालय ने सभी विभागों से अपने-अपने नारों के प्रदर्शन पर खर्च होने वाली राशि के बराबर सहयोग करने को कहा है।

जब किसानों ने अनुरोध किया कि नारे लिखित रूप में भी उपलब्ध कराए जाएं तो उपलेटा के एक कृषक संगठन- वृक्ष प्रेम सेवा ट्रस्ट ने 'कृषि रत्नकणिका' पुस्तिका को प्रायोजित करने का फैसला कर लिया। ❑

(लेखिका इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप, राजकोट से संबद्ध है)

(कवर दो का शेष)

खास काम सरकार ने हाथ में लिए हैं, उनमें कोताही न हो। 2005-06 के मंसूबे में जम्मू-कश्मीर के लिए करीब 4,200 करोड़ रुपये रखे गए हैं जिसका मरकज़ी हिस्सा 90 प्रतिशत है। अगले 4-5 साल में हर गांव में बिजली पहुंच जाएगी, और ये न सिर्फ चंद घंटों के लिए एक या दो बल्ब में रोशनी, बल्कि बाकायदा बिजली की रफ्तार जिससे कारोबार भी चल सके। बगलिहार का काम चल रहा है - 330 करोड़ रुपये की रकम खासतौर से इस काम को मुकम्मल करने के लिए रखी गई है। और भी बिजली की स्कीमों पर काम जोरशोर से चल रहा है।

रोजगार, सय्याहत का फ़रोग, सेहतमंद माहौल और काश्त की तरक्की ये सब हमारे मंसूबों में अहमियत रखते हैं। आपको याद होगा कि जब मैं यहां पिछली दफा हाजिर हुआ था तो हर तरफ से रोजगारी की मांग सुनने में आयी थी, हमने 6,800 आंगन-बाड़ी मरकज़ों को खोलने की मंजूरी दे दी है जिससे 14 हजार गांव की औरतों को नौकरी मिलेगी। मुझे बताया गया है कि इसमें भर्ती शुरू हो गई है। रियासती पुलिस में 5 इंडियन रिजर्व बटालियन मंजूर हुए हैं जो आखिर जून में काम पर लग जाएंगे। इसमें 5,000 नौजवान नौकरी में लगाए जाएंगे। इसी तरह सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और बार्डर गार्ड्स में 20-40 फीसदी तक जगह जम्मू-कश्मीर और भारत के कुछ और हिस्सों के नौजवानों के लिए रखी गई है। शहरों में रहने वाले नौजवानों के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू की जा रही है जिसके लिए 12 करोड़ रुपये अलग रख दिए गए हैं।

माहौल की तरक्की के लिए डल, मनसार और वूलर झीलों को सेहतमंद बनाने के काम उठाए जाएंगे। साथ-साथ शहरी इलाकों में नालों और पानी के निकास के लिए एडीबी ने तकरीबन 1,900 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इससे काफी नई-नई सड़कें और पुल भी बन सकेंगे।

जम्मू-कश्मीर के हर हिस्से का ख्याल रखा जा रहा है। लद्दाख, करगिल की तरक्की के लिए पैसे रखे जा रहे हैं। वहां सय्याहत के फ़रोग़ के लिए हमने काफी इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। बहुत सी स्कीमों पर काम शुरू हो चुका है।

सय्याहत को फ़रोग़ देने के लिए कई मंसूबों को मंजूर किया गया है। सय्याहत को गांवों तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। इन सब मंसूबों को मुस्तहकम बनाने के लिए तालीम और तरबियत भी शुरू की गई है ताकि रोजगार का फायदा बहुतों तक पहुंच पाए। सय्याहत की सहूलियत को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए भारत की सय्याहत की वज़ारत ने 16 करोड़ रुपये का इंतजाम किया है। हमारी सरकार आम आदमी की सरकार है। शिकारेवालों, हाउसबोट के मालिकान और नुमाइंदों, घोड़े और टट्टू वालों के लिए, इसके साथ ही सय्याहत के नये मंजिल, तरबियत के मरकज वगैरहा पर भी जोर दिया जा रहा है। पिछले साल 4 लाख के करीब सय्याह जम्मू-कश्मीर आए। उम्मीद है कि नये इकदामात के नतीजे में ये आमद और बढ़ेगी और हर खित्ते को फायदा होगा।

इन सब तरक्कियाती कामों का एक ही मकसद है वो ये कि जम्मू-कश्मीर का अवाम, अमन और खुशहाली में एक बाइज्जत जिंदगी बसर कर सके। गुजरे हुए जमाने के दुख-दर्द आसानी से भुलाए नहीं जा सकते। मगर ये हमारे मुस्तकबिल को किसी तरह से न बिगाड़ें, ये हमारी कोशिश होगी।

आज जिस सड़क की मैं इफ्तिताह कर रहा हूं, उम्मीद है कि ये न सिर्फ मुसाफिरों के आने-जाने के लिए इस्तेमाल हो बल्कि जैसे ये कभी होता था तिजारत का एक अहम रास्ता बन जाए। जिसके जरिये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरम्यान खास तौर से कश्मीर की पैदावार और और यहां का बना हुआ सामान पाकिस्तान के बड़े शहरों में फरोख्त होने लगे। मगर पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान और ईरान तक ये माल पहुंचाने के ये रास्ते यहां के ताजिरों के लिए खोल दिए जाएं। ऐसे और रास्तों की फिर जरूरत होगी ताकि जम्मू-कश्मीर के हर खित्ते से तिजारत इन रास्तों पर बहाल हो जाए जो हैं रिवायती मगर अरसे से बंद पड़े हैं।

मैं अपने पाकिस्तान के दोस्तों से चाहूंगा कि हम मिलकर जब्र और तशद्दुद का मुकाबला करें। तशद्दुद से कभी किसी को फायदा नहीं पहुंचा, न ही पहुंचेगा। सभी का नुकसान ही नुकसान है। भारत पाकिस्तान का हाथ थामने के लिए तैयार है ताकि हम हाथ से हाथ मिलाकर अपने लोगों के लिए पुर अमन माहौल पाइंदा बनाएं और खास तौर से सारी रियासत जम्मू-कश्मीर में अमन और खुशहाली का नया दौर शुरू करें। इस नये दौर में हम जम्मू-कश्मीर के अवाम को पूरा हिस्सेदार बना सकते हैं और हम जरूर बनाएंगे।

ये ख्यालात आपके सामने रखते हुए मैं आप सबको आज इस मौके की मुबारकवाद देता हूं और ये उम्मीद रखूंगा कि ये छोटा सा कदम जम्मू-कश्मीर के लिए, सारे हिंदुस्तान के लिए और पाकिस्तान के साथ हमारी बढ़ती हुई दोस्ती के लिए एक नये दौर की शुरुआत होगा।

जिस खाक के ज़मीर में हो आतिशे चिनार
मुमकिन नहीं कि सर्द हो वो ख़ाके अरजुमंद।"

प्रो0 उमाकांत मिश्र, निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पटियाला हाऊस, नई दिल्ली–110 001 से प्रकाशित एवं मुद्रित तथा अरावली प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली–110 020 में मुद्रित। दूरभाष : 26388830–32
संपादक : विश्व नाथ त्रिपाठी

रजि.सं.एल. 12036 यू (डीएन) 53/2003–05 तथा डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक में डालने के लिए लाइसेंस–प्राप्त
Reg. No. D.L.12036 (DN) 53/2003-05 Licenced to post without pre-payment at RMS, Delhi.
पंजी सं. 951/57
R.N. 951/57

IAS/PCS

मणिकांत सिंह के निर्देशन में 'द स्टडी' सफलता के नये कीर्तिमानों की ओर सदैव अग्रसर .....

इतिहास

–मणिकांत सिंह

'इतिहास के अध्ययन का अर्थ महज तथ्यों का संकलन नहीं अपितु एक समग्र दृष्टिकोण का विकास है।'

पत्राचार पाठ्यक्रम उपलब्ध

अन्य विषय

सामान्य अध्ययन
– मणिकांत सिंह
कुमार सर्वेश एवं अन्य

हिन्दी साहित्य
– कुमार सर्वेश

- साक्षात्कार में दो बार शामिल (**U.P.S.C**)
- हिन्दी साहित्य में 347 अंक प्राप्त

संस्कृत साहित्य
– सदानन्द कुमार एवं कैलाश बिहारी

- एम. ए. स्वर्णपदक (भागलपुर विश्वविद्यालय)
- व्याकरण एवं साहित्याचार्य, यू. जी. सी. नेट, बेट.
- छः वर्षों का अध्यापन अनुभव (एस. एम. कॉलेज भागलपुर)

विशेष रणनीति

★ इतिहासलेखन के प्रकाश में प्रत्येक टॉपिक का विस्तृत विश्लेषण
★ प्रत्येक टॉपिक पर अध्ययन सामग्री
★ पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण
★ प्रश्नोत्तर पर विशेष कक्षाएँ
★ मानचित्र (इतिहास) वाले प्रश्न पर विशेष अभ्यास
★ आवधिक परीक्षा

अध्ययन कार्यक्रम

★ मुख्य परीक्षा
★ मुख्य परीक्षा तथा प्रारम्भिक परीक्षा समन्वित कार्यक्रम

कक्षाएँ 15 जून से आरम्भ

THE STUDY
(AN INSTITUTE FOR IAS)

210, Virat Bhawan, Near MTNL Office
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Ph. 27653672, 27652263